जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2023 (संयुक्तांक), वर्ष 32, अंक 49, 50, 51

उत्तर प्रदेश संदेश

आज़ादी का अमृत महोत्सव

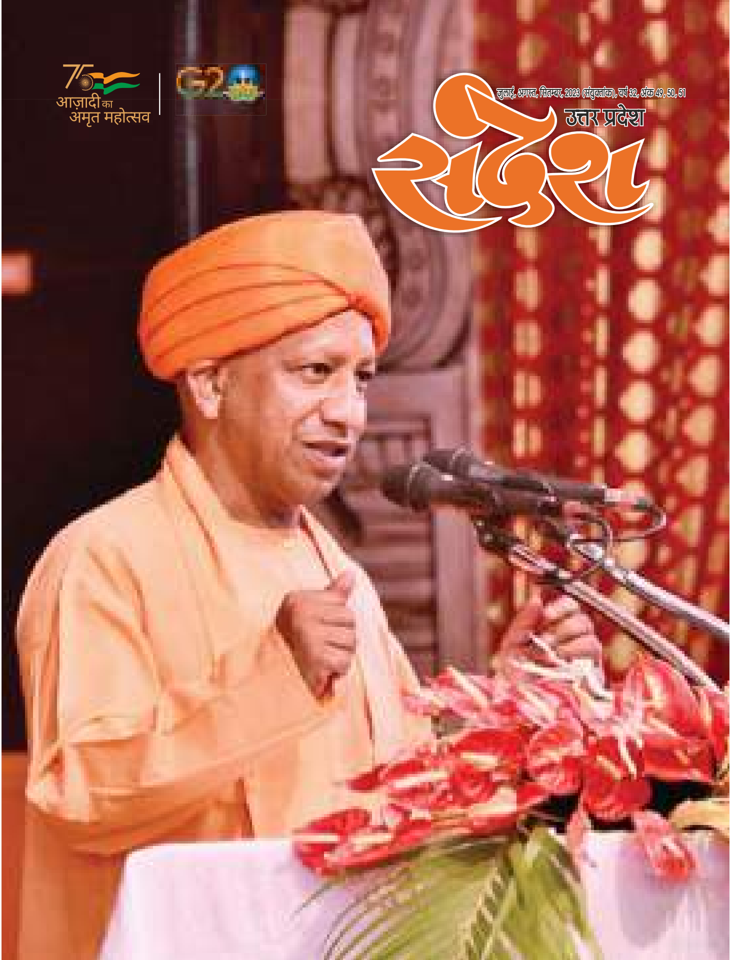

सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाएं
आकर्षक अनुदान एवं
बिल में राहत पाएं
www.solarrooftop.gov.in

जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2023 तक (संयुक्तांक), वर्ष 32, अंक 49, 50, 51

उत्तर प्रदेश संदेश

संरक्षक एवं मार्गदर्शक :
संजय प्रसाद
प्रमुख सचिव, सूचना

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी :
शिशिर
सूचना निदेशक

सम्पादकीय परामर्श :
अंशुमान राम त्रिपाठी
अपर निदेशक, सूचना

डॉ. मधु ताम्बे
उपनिदेशक सूचना

डॉ. जितेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक निदेशक, सूचना

अतिथि सम्पादक :
कुमकुम शर्मा

सम्पादकीय सहयोग :
दिनेश कुमार गुप्ता
उपसम्पादक, सूचना

सम्पादकीय संपर्क : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पं. दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर, पार्क रोड, लखनऊ
ईमेल : upsandesh20@gmail.com
दूरभाष कार्यालय : ई.पी.ए.बी.एक्स 0522–2239132–33, 2236198, 2239011

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित

भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की रजिस्ट्री संख्या : 55884/91

प्रकाशित सामग्री में विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण एवं विचार से सूचना विभाग की सहमति अनिवार्य नहीं हैं। लेखों में प्रयुक्त आंकड़े अनन्तिम हो सकते हैं।

इस अंक में

सच्चे किसान विज्ञानी थे एमएस स्वामीनाथन	- नरेन्द्र मोदी	3
अमृतकाल के सारथी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी	- योगी आदित्यनाथ	5
देश की मिट्‌टी से जुड़ने का अभियान	- जी. किशन रेड्डी	9
सुशासन का पर्याय एक अटल व्यक्तित्व	- के.पी. तिवारी	12
पर्यावरण और प्रकृति का करना होगा संरक्षण	- प्रद्युम्न तिवारी	14
शहर से लेकर गांव तक रोशन	- अनिल श्रीवास्तव	17
शिक्षा का बदलता परिवेश आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश	- अंजु अग्निहोत्री	20
पंच प्रण को साकार करती उत्तर प्रदेश की धरती	- प्रदीप कुमार गुप्ता	24
समाज को जोड़ने का अनूठा मूलमंत्र	- यशोदा श्रीवास्तव	30
जी-20 शिखर सम्मेलन और उत्तर प्रदेश	- सियाराम पांडेय 'शांत'	33
पर्यटकों को आकर्षित करता है उत्तर प्रदेश	- डॉ. सौरभ मालवीय	36
एक जिला एक उत्पाद से अन्त्योदय तक	- अशोक सिन्हा	39
निवेश से बदलता परिवेश	- सुयष मिश्रा	42
पंचायती राज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका	- डॉ. नन्द किशोर साह	46
आकांक्षी नगर योजना से शहरों का बदलता रूपरंग	- सुरेन्द्र अग्निहोत्री	50
निडर हुई महिलाएँ महिला अपराधों से संबंधित...	- अखिलेश कुमार सिंह	53
श्रीअन्न से समृद्धि की ओर	- मीनाक्षी लोहानी	57
पिछड़ों और दिव्यांगजनों के साथ खड़ी सरकार	- प्रिया श्रीवास्तव	62
बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन...	- विदर्भ कुमार	64
चंदन से महक रहा प्रदेश	- केवल राम	67
सजग युवा, सशक्त प्रदेश	- उपेन्द्र कुमार	69
वन्यजीवों के संरक्षण से मिली नई दिशा	- के.एल. चौधरी	71
ऊर्जा के बढ़ते कदम	- के.एल. चौधरी	73

सम्पादकीय

जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह प्रदेश एक समय में विकास की गति में पिछड़-सा गया था पर 2017 के बाद से यही प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक कुशल प्रयासों से उत्तम प्रदेश बनने की राह पर बहुत मजबूती से चल पड़ा है, जिसके सुखद परिणाम आज हम सभी के सामने हैं। योगी जी ने अपनी जनकल्याणकारी नीतियों अपनी पारदर्शी कार्यप्रणाली से उत्तर प्रदेश की जैसे काया ही पलट दी है। जो बातें कल तक असम्भव लगती थीं वे आज रोजमर्रा की बातें हो गई हैं, कम संसाधनों के बावजूद उत्तर प्रदेश निवेशकों का पंसदीदा गंतव्य बन गया है। अराजकता और माफिया राज एक गुज़रे ज़माने की बातें हो गई हैं। मुख्यमंत्री के कठोर अनुशासन के चलते अब प्रदेश में सुरक्षित माहौल है। देश और दुनिया के पटल पर प्रदेश अपनी बदलती तस्वीर के साथ अपनी नई पहचान बना रहा है। निवेश, उत्पादन, निर्यात में बढ़ोत्तरी व बेहतर होते कारोबार अब प्रदेश की नई पहचान हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश को खुशहाल और विकसित प्रदेश बनाने का श्रेय मुख्यमंत्री जी को ही दिया है। उन्होंने योगी जी की तारीफ करते हुये कहा था कि उत्तर प्रदेश विकास के हर क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है। उन्होंने योगी जी की प्रशंसा करते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश देश के लिए ग्रोथ इंजन की भूमिका अदा करने में मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व से सक्षम हुआ है। उन्होंने कहा कि, ''आज यू.पी. निराशा की पुरानी छवि से बाहर आ गया है जैसे-जैसे सुरक्षा मजबूत होगी और सुविधाएं बढ़ेंगी वैसे-वैसे समृद्धि आना तय है।'' प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री की सबसे लम्बे समय तक राज्य की सेवा करने वाले एकमात्र सी.एम. बनने का रिकार्ड बनाने के लिए भी प्रशंसा की है।

अपने साढ़े 6 साल के कार्यकाल में योगी जी ने माफियाओं के अंत, अपराध व अवराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। राज्य में पिछले पांच वर्षों में चार मुख्य बिन्दुओं पर कार्य किया गया है।

सम्पादक

सच्चे किसान विज्ञानी थे एमएस स्वामीनाथन

–नरेन्द्र मोदी

प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन अब हमारे बीच नहीं हैं। देश ने एक ऐसे दूरदर्शी एवं महान व्यक्ति को खोया है, जिन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और जिनका भारत के लिए योगदान हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। स्वामीनाथन भारत से प्रेम करते थे और चाहते थे कि हमारे किसान समृद्धि के साथ जीवन यापन करें। यह अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली थे और किसी भी करियर का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन 1943 के बंगाल के अकाल से वे इतने द्रवित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि अगर कोई एक चीज, जिसे वे करना चाहेंगे, तो वह है कृषि–क्षेत्र का कायाकल्प।

बहुत छोटी उम्र में वह डॉ. नार्मन बोरलाग के संपर्क में आए और उनके काम को गहराई से समझा। पिछली सदी के छठे दशक में अमेरिका ने उन्हें एक फैकल्टी के तौर पर जुड़ने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह देश के लिए काम करना चाहते थे। आज हम सभी को दशकों पहले की उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बारे में विचार करना चाहिए, जिनका स्वामीनाथन ने डटकर सामना किया और देश को आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के मार्ग पर ले गए। आजादी के बाद पहले दो दशकों में हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे थे और उनमें से एक थी– खाद्यान्न की कमी। पिछली सदी के सातवें दशक की शुरुआत में भारत अकाल से जूझ रहा था। इसी दौरान स्वामीनाथन की प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता ने कृषि क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। उनके कार्यों से गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर वाले राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया। इस शानदार उपलब्धि की वजह से उन्हें 'हरित क्रांति के जनक' की उपाधि मिली, जो बिल्कुल सही है। हरित क्रांति में भारत की 'हम कर सकते हैं' वाली भावना झलकती है।

यदि हमारे सामने करोड़ों चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इनोवेशन की लौ जलाने वाले करोड़ों प्रतिभाशाली लोग भी हैं। हरित क्रांति शुरू होने के पांच दशक बाद भारतीय कृषि आधुनिक और प्रगतिशील हो गई है, लेकिन स्वामीनाथन द्वारा रखी गई नींव को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आलू की फसल को प्रभावित करने वाले कीटों से निपटने की दिशा में भी प्रभावी अनुसंधान किया। उनके शोध ने आलू की फसल को ठंड के मौसम का सामना करने में सक्षम बनाया। आज दुनिया सुपर फूड के रूप में मिलेट्स या श्रीअन्न के बारे में

बात कर रही है, लेकिन स्वामीनाथन ने 1990 से ही मिलेट्स के बारे में चर्चा को प्रोत्साहित किया था।

प्रो. स्वामीनाथन के साथ मेरी बातचीत का दायरा बहुत व्यापक था। इसकी शुरुआत 2001 में मेरे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद हुई। तब गुजरात आज की तरह अपने कृषि सामर्थ्य के लिए नहीं जाना जाता था। निरंतर सूखे, तबाही लाने वाले चक्रवात और भूकंप ने राज्य की विकास यात्रा को बुरी तरह प्रभावित किया था। उसी दौर में हमने स्वाइल हेल्थ कार्ड की पहल की। हमारी कोशिश थी कि किसानों को मिट्टी को बेहतर ढंग से समझने और समस्या आने पर उसके समाधान में मदद मिले। इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात स्वामीनाथन से हुई। उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिए। उनका समर्थन उन लोगों को समझाने के लिए पर्याप्त था, जो हमारी योजना को लेकर संशय में थे। अंततः हमारी योजना ने गुजरात में कृषि क्षेत्र की सफलता का सूत्रपात कर दिया। मुख्यमंत्री रहने के दौरान और उसके बाद जब मैंने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब भी हमारी बातचीत चलती रही। मैं उनसे 2016 में इंटरनेशनल एग्रो–बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस में मिला और अगले वर्ष मैंने उनके द्वारा लिखित पुस्तक श्रृंखला लांच की।

'कुरल' ग्रंथ के मुताबिक किसान वह धुरी है, जिसके चारों तरफ पूरी दुनिया घूमती है। ये किसान ही हैं, जो सब का भरण–पोषण करते हैं। स्वामीनाथन इसे अच्छी तरह समझते थे। अधिकांश लोग उन्हें 'कृषि विज्ञानी' कहते हैं, मगर उनके व्यक्तित्व का विस्तार इससे कहीं ज्यादा था। वह एक सच्चे 'किसान विज्ञानी' थे। उनके दिल में किसान बसता था। उनके कार्यों की सफलता उनकी अकादमिक उत्कृष्टता तक ही सीमित नहीं। वह खेतों और मैदानों में स्पष्ट रूप से दिखती है। उनके कार्य ने साइंटिफिक ज्ञान और उसके व्यावहारिक उपयोग के बीच के अंतर को कम किया। उन्होंने ह्यूमन एडवांसमेंट और इकोलाजिकल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन पर जोर देते हुए हमेशा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वकालत की। उन्होंने छोटे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उन तक इनोवेशन का लाभ पहुंचाने पर बहुत जोर दिया। वह विशेष रूप से महिला किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति समर्पित थे।

प्रो. स्वामीनाथन इनोवेशन और मेंटोरशिप को भी बहुत बढ़ावा देते थे। जब उन्हें 1987 में पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला, तो उन्होंने पुरस्कार राशि का उपयोग एक गैर–लाभकारी रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना में किया। आज भी यह फाउंडेशन विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक कार्य कर रहा है। उन्होंने अनगिनत प्रतिभाओं को निखारा और उनमें इनोवेशन के प्रति जुनून पैदा किया। उनका जीवन हमें ज्ञान, मार्गदर्शन और इनोवेशन की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। वह एक संस्थान निर्माता भी थे। उन्हें कई ऐसे केंद्रों की स्थापना का श्रेय जाता है, जहां आज वाइब्रेंट रिसर्च हो रही है। उन्होंने कुछ समय तक मनीला स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी अहम जिम्मेदारी निभाई। दक्षिण एशिया में इस संस्थान का रीजनल सेंटर 2018 में वाराणसी में खोला गया।

मैं प्रो. स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि देने के लिए फिर से 'कुरल' ग्रंथ को उद्धृत करूंगा। उसमें लिखा है, 'यदि योजना बनाने वालों में दृढ़ता हो, तो वे वही परिणाम हासिल करेंगे, जो वे चाहते हैं।' स्वामीनाथन ने इस संकल्प को बेहद रचनात्मक तरीके से और जुनून के साथ निभाया कि वह कृषि को मजबूत करेंगे और किसानों की सेवा करेंगे। जैसे–जैसे हम एग्रीकल्चरल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे, स्वामीनाथन का योगदान हमें प्रेरित करता रहेगा। हमें उन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते रहना होगा, जो उन्हें बेहद प्रिय थे। इन सिद्धांतों में किसानों के हितों की वकालत करना, साइंटिफिक इनोवेशन के लाभ को कृषि विस्तार की जड़ों तक पहुंचाना आर आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, स्थिरता एवं समृद्धि को बढ़ावा देना शामिल है। मैं एक बार फिर प्रो. स्वामीनाथन को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। ◆

(07 अक्टूबर, 2023 दैनिक जागरण से साभार)

अमृतकाल के सारथी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

–योगी आदित्यनाथ

यह कितना सुंदर संयोग है कि सृष्टि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती और एक भारत–श्रेष्ठ भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन एक ही दिवस पर है। दोनों ही सृजन के प्रणेता हैं, दोनों ही नवनिर्माण के संवाहक हैं। एक महान नेता वह होता है, जो बड़े लक्ष्य के लिए न केवल स्वयं को समर्पित करता है, बल्कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संस्थाएं और व्यवस्थाएं भी तैयार करता है। बीते साढ़े नौ वर्षों में हमने इसका साकार रूप प्रधानमंत्री मोदी में प्रत्यक्ष अनुभव किया है। 2014 के पूर्व भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और परिवारवाद की घुन से खोखली हो चुकी व्यवस्था के प्रति देश के सामान्य नागरिक के मन में वितृष्णा का भाव था तो भविष्य की अनिश्चितता को लेकर आशंका घर कर चुकी थी। सरकारी योजनाओं के केंद्र में 'अपनों का लाभ' निहित था, तो विश्व परिदृश्य पर भारत की साख पतनोन्मुख थी। जब संविधान में जोड़ा गया 'समाजवाद' शब्द यथार्थ में परिवारवाद बन कर रह गया और 'गरीबी हटाओ' का नारा गरीब को मिटाओ में परिवर्तित हो गया, तब निराशा के ऐसे गहरे सागर में डूबते–उतराते भारतीय लोक ने अंततः तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन का निर्णय लिया और अपनी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के रथ के सारथी 'प्रधानमंत्री' के रूप में नरेन्द्र मोदी का चुनाव किया।

2014 में नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण यज्ञ का शुभारंभ था। कभी विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित रहा भारत लंबी अवधि से ऐसे राष्ट्र यज्ञ की प्रतीक्षा में था। यह मोदी जी के नेतृत्व की विशिष्टता है कि उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को इस यज्ञ का साधक बनाया। हर भारतीय को देश की डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की त्रिवेणी के महत्व को समझाया। भारत को उसकी क्षमता से परिचित कराया। राष्ट्र जागरण के इस यज्ञ के सुफल के रूप में ही 'नए भारत' की रचना संभव हुई। यह मोदी जी के नेतृत्व का ही चमत्कार है कि विभिन्न धर्म, संप्रदाय, मत, भाषा, विचार में बंटा देश, आज एकता के सूत्र में बंधकर 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' के स्वप्न को साकार कर रहा है। आज मां भारती का मुकुट कश्मीर अनुच्छेद 370 के कलंक को धो चुका है। मुस्लिम बहनें तीन तलाक जैसी मध्ययुगीन वीभत्सता से मुक्त हैं। अब किसी माता–बहन का जीवन रसोईघर के धुएं की धुंध में होम नहीं होता। उनके जीवन में

''उज्ज्वला'' है, ''सौभाग्य'' का उजियारा है। हर किसान की हर फसल का बीमा है। हर गरीब को ''आयुष्मान'' का आशीष है और अपना घर होने का आत्मिक सुख है। विश्वस्तरीय सड़कों ने आम आदमी से लेकर उद्योग जगत तक के जीवन को सरल–सुगम बनाया है। यह सब प्रधानमंत्री की राष्ट्र साधना का ही प्रतिफल है।

2014 के बाद इस देश ने एक नई कार्य संस्कृति को अपनाया। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' इस नवीन कार्यसंस्कृति का प्राण है। 'अंत्योदय से सर्वोदय' का मंत्र आत्मसात करने वाली इस व्यवस्था में समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है। पहली बार कृषि और किसान राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। युवाओं की आकांक्षाएं हौसले के पंख से उड़ान भर रही हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र आराधना में रत है। आमजन में शासन के प्रति एक विश्वास है। संभवतः गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी ही व्यवस्था के लिए 'रामराज्य' की संज्ञा दी है।

यह साधारण नहीं कि प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रीय पर्व पर देशवासियों से स्वच्छता पर बातें करें। सामान्यतः स्वच्छता जैसे विषय कभी नेतृत्व के विमर्श के विषय नहीं बनते थे, लेकिन यह उनके नेतृत्व की दूरदर्शिता है कि आज स्वच्छता भारत में जनान्दोलन का स्वरूप ले चुका है। वंशवादी राजनीति के रूप में राजतंत्र की छाया में 70 वर्ष बिताने वाले देश में यह कल्पनातीत था कि कभी प्रधानमंत्री सफाईकर्मियों का चरण प्रक्षालन करें। कोरोना काल में अपने नेता के प्रत्येक आह्वान पर पूरा देश अनुशासित रहा। यह तभी संभव होता है, जब सामान्य नागरिक को नेतृत्व की नीति और नीयत पर अटूट विश्वास होता है। स्वातंत्रयोत्तर भारत में यह पूंजी अर्जित करने वाले मोदी जी एकमात्र नेता हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों के लिए 'मेरे परिवारजन' का संबोधन हर भारतीय के मन में अपनत्व का भाव भर देता है।

यह साधारण नहीं कि प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रीय पर्व पर देशवासियों से स्वच्छता पर बातें करें। सामान्यतः स्वच्छता जैसे विषय कभी नेतृत्व के विमर्श के विषय नहीं बनते थे, लेकिन यह उनके नेतृत्व की दूरदर्शिता है कि आज स्वच्छता भारत में जनान्दोलन का स्वरूप ले चुका है। वंशवादी राजनीति के रूप में राजतंत्र की छाया में 70 वर्ष बिताने वाले देश में यह कल्पनातीत था कि कभी प्रधानमंत्री सफाईकर्मियों का चरण प्रक्षालन करें। कोरोना काल

में अपने नेता के प्रत्येक आह्वान पर पूरा देश अनुशासित रहा। यह तभी संभव होता है, जब सामान्य नागरिक को नेतृत्व की नीति और नीयत पर अटूट विश्वास होता है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में यह पूंजी अर्जित करने वाले मोदी जी एकमात्र नेता हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों के लिए 'मेरे परिवारजन' का संबोधन हर भारतीय के मन में अपनत्व का भाव भर देता है। आस्था और अर्थव्यवस्था के प्रति समदर्शी भाव रखने वाले प्रधानमंत्री की अवधारणा विकास और विरासत को साथ–साथ लेकर चलने की रही है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत अवधपुरी में श्रीरामजन्मभूमि मंदिर लोकार्पित होने को तैयार है। पूरी दुनिया टकटकी लगाए अयोध्या को निहार रही है। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम पुनरोद्धार, उज्जयिनी में महाकाल का महालोक जैसे बहुप्रतीक्षित कार्यों ने सदियों से आहत आस्था को पुनः प्रफुल्लित होने का अवसर दिया है। हाल में नवीन संसद भवन का भी उद्घाटन हुआ। भारतीयता की सुगंध से सुवासित लोकतंत्र का यह मंदिर हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थांपना, लोक–कल्याण की भावना और सनातन की सात्विक मर्यादाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

> **विगत साढ़े नौ वर्षों में न केवल हम भारतीय वरन समूचा विश्व एक 'नए भारत' के निर्माण का प्रत्यक्षदर्शी रहा है। मंगल, चंद्रमा और सूर्य पर 'भारत उदय' को पूरा विश्व बड़ी आतुरता के साथ निहार रहा है। यह नया भारत है जिसकी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को अपनाने में विश्व का हर देश स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है, तो यह अपनी आस्था, अस्मिता और अर्थव्यवस्था के प्रति सजग और संवेदनशील भी है।**

विगत साढ़े नौ वर्षों में न केवल हम भारतीय वरन् समूचा विश्व एक 'नए भारत' के निर्माण का प्रत्यक्षदर्शी रहा है। मंगल, चंद्रमा और सूर्य पर 'भारत उदय' को पूरा विश्व बड़ी आतुरता के साथ निहार रहा है। यह नया भारत है जिसकी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को अपनाने में विश्व का हर देश स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है, तो यह अपनी आस्था, अस्मिता और अर्थव्यवस्था के प्रति सजग और संवेदनशील भी है। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को सूक्ष्मता से देखें तो उसमें व्यवहारिकता और आदर्शवादिता, दोनों ही गुणों का सुंदर समन्वय, परिलक्षित होता है। उनमें एक स्टेट्समैन है तो किसी अबोध बालक–सी निर्मलता भी। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानसेवक बनने तक का लगभग सवा दो दशकों की उनकी

यात्रा का पग–पग चुनौतियों और संघर्षों से भरा रहा है। यह उनका विलक्षण व्यक्तित्व ही है कि काल के कपाल पर लिखते–मिटाते, हर बाधा को पार करते हुए अपने संकल्पों की सिद्धि हेतु सतत चलायमान हैं।

कोरोना के बाद एक नया भू–राजनीतिक समीकरण तेजी से आगे बढ़ा है। वैदेशिक संबंधों की पुरानी परिभाषाएं बदल रही हैं। ऐसे अवसर पर भारत दुनिया के लिए मार्गदर्शक बन कर उभरा है। आज दुनिया में कहीं भी कोई मानवीय संकट हो, हर देश भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है। हाल में संपन्न जी–20 की सफलता ने भारत को नई विश्व व्यवस्था के केंद्र में ला खड़ा किया है। आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। अफ्रीकी संघ को जी–20 की सदस्यता दिलाना, भारत–मिडिल ईस्ट–यूरोप इकोनामिक कॉरिडोर का निर्माण और सर्व सहमति से नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी करने का सफल प्रयास वैश्विक पटल पर 'ब्रांड भारत' को और विश्वसनीय बनाने वाला सिद्ध हुआ है। भारत की सेना आज सर्वकालिक दक्ष, साधन संपन्न, स्वतंत्र और आत्मविश्वास से भरी है। प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के साथ ही भारत की विदेश नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन को दुनिया ने देखा और सराहा है। 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प के साथ भारत ने वैदेशिक संबंधों में बहुपक्षीय नीति को अपनाया है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हो, चीन की अराजक गतिविधियों का यथोचित प्रत्युत्तर हो या यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोप और अमेरिका को सीधा जवाब हो, भारत ने स्पष्ट शब्दों में दृढ़ता से अपना पक्ष रखा। यह मोदी जी के नेतृत्व का कौशल ही है कि आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में आज पूरा भारत आजादी के अमृतकाल के महान संकल्पों से जुड़ चुका है। लाल किले की प्राचीर से उद्घोषित 'पंच प्रण' इन संकल्पों की आत्मा है, जिसकी पूर्ति में पूरा देश समवेत स्वर और एकनिष्ठ भाव के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत' का स्वप्न अब यथार्थ होने की ओर अग्रसर है। ◆

(साभार : दैनिक जागरण, 17 सितम्बर, 2023)

देश की मिट्टी से जुड़ने का अभियान

–जी. किशन रेड्डी

किसी भी सच्चे नागरिक के लिए उसके देश की मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इतिहास गवाह है हमारे वीर जवानों ने 'खून भी देंगे जान भी देंगे– देश की माटी कभी नहीं देंगे' के भाव को आत्मसात करते हुए वतन की मिट्टी की ख़ातिर लाखों बलिदान दिए और दुश्मनों को मौत के घाट भी उतारा। मिट्टी से ही जीवन है और मिट्टी में ही जीवन का अंत, मिट्टी पवित्रता की पराकाष्ठा भी है और संकल्पों की शक्ति भी है। अथर्ववेद में कहा गया है कि 'माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः' अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। स्वामी विवेकानंद 15 जनवरी, 1897 को अपनी चार वर्ष की विदेश यात्रा के उपरांत जब भारत लौटे और देश की ज़मीन पर अपना पहला कदम रखा तो अपने मन के आवेग को रोग नहीं पाए। स्वदेश की मिट्टी में लोट–पोट होने लगे। भाव–विभोर होकर रोते हुए कहने लगे कि 'विदेश में प्रवास के कारण मुझमें यदि कोई दोष आ गए हों तो हे धरती माता, मुझे क्षमा कर देना।' यह घटना भारत की मिट्टी की पवित्रता को दर्शाती है।

भारत की मिट्टी की संकल्प शक्ति का साक्षी जलियांवाला बाग भी है। 13 अप्रैल, 1919 को वहां जनरल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषणों में एक संकल्प अक्सर सुना है– 'सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मेरा वचन है भारत मां को, मैं शीश नहीं झुकने दूंगा।' उसी संकल्प की शक्ति है कि आज दुनिया में भारत की जय–जयकार हो रही है। अब विकसित भारत के लिए करोड़ों भारतीयों को मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के उस मंत्र को चरितार्थ करने का समय है, जिसमें उन्होंने कहा कि 'यही समय है– सही समय है।' हाल में जी–20 शिखर सम्मेलन में दुनिया ने भारत की उभरती शक्ति को देखा है जिससे हर भारतवासी का आत्मविश्वास बढ़ा है। विकसित भारत के सपने को साकार करने में 'मेरी माटी–मेरा देश' अभियान से निर्मित होने वाली अमृत वाटिका आने वाले 25 वर्षों में यानि अमृतकाल के पंच प्रणों की पूर्ति तो करेगी ही, साथ में हमारे बलिदानियों के सपनों को साकार करने के लिए देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित भी करेगी।

डायर ने हजारों भारतीयों की निर्मम हत्या करा दी। तब वहां की उसी मिट्‌टी को हाथ में लेकर उधम सिंह ने जनरल डायर को सबक सिखाने का संकल्प लिया। उधम सिंह ने उस मिट्‌टी की लगभग 21 वर्षों तक प्रतिदिन पूजा की। अंततः 13 मार्च, 1940 को जनरल डायर को मार कर हजारों निर्दोष भारतीयों की हत्या का बदला लिया। इसी प्रकार हल्दी घाटी में हल्दिया रंग की मिट्‌टी शौर्य, साहस, संघर्ष, प्रेरणा और विजय की प्रतीक है। लोग आज भी इस मिट्‌टी को अपने माथे पर लगा कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। खमनोर की रक्त तलाई में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना में निर्णायक युद्ध हुआ था। तब हजारों सैनिकों का खून बहने से यहां की मिट्‌टी का रंग लाल हो गया था। रक्त तलाई की मिट्‌टी को देखकर आज भी देशवासियों के मन में इसके प्रति श्रद्धा, विश्वास और राष्ट्रभक्ति के भाव जीवंत हो जाते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि भारत के ऐसे सभी ऐतिहासिक स्थलों सहित हर घर की पवित्र मिट्‌टी का पूजन कर 'आजादी के अमृत महोत्सव' का समापन कार्यक्रम 'मेरी माटी–मेरा देश' के रूप में मनाया जाए। बीते माह एक सितंबर से इस अभियान की शुरुआत हुई है। भारत के प्रत्येक गांव के लगभग 30 करोड़ परिवारों से अमृत कलश में मिट्‌टी या चावल का संग्रह किया गया है। अमृत कलश में मिट्‌टी या चावल एकत्र करने के दौरान समूह के साथ ढोलक, नगाड़ा और अन्य वाद्य यंत्र बजाते हुए लोग शामिल हुए। मिट्‌टी और चावल संग्रह के समय अमृतकाल के पंच प्रण की प्रतिज्ञा भी ली गई। इन अमृत कलशों को दिल्ली भेजने से पहले हर राज्य की राजधानी में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सांसदों की उपस्थिति में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तत्पश्चात नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए देश भर से इन अमृत कलशों को लाने वाले स्वयंसेवकों के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था हुई। साथ ही जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इन ट्रेनों का देश के मुख्य रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय रीति–रिवाज से स्वागत हुआ। इन अमृत कलशों की ऐतिहासिक मिट्‌टी का उपयोग

हमारे महान बलिदानियों के सम्मान में नेशनल वार मेमोरियल के पास अमृत वाटिका बनाने में किया जाएगा। 'मेरी माटी—मेरा देश' अभियान का समापन 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में 7,297 ब्लाकों और 500 से अधिक नगर पालिकाओं और नगर निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 75 हजार लोगों के साथ संपन्न होगा।

'आजादी के अमृत महोत्सव' के दौरान विगत वर्ष देश ने जिस प्रकार से 'हर घर तिरंगा' अभियान की सफलता को देखा, वह निश्चित ही अभूतपूर्व था। इतना ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले भारतीयों ने अपने परिवार के साथ विदेशी धरती पर भी तिरंगा झंडा फहराया था। वह दृश्य मन को खुशी, उल्लास और गर्व से भर देने वाला था। कह सकते हैं कि आजादी के बाद यह पहला ऐसा ऐतिहासिक 'स्वतंत्रता दिवस' था, जिसमें सारा देश शामिल हुआ था। देश के असंख्य शिक्षण संस्थानों, ग्राम, पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों, विभिन्न विभागों, कंपनियों, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक पार्टियों और केंद्र एवं राज्य सरकारों ने जिस प्रकार से 'आजादी के अमृत महोत्सव' को अभियान के रूप में लेकर सफल बनाया है, उससे विश्व ने भारत की सामर्थ्य शक्ति, एकता और एकजुटता को देखा है। इसलिए यह समय 142 करोड़ भारतीयों का अभिनंदन करने का भी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषणों में एक संकल्प अक्सर सुना है– 'सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मेरा वचन है भारत मां को, मैं शीश नहीं झुकने दूंगा।' उसी संकल्प की शक्ति है कि आज दुनिया में भारत की जय–जयकार हो रही है। अब विकसित भारत के लिए करोड़ों भारतीयों को मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के उस मंत्र को चरितार्थ करने का समय है, जिसमें उन्होंने कहा कि 'यही समय है– सही समय है।' हाल में जी–20 शिखर सम्मेलन में दुनिया ने भारत की उभरती शक्ति को देखा है जिससे हर भारतवासी का आत्मविश्वास बढ़ा है। विकसित भारत के सपने को साकार करने में 'मेरी माटी–मेरा देश' अभियान से निर्मित होने वाली अमृत वाटिका आने वाले 25 वर्षों में यानी अमृतकाल के पंच प्रणों की पूर्ति तो करेगी ही, साथ में हमारे बलिदानियों के सपनों को साकार करने के लिए देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित भी करेगी। ◆

(लेखक केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री है।

(साभार : दैनिक जागरण 30 अक्टूबर, 2023)

पुण्यतिथि पर विशेष

सुशासन का पर्याय एक अटल व्यक्तित्व

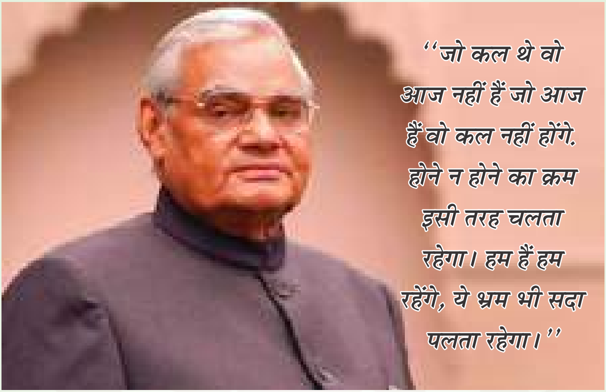

—के.पी. तिवारी

जननायक अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन लेखनी और वाणी के धनी अटल जी के कर्तत्व आज भी जीवंत हैं। भारतीय संस्कारों से अनुप्राणित अटल जी थे तो राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन उनकी मूल चेतना साहित्यिक थी। अटल की सर्व स्वीकार्यता के सभी कायल थे। सुशासन के वह पर्याय थे। मनुष्यता उनकी पहली पहचान थी। यही वह गुण था, जिससे अटल सत्ता के शीर्ष पर तो पहुंचे ही, उन्होंने दलीय मतभेदों से उठकर हर नेता के साथ आत्मीयता का रिश्ता भी कायम किया। अटल ही में वह कला थी कि उन्होंने तीव्र वैचारिक मतभेद वाले राजनीतिक दलों के नेताओं में मतैक्य स्थापित कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को खड़ा कर दिया था। यह उन्हीं की मेहनत और तपस्या का फल है कि आज एनडीए देश पर राज कर रहा है।

प्रधानमंत्री रहते हुए अटल जी ने कई ऐसे अनूठे कार्य किये जो देश के विकास में सुनहरा अध्याय लिखने में सफल रहे हैं। अटल की नदी जोड़ो परिकल्पना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं।

अटल की सहजता में भी जो भाव था, वह लोगों को सहसा अपनी ओर आकर्षित करता था। जीवन भर की राजनीति में कभी किसी ने उनके मुख से धुर विरोधियों के लिए भी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं सुना। अटल की वाणी, वाकपटुता और हास्य प्रधान शैली का कोई सानी नहीं था। बात लखनऊ के बेगम हज़रत महल पार्क की है। अटल जनसभा में बोल रहे थे। सभा में उन्होंने राजनीतिक छुआछूत के पुरोधाओं पर चुटकी लेते हुए कहा था– "आपने एक कहावत सुनी होगी, आठ कनौजिया, नौ चूल्हे। नवां चूल्हा इसलिए कि उससे आग लेकर बाकी अपने अलग–अलग आठ चूल्हे जलाते थे।" यह भी जोड़ा कि मैं भी कनौजिया

ब्राह्मण हूं। इस पर सभा में जोरदार ठहाका लगा।

अटल जी की 'परिचय' नामक कविता बहुत चर्चित हुई थी। उसकी पंक्तियां थीं–'पय पीकर सब मरते आये, लो अमर हुआ मैं विष पीकर'। इन्हीं पंक्तियों में छिपा है अटल का जीवन दर्शन। अपने राजनीतिक जीवन में पता नहीं उन्हें कितनी बार गरल पीना पड़ा लेकिन हंसते–हंसते उन्होंने समस्याओं को ऐसा सुलझाया कि विरोधी भी उनके हुनर को दाद देने से नहीं चूके। अटल ने 'सोद्देश्य पत्रकारिता' को कभी ओझल नहीं होने दिया। छह दशक पूर्व लखनऊ के लोगों ने राजनीति की रपटीली राहों पर निकले जिस पथिक को पहचानने से इंकार कर दिया था, बाद के दौर में उसे ही सिर आंखों पर बिठाकर पांच बार संसद तक भेजा। प्रदेश और पूरे मुल्क के लोगों के दिलों के बादशाह अटल बिहारी वाजपेयी ने सबको साथ लेकर जिस तरह से किसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में पूरे पांच साल सरकार चलायी और देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीन बार संसद की शोभा बढ़ायी, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती।

अटल जी पर दीनदयाल उपाध्याय और संघ का बेहद प्रभाव था। संघ के बड़े पदाधिकारी रहे भाउराव देवरस का जब निधन हुआ तो दिल्ली में मीडिया ने अटल की प्रतिक्रिया जाननी चाही। तब अटल जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि देवरस ना होते तो दीनदयाल उपाध्याय ना होते और दीनदयाल जी न होते तो मैं न होता। ये थे अटल। पुण्य तिथि पर विनम्र नमन।

कानपुर में पढ़ाई के ठीक बाद अटल ने साहित्य को ही कर्मक्षेत्र चुना था। जून 1947 में वह लखनऊ आ गये थे। यहां उन्हें पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने मासिक पत्रिका 'राष्ट्रधर्म' के संपादक का दायित्व सौंप दिया। यह वह समय था, जब देश में राजनीतिक उथल–पुथल मची थी। साहित्य पिछड़ गया था। 'माधुरी' सरीखी पत्रिका, जिसके सम्पादक साहित्य मनीषी पंडित रूप नारायण पांडे थे, अंतिम घड़ियां गिन रही थी। ऐसे समय में अटल के सम्पादन में 31 अगस्त 1947 को निकली राष्ट्रधर्म पत्रिका। अटल के सम्पादन में राष्ट्रधर्म पत्रिका हर ओर चर्चित हो गयी। अटल जी की लगन और प्रतिभा एक दूसरे की पूरक थीं। यही कारण था कि राष्ट्रधर्म ने जल्दी ही प्रतिष्ठिा पा ली। पर अटल जी तो दूसरी ही माटी के बने थे। वह अकेले ही सफलता का श्रेय लेने को तैयार नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि सफल अंक निकालने का चमत्कार उन्होंने सुख–साधन जुटाने के बाद किया हो। लखनऊ के 6, एपी सेन रोड के तीन–चार कमरे इस बात के गवाह हैं कि किन जटिल परिस्थितियों में वहां कार्य होता था। वहीं खाना, वहीं रहना और दरी पर बैठकर पत्रिका का संपादन करना। घंटों जी जान से जुटकर कार्य करते थे। यहां तक कि कई बार पत्रिका के बंडल बनाने तक का कार्य वह स्वयं करते थे। एक बार लगातार कार्य करते–करते वह बेहोश तक हो गये।

अटल जी पर दीनदयाल उपाध्याय और संघ का बेहद प्रभाव था। संघ के बड़े पदाधिकारी रहे भाउराव देवरस का जब निधन हुआ तो दिल्ली में मीडिया ने अटल की प्रतिक्रिया जाननी चाही। तब अटल जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि देवरस ना होते तो दीनदयाल उपाध्याय ना होते और दीनदयाल जी न होते तो मैं न होता। ये थे अटल। पुण्य तिथि पर विनम्र नमन। ◆

मो. : 9368724177

पर्यावरण और प्रकृति का करना होगा संरक्षण

–प्रद्युम्न तिवारी

"क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पंच रचित् अधि अधम शरीरा ।।" भारतीय दर्शन तथा योग में पृथ्वी (क्षिति), जल (अप), अग्नि (ताप), वायु (पवन) एवं गगन (शून्य) को पंचतत्व या पंचमहाभूत कहा जाता है। पंचतत्व को ब्रह्मांड में व्याप्त लौकिक एवं अलौकिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कारण और परिणति माना गया है। ब्रह्मांड में प्रकृति से उत्पन्न सभी वस्तुओं में पंचतत्व की अलग–अलग मात्रा में मौजूद है। अपने उद्‌भव के बाद सभी वस्तुएं नश्वरता को प्राप्त होकर इनमें ही विलीन हो जाती है। यहां तत्व के नाम का अर्थ उनके भौतिक रूप से नहीं है–यानि जल का अर्थ पानी से जुड़ी हर चीज, अग्नि का अर्थ आग से जुड़ी हर चीज शामिल होगी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पांच महाभूत माने जाते हैं। पंचभूतों में प्रत्येक का विशिष्ट गुण माना गया है। आकाश का विशिष्ट गुण शब्द, वायु का विशिष्ट गुण स्पर्श, अग्नि का विशिष्ट गुण रूप, जल का विशिष्ट गुण स्वाद और पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध होता है। इन्हीं पंचभूतों का संरक्षण और संवर्धन ही पर्यावरण संरक्षण कहा जाता है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। वन्य व प्रकृति प्रेमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मर्म को समझते हुए ही राज्य में वृक्षारोपण का वृहद अभियान चलाया। बीते छह साल के कार्यकाल में यानि 2017 के बाद से अब तक प्रदेश में 173 करोड़ पौधे लगाने का कार्य हुआ है। यही कारण है कि आज प्रदेश की जनता में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर सकारात्मक भाव पैदा हुआ है। इसे झुठलाया नहीं जा सकता कि विकास आज की आवश्यकता है लेकिन पर्यावरण और प्रकृति के प्रति भी हमारे कुछ दायित्व हैं, इसे भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रकृति का अति दोहन करके जिन दुष्परिणामों को आमंत्रित किया है, आज हम सब उसके भुक्तभोगी बन रहे हैं। यानि जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसी साल अतिवृष्टि के रूप में हम सबने इसके दुष्परिणामों को देखा है। उत्तराखण्ड और हिमाचल जैसे राज्यों में करोड़ों का नुकसान होने के साथ ही जनहानि भी हुई। वास्तव में हमारी संस्कृति नदियों, वृक्षों, वायु की पूजा करने की रही है। ऐसे में हमें यह सोचना होगा कि हम भावी पीढ़ी के लिए कैसा जीवन देंगे।

भारत की परंपरा सदैव से पर्यावरण हितैषी रही है और उत्तर प्रदेश में लगातार इस दिशा में कार्य हो रहे हैं। उप्र की योगी सरकार ने राज्य में आम नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण का भाव पैदा किया है। साथ ही सरकार 100 साल से पुराने वृक्षों को विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता देकर उनका संरक्षण कर रही है। प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार अपने स्तर पर गंभीर प्रयास कर रही है पर इसके साथ ही प्रदूषण के घातक दुष्परिणामों से बचने के लिए

हर व्यक्ति को पर्यावरण अनुकूल आचरण अनिवार्य रूप से करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि पर्यावरण पृथ्वी, जल, वायु, पेड़–पौध सबका समन्वित रूप है। हम सबकी रचना भी पंचतत्वों के इर्दगिर्द हुई है। हमारा जीवन चक्र व सृष्टि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन हमने सृष्टि के तत्वों जल, वायु को प्रदूषित किया। इसका ख़ामियाजा हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रूप में भुगतना पड़ रहा है। लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा इन बीमारियों के उपचार पर खर्च हो जा रहा है।

फेंके गए प्लास्टिक को गाय खाकर मर जाती हैं तो गोमाता की हत्या का पाप लगता है। कभी नष्ट न होने से यह प्लास्टिक धरती मां के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक से पर्यावरण के संरक्षण के लिए सिक्स आर का मंत्र भी दिया है। उन्होंने रिड्यूज, रियूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफैब्रिकेट और रिपेयर के फार्मूले को अपनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने पौधे लगाने के साथ उनकी रक्षा का दायित्व लेने की भी अपील कर रखी है। वन आच्छादित क्षेत्र में तापमान 5 से 6 डिग्री कम रहता है और भीषण गर्मी से राहत मिलती है। ज़ाहिर है कि इससे हम 'ग्लोबल वार्मिंग' के खतरे को भी कम कर सकते हैं।

भारतीय मनीषा के मंत्र इस बात के प्रमाण हैं कि हमारे पूर्वजों ने सृष्टि के प्रत्येक वस्तु के कल्याण की बात की है। कल्याण मतलब कोई भी वस्तु प्रदूषित न होने पाए। पहले हम यज्ञ करते थे, घर–घर हवन होता था। इन सबको तिलांजलि देकर हमनें ऐसी जीवन पद्धति अपना ली जो आज हमारे लिए ही घातक हो गई। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने का दुष्परिणाम प्रदेश के कुछ हिस्सों में सितंबर–अक्टूबर की असमय बाढ़ या दिल्ली में नवंबर–दिसंबर के स्मॉग के रूप में सामने है। दिल्ली में तो ऐसा संकट होता है कि लोगों को श्वांस लेने, आंखें खोलने में दिक्कत होने लगती है। उद्योगों को बंद करना पड़ता है।

कभी सूखा तो कभी अतिवृष्टि से अन्न का संकट भी खड़ा हो सकता है।

मुख्यमंत्री की मंशा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 22 जुलाई व 15 अगस्त को व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण महाभियान 2023 चलाया गया। सीएम योगी ने 22 जुलाई को बिजनौर और मुजफ्फरनगर में गंगा किनारे पौधरोपण कर इस महाभियान का शुभारंभ किया था, जबकि 15 अगस्त को अमृत वाटिका, गोमती तट (झूलेलाल वाटिका के निकट) लखनऊ में पौधरोपण किया। 22 जुलाई को लगाए गए थे 30 करोड़ 21 लाख 51 हजार 570 पौधे रोपित किए गए। वहीं 15 अगस्त को 5 करोड़, 94 लाख 47 हजार 384 पौधे यूपी में रोप गए। यानी दो दिन में कुल 36 करोड़ 15 लाख 98 हजार 954 पौधे रोपे गए। साफ है कि माफिया के प्रति कठोर और बच्चों के लिए नर्म दिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के वन्य व प्रकृति प्रेमी होने और उनकी सक्रियता के कारण राज्य के रानीपुर अभयारण्य को पिछले साल देश के बाघ अभयारण्य में सम्मिलित किया गया। उत्तर प्रदेश में बाघ अभयारण्य की संख्या बढ़कर तीन हो गई है, इसमें दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर सम्मिलित हैं। आंकड़े गवाही देते हैं कि गंगा और शिवालिक क्षेत्र के बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या साल 2018 में 646 थी, लेकिन योगी सरकार के प्रयासों से यह अब बढ़कर 804 हो गई है। वहीं दूसरी ओर, कार्बन उत्सर्जन कम कर पर्यावरण संरक्षण के लिए योगी सरकार पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए शहर ही नहीं गांवों में एलईडी लाइट की व्यवस्था की जा रही है। एलईडी कार्बन उत्सर्जन कम करने का माध्यम बन रहा है। इसी तरह सोलर पावर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जबकि जल संरक्षण के लिए ही आजादी के अमृत महोत्सव में गांव–गांव अमृत सरोवर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि चार दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पचास हजार मासूमों को असमय काल कवलित करने वाली बीमारी इंसेफेलाइटिस के पीछे प्रदूषण व गंदगी ही मुख्य कारण थे। पर्यावरण व स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर इसे दोबारा पैर पसारने से रोकने का भागीरथ प्रयास मुख्यमंत्री योगी ने किया है।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का ध्येय वाक्य 'सॉल्यूशन फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन' है। प्रदेश में इसे 2018 में ही बैन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी का मानना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पाप के समान है। फेंके गए प्लास्टिक को गाय खाकर मर जाती हैं तो गोमाता की हत्या का पाप लगता है। कभी नष्ट न होने से यह प्लास्टिक धरती मां के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक से पर्यावरण के संरक्षण के लिए सिक्स आर का मंत्र भी दिया है। उन्होंने रिड्यूज, रियूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफैब्रिकेट और रिपेयर के फार्मूले को अपनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने पौधे लगाने के साथ उनकी रक्षा का दायित्व लेने की भी अपील कर रखी है। वन आच्छादित क्षेत्र में तापमान 5 से 6 डिग्री कम रहता है और भीषण गर्मी से राहत मिलती है। जाहिर है कि इससे हम 'ग्लोबल वार्मिंग' के खतरे को भी कम कर सकते हैं। ◆

मो. : 9935097419

शहर से लेकर गांव तक रोशन

–अनिल श्रीवास्तव

प्रदेश की बिजली व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से बीते छह साल में उठाए गए कदमों का असर अब साफ नज़र आने लगा है। योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने से पहले हर साल खास तौर पर गर्मी में बिजली संकट की वजह से कानून–व्यवस्था की चुनौती खड़ी होती थी लेकिन बीते छह साल में यह सिलसिला थमा है। अब गाहे–बगाहे किसी तकनीकी वजह से भले ही थोड़ी–बहुत देर के लिए बिजली आपूर्ति बाधित होती हो वरना बिना किसी भेदभाव के हर गांव–हर शहर को पर्याप्त बिजली मिल रही है। यही नहीं जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंच पाई थी वहां भी योगी सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग न केवल बिजली पहुंचाई बल्कि ऐसे घरों को भी रोशन किया जो बिजली से कोसों दूर थे। बिजली के क्षेत्र में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है तथा जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय–समय पर ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके जरूरी निर्देश देते रहे उससे भी बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने में काफी मदद मिली है। अब योगी सरकार का लक्ष्य पूरे प्रदेश को अनवरत 24 घंटे बिजली आपूर्ति का है। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। दरअसल, प्रदेश में साल दर साल बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही बिजली व्यवस्था में सुधार को प्राथमिकता पर रखा। सबसे पहले बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी क्षेत्रों को एक समान बिजली आपूर्ति का अभियान छेड़ा गया। बिजली आपूर्ति में वीआईपी कल्चर को समाप्त किया गया वरना पहले की सरकारों में मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली नेताओं के इलाकों, बड़े शहरों के अलावा कुछ चुनिंदा जिलों को ही भरपूर बिजली मिल पाती थी। अब सभी जिलों को एक समान बिजली आपूर्ति हो रही है तो गांवों को भी तय शिड्यूल के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मौजूदा समय में गांवों के लिए 18 घंटे, नगर पंचायत व तहसीलों के लिए 21.30 घंटे, बुंदेलखंड के लिए 20 घंटे तथा महानगर, मंडल व जिला मुख्यालय तथा उद्योगों के लिए 24 घंटे आपूर्ति का रोस्टर तय है। खास बात यह है बीते कुछ वर्षों में बिजली की मांग में भारी इज़ाफा हुआ है लेकिन सरकार बेहतर प्रबंधन करके बिजली आपूर्ति पटरी पर बनाए रखने में कामयाब रही है। किसानों को इससे काफी राहत मिली है। गांवों में लोगों को अब घरेलू इस्तेमाल के साथ खेती किसानी के लिए भी पर्याप्त बिजली मिल रही है। हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पावर कारपोरेशन प्रबंधन को सख्त हिदायत दी है कि रोस्टर का कड़ाई से पालन किया जाए और हर श्रेणी को तय शिड्यूल के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

एक दौर था जब ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने या फुंकने पर शहरी क्षेत्रों के लोगों को 48 से 72 घंटे और कभी–कभी

तो उससे भी ज्यादा वक्त तथा ग्रामीण इलाकों में 15 दिन से एक महीने का इंतजार करना पड़ता था। खास तौर पर इससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी अब शहरी क्षेत्रों में छह से 24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे के भीतर क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था की गई और इसका सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है।

बिजली आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर लाने के साथ–साथ योगी सरकार ने उपभोक्ताओं की सहूलियत का भी ध्यान रखा है। सरकार ने 2023–24 के बजट में किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में 2019 से बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि बिजली कंपनियों की तरफ से इसकी पहल नहीं हुई लेकिन सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाने के बजाय बिजली चोरी रोककर और लाइन हानियां कम करके लोगों को राहत देने की कोशिश की। अब महिलाओं को बिजली कनेक्शन में 15 से 30 फीसदी छूट देने विचार किया जा रहा है।

जहां तक यूपी में बिजली व्यवस्था का प्रश्न है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस साल गर्मी को छोड़ दिया जाए तो बीते पांच साल में बहुत ज्यादा संकट जैसी स्थिति नहीं रही। गाहे–बगाहे मांग बढ़ने या अन्य तकनीकी वजहों से थोड़ी बहुत समस्या खड़ी भी हुई तो जल्द ही उसे दुरुस्त करके आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर ले आई गई। दरअसल, यूपी में बीते पांच–छह साल में बिजली व्यवस्था में सुधार नज़र आने के पीछे एक बड़ी वजह पिछली सरकारों में शुरू हुई बिजली परियोजनाओं को योगी सरकार द्वारा प्राथमिकता पर पूरा कराना भी है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढ़ी है लेकिन बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनने और पूरे प्रदेश को अनवरत 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य हासिल करने के लिए यूपी को अभी लंबा सफर तय करना है। योगी सरकार ने इसके लिए रोडमैप तैयार करके काम शुरू कर दिया है। आने वाले वर्षों में इसके परिणाम भी नजर आएंगे। यूपी में बिजली की मांग 28,000 मेगावाट से आसपास पहुंच गई है। प्रदेश के बिजलीघरों से मिलने वाली बिजली के अलावा सरकार जरूरत पड़ने पर एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीद रही है ताकि प्रदेशवासियों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े। योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से प्रदेश में प्रमुख धार्मिक स्थलों की बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने पर भी ध्यान दिया गया है। धार्मिक पर्यटन के लिहाज़ से बेहद अहम अयोध्या, वाराणसी, विंध्याचल धाम, गोरखपुर, प्रयागराज, देवीपाटन धाम समेत लगभग प्रमुख धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश दिए गए हैं। यही नहीं धार्मिक स्थलों की बिजली व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त रखने के लि रखने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। खुले तारों को भूमिगत कराने के साथ ही इन स्थलों को सोलर प्लांट से भी रोशन रखने की मुहिम छेड़ी गई है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों की बिजली व्यवस्था में सुधार की योगी सरकार की पहल का बेहतर परिणाम यह है कि जहां पर्यटकों की संख्या में इज़ाफा हो रहा है वहीं इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निवेशकों के आने से स्थानीय स्तर पर विकास के साथ–साथ रोज़गार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। इतना ही नहीं अब होली, दीवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि सहित अन्य प्रमुख त्योहारों पर शहरों से लेकर गांवों तक कटौतीमुक्त बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

यही नहीं प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश की बिजली

आपूर्ति व्यवस्था और चाक–चौबंद करने के लिए 15 नए जोन गठित करने का निर्णय किया है। राजधानी लखनऊ के शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति कर रहे लेसा के दो नए जोन के साथ ही लखनऊ में एक और जोन बनाया गया है। गाज़ियाबाद को भी तीन खंडों में बांट दो नए क्षेत्र गठित किए गए हैं। इनके अलावा दस अन्य बड़े जिलों में भी एक–एक नया जोन बनाया गया है। जिन जिलों में एक–एक जोन और बनाया गया है उनमें गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा हैं। अभी लखनऊ के शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लेसा के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में लेसा के दो जोन लेसा (सिस गोमती) और लेसा (ट्रांसगोमती) हैं। 15 नए जोन बनने के बाद प्रदेश में अब कुल 40 जोन हो गए हैं। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है शहरी क्षेत्रों में बिजली संबंधी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए बड़े नगरों में नए जोन बनाने का निर्णय किया गया है। विद्युत वितरण क्षेत्रों के पुनर्गठन से गुणवत्तापरक बिजली आपूर्ति के साथ ही निगरानी तंत्र भी बेहतर होगा। इससे लाइन हानियां कम करने और बिजली चोरी रोकने में भी मदद मिलेगी। अहम बात यह है कि नए जोन बन जाने से बिजली सुधार के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से चलाई जा रही रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) को रफ्तार मिलेगी। स्मार्ट मीटरिंग के काम में भी तेजी आएगी। गौरतलब है कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए आरडीएसएस योजना के तहत बिजली वितरण निगमों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने पर सरकार का ख़ास ज़ोर है। बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार करके भेजी जा रही है।

हालांकि यूपी में बिजली के क्षेत्र में चुनौतियां भी कम नहीं है। राज्य सरकार के नियंत्रण वाली बिजली कंपनियों (डिस्कॉम्स) का घाटा एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया है। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और डिस्कॉम्स को घाटे से उबारने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। लाइन लॉस (बिजली चोरी) पर नियंत्रण के लिए मुहिम चलाई जा रही है। यही नहीं बीते 10 साल में यूपी में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 1.27 करोड़ से बढ़कर 3.50 करोड़ से ज्यादा यानि करीब तीन गुना हो गई है। जिस अनुपात में उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा हुआ है सरकार ने उसी अनुपात में वितरण और ट्रांसमिशन नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया है ताकि बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित न हो। आने वाले समय में बिजली की संभावित मांग का आकलन कराकर जरूरत के अनुसार वितरण और ट्रांसमिशन ढांचा तैयार कराने के साथ–साथ बिजली उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ◆

मो. : 9935097410

शिक्षा का बदलता परिवेश

आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश

—अंजु अग्निहोत्री

सा विद्या या विमुक्तये् यानि शिक्षा वह है जो बंधनों से मुक्त करती है। इस सोच का विस्तार कर देश में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य, उत्तर प्रदेश की सरकार सर्वांगीण विकास करने में शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। शिक्षा से हम जीवन को खुशहाल और सार्थक बना सकते हैं। जीवन को नई दिशा दे सकते हैं और बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति में शिक्षित युवा शक्ति की अहम भूमिका होती है। जिस देश की युवा शक्ति शिक्षित और मजबूत होती है वह देश तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। शिक्षा के लिए बचपन में ही विशेष ध्यान रखने के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सार्थक पहल और प्रयास की बदौलत स्कूली शिक्षा में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय फलक पर अपनी अनूठी पहचान बनाई है। बीते कुछ समय में प्रदेश में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर सकारात्मक बदलाव आये हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और बेहतर ढंग से किया है। 1.92 करोड़ छात्र–छात्राओं को बैग, ड्रेस, स्वेटर, जूता–मोजा एवं स्टेशनरी हेतु प्रति छात्र/छात्रा 1200 रु. की धनराशि अंतरित हुई है।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत 1.92 करोड़ बच्चों का नामांकन कराकर जता दिया है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। डबल इंजन की सरकार जहां चाह वहां राह निकलने के लिए कृतसंकल्पित है। 16 लाख प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित किये है।

निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करायी हैं। परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को दी रही शिक्षा को और बेहतर ढंग से प्रदान किया जाये, इसका भी विशेष ध्यान रखा हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत विद्यालयों में सभी निर्धारित मानक बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए विद्यालयों के संतृप्तीकरण का

कार्य तथा विद्यालयों एवं शौचालयों की साफ–सफाई व अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जा हैं। विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के तहत अविद्युतीकृत विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था कराये जाने, गुणवत्ता शिक्षा के तहत निपुण लक्ष्य ऐप पर आंकलन की प्रगति, शिक्षक संकुल, एस.आर.जी. एवं ए.आर.पी. द्वारा निपुण विद्यालय बनाये जाने की कार्ययोजना एवं प्रगति, जनपद के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के संचालन एवं विद्यालयों में लगाये गये 'हमारे शिक्षक' बोर्ड अद्यतन किये गये हैं। बालिका शिक्षा के तहत बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन एवं आधार वेरिफिकेशन, शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के चयन की प्रगति, कक्षा–9 की बालिकाओं का रजिस्ट्रेशन कराने की प्रगति, विद्यालयों के उच्चीकरण हेतु निर्माण कार्यों की प्रगति तथा समेकित शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों को डी.बी.टी. के माध्यम से स्टाइपेण्ड एवं एस्कॉर्ट एलाउंस बच्चों को दिये जाने तथा समर्थ एप पर दिव्यांग बच्चों के पहचान एवं नामांकन में वृद्धि की है। प्रदेश के नौनिहालों के सपनों को साकार करने के लिए निरन्तर प्रयास हो रहे हैं। बालक–बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हाल के वर्षों में प्रदेश ने शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में आशाजनक सफलताएं प्राप्त की हैं।

प्रदेश का शैक्षणिक परिदृश्य गुणवत्ता और नवाचारों की दिशा तय करने में देश में एक आदर्श स्थापित कर रहा है।

सरकारी स्कूलों की बदल रही तस्वीर

राज्य के सरकारी स्कूलों की तस्वीर अब बदलने लगी है। शैक्षिक गुणवत्ता, मूलभूत सुविधाओं तथा भौतिक संरचना में निजी स्कूलों से राजकीय विद्यालय आज पूर्ण प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने के

लिए समाजसेवी भी सहयोग कर रहे हैं। 1.40 लाख से अधिक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालक–बालिकाओं के लिए स्मार्ट क्लास, शौचालय, मल्टिपल हैण्ड वांशिंग यूनिट, रसोईघर का सुदृढ़ीकरण, फर्श का टाइलीकरण, स्वच्छ पेयजल आदि की सुविधाएँ सरकार ने विकसित की हैं। ई–एजुकेशन की आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन की शुरुआत कर नई पहल की गई है। प्रदेश के चिन्हित राजकीय विद्यालयों में विभिन्न चरणों में कंप्यूटर लैब स्थापित की गई हैं तथा शेष विद्यालयों में लैब स्थापना का कार्य जारी है। विद्यालय में शैक्षिक प्रगति और गतिविधियों की अनवरत मॉनिटरिंग के लिए प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करते हुए एप के माध्यम से कम समय में सूचनाओं का संकलन कर विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम को ट्रैक किया जा रहा है।

डिजिटल शिक्षा पर जोर

- 40000 से अधिक स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं।
- 5000 से अधिक स्कूलों की आईसीटी प्रयोगशालाओं का सुसज्जीकरण
- दीक्षा ऐप पर कक्षा 1 से 12 तक के सभी विषयों के लिए उत्कृष्ट शिक्षण सामग्री।
- समर्थ ऐप द्वारा 2,98,000 से अधिक दिव्यांग बच्चों का चिह्नांकन एवं विद्यालयों में नामांकन।
- दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षकों का व्यावसायिक विकास।
- बहु–दिव्यांग बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन।
- कैरियर परामर्श पोर्टल 'पंख' के माध्यम से छात्रों को कैरियर विकल्प का चयन करने में मार्गदर्शन।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना

- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था।
- विशेषज्ञों द्वारा अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन।
- योजना से विगत दो वर्षों में कोचिंग प्राप्त करने वाले 23 अभ्यर्थियों का संघ लोक सेवा आयोग एवं 95 अभ्यर्थियों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन।

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण

- 44,000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 746 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की लगभग 40 लाख बालिकाओं को प्रशिक्षण।

बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थाओं में सुधार

- बोर्ड परीक्षाओं की निगरानी के लिए केन्द्रीय कमान एवं नियंत्रण केन्द्र की स्थापना।
- 3 लाख से अधिक कैमरों का उपयोग कर इमेजिंग के माध्यम से सभी 1.37 लाख परीक्षा केन्द्रों की वास्तविक समय निगरानी NIPUN भारत मिशन।
- छात्रों के कक्षा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए शैक्षणिक स्तर में सुधार।

- प्राथमिक विद्यालय के सभी 6.24 लाख शिक्षकों को साप्ताहिक एवं दैनिक पाठ योजनाएं प्रदान करने के लिए शिक्षक संदर्शिका एवं निर्देशिका।
- छात्रों के समग्र विकास हेतु प्रत्येक स्कूल में सुसज्जित पुस्तकालय एवं खेल सामग्री की व्यवस्था।
- प्रत्येक स्कूल में 150 से अधिक प्रिंट समृद्ध सामग्री और गणित किट के माध्यम से एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा।

SHARDA (स्कूल हर दिन आयें) कार्यक्रम

- 5.5 लाख से अधिक आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान एवं विद्यालयों में नामांकन।
- बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु जेन्डर सेन्सिटिविटी कार्यक्रम।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण।

प्रोजेक्ट अलंकार

- माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं जैसे कम्प्यूटर लैब, आईसीटी लैब, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान लैब, टैबलेट, पुस्तकालय आदि का विकास एवं नवीनीकरण।
- स्कूल मैपिंग पोर्टल 'पहुंच' के माध्यम से असेवित बस्तियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पहचान कर उनका निस्तारण।
- स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विद्या समीक्षा केन्द्र के माध्यम से प्रतिमाह 1 लाख से अधिक हितधारकों से संवाद परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को 2.09 लाख टैबलेट वितरित।

मो. : 8787093085

पंच प्रण को साकार करती उत्तर प्रदेश की धरती

–प्रदीप कुमार गुप्ता

भारत ने वर्ष 2022 में अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत देशवासियों से पंचप्रण का आह्वान किया। देश वर्ष 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा। इन 25 वर्षों के आगामी काल को प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर तथा विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की पूर्ति के लिए भारतवासियों से पंचप्रण को आत्मसात करने को कहा है। इन पंचप्रण में विकसित भारत के लिए कार्य करना, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता के लिए कार्य करना तथा नागरिकों के कर्तव्य शामिल हैं। पंचप्रण को साकार करने के लिए देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कार्य किये जा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश भी पंचप्रण को साकार करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर होकर कार्य प्रारंभ कर चुका है। मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि 'उत्तर प्रदेश पर प्रकृति व परमात्मा की असीम कृपा है। राज्य में अनन्त सम्भावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश अवसरों की भूमि है। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है, उत्तर प्रदेश देश में सबसे युवा राज्य है।' विश्व के अनेक देशों की सम्मिलित जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी के समक्ष बहुत छोटी नजर आती है। यहां देश की सर्वाधिक युवा, कामकाजी, ऊर्जावान, क्षमतावान तथा कर्मशील आबादी रहती है। यह विशेषताएं उत्तर प्रदेश को पंचप्रण की प्राप्ति के लिए सक्षम और समर्थ बनाती हैं।

पंचप्रण का पहला प्रण विकसित भारत है। देश को विकसित बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपनी अर्थव्यवस्था को अगले 05 वर्षों में 01 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में यू.पी. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2023 का आयोजन महत्वपूर्ण अवसरों का सृजन करने वाला रहा है। यह राज्य के विकास को गति देगा, रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा तथा क्षेत्रीय विषमताएं दूर करेगा। इन के माध्यम से समाज, प्रदेश तथा देश का

विकास त्वरित होगा और भारत को 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री जी की लक्ष्य प्राप्ति में भी यह साधक बनेगा।

पंचप्रण का दूसरा भाग गुलामी के हर अंश से मुक्ति है। इसके लिए देश में जहां अनेक कार्य किये जा रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं है। व्यापक रूप से देखा जाए तो गुलामी एक मानसिकता व सोच भी है। मुख्यमंत्री जी भारत की प्राचीन परंपराओं के प्रति सम्मान का भाव विकसित कर, प्रदेशवासियों में गुलामी की सोच से मुक्ति के लिए सतत् प्रयत्नशील है। हमें अपनी परम्पराओं पर गर्व होना ही चाहिए। हम आजाद भारत में रह रहे हैं। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा तथा सुदृढ़ लोकतंत्र है। एक लंबे समय तक गुलामी का दंश झेलने के बाद भारत ने अनेक संघर्षों व बलिदानों के माध्यम से गुलामी से मुक्ति पायी है और स्वतंत्र हुआ है। इसलिए अब गुलामी के हर अंश से मुक्ति आवश्यक भी है और अनिवार्य भी।

अपनी विरासत पर गर्व की अनुभूति करना पंचप्रण का तीसरा प्रण है। अपनी विरासत के सम्मान, उनके संवर्धन तथा अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश में बहुत से ऐसे कार्य किये जा रहे हैं, जो अपनी विरासत पर गर्व करने से जोड़े जा सकते हैं। प्रयागराज कुम्भ–2019 का आयोजन सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा स्वच्छता के मानकों पर किया गया। यह किसी उपलब्धि से कम नहीं है। प्रयागराज कुम्भ–2019 के आयोजन देश व दुनिया के लोगों को भारत की परम्पराओं के प्रति आकृष्ट किया। अयोध्या में दीपोत्सव, मथुरा में रंगोत्सव सहित देव दीपावली जैसे आयोजन अपनी विरासत पर गर्व करने के ही उदाहरण है। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम, मथुरा वृन्दावन, नैमिषारण्य, श्रृंगवेरपुर का विकास हो या अयोध्या को विश्व की सबसे सुंदर नगरी के रूप में विकसित करने का मुख्यमंत्री जी का संकल्प, यह सभी अपनी विरासत के प्रति सम्मान के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में बड़ी विरासत मौजूद है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के परम्परागत कुटीर उद्योगों से जुड़े हस्तशिल्पियों तथा कारीगरों के लिए 'एक जनपद, एक उत्पाद योजना' (ओ.डी.ओ.पी.) तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरूआत की गयी। आज यह योजनाएं देश व अन्य प्रदेशों के लिए नजीर बनी हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा विदेशी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को ओ.डी.ओ.पी. के उत्पाद उपहार में दिये जा रहे हैं। ओ.डी.ओ.पी. योजना प्रदेश में अपनी विरासत के संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हुई है। इसने प्रदेश से निर्यात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, साथ ही, रोजगार के अनेक नवीन अवसर भी सृजित हुए हैं।

मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि 'उत्तर प्रदेश पर प्रकृति व परमात्मा की असीम कृपा है। राज्य में अनन्त सम्भावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश अवसरों की भूमि है। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है, उत्तर प्रदेश देश में सबसे युवा राज्य है।' विश्व के अनेक देशों की सम्मिलित जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी के समक्ष बहुत छोटी नजर आती है। यहां देश की सर्वाधिक युवा, कामकाजी, ऊर्जावान, क्षमतावान तथा कर्मशील आबादी रहती है। यह विशेषताएं उत्तर प्रदेश को पंचप्रण की प्राप्ति के लिए सक्षम और समर्थ बनाती हैं।

पंचप्रण का चौथा प्रण एकता और एकजुटता की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भलाई तथा उनके कल्याण के लिए योजनाएं चलाई हैं। शासन की समस्त योजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी वर्गों, सभी धर्म के लोगों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जब भी प्रदेशवासियों की बात करते हैं तो वे समस्त 25 करोड़ प्रदेशवासियों के हित की बात करते हैं, इसमें कोई विभाजन नहीं है। यह एकता और एकजुटता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। एकता और एकजुटता का वातावरण वर्तमान में प्रदेश की सुदृढ़ कानून–व्यवस्था से भी स्थापित हुआ है। प्रदेश में सभी धर्मों के धार्मिक उपासना स्थलों से मुख्यमंत्री जी की पहल पर लाउडस्पीकर उतारे गए या उनकी आवाज धीमी हुई है। अब कोई भी धार्मिक आयोजन सड़क पर नहीं होते हैं। यह कार्य समाज के विभिन्न वर्गों में एकता व एकजुटता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

पंचप्रण का पांचवा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रण है नागरिकों का कर्तव्य। पंचप्रण के पहले चार प्रण की सिद्धि के लिए जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं, वही है पांचवा प्रण जिसके बारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यह पांचवा प्रण सभी प्रण की आधारशिला है। वास्तव में एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार प्रदेशवासी होने की दृष्टि से सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यदि देश के सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया के विकसित देश अपने नागरिकों के राष्ट्रप्रेम के कारण ही विकसित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में किए जा रहे सभी विकास परक कार्यों में प्रदेशवासियों की सहभागिता ही उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है और पहुंचा भी रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर प्रदेश वासियों ने अनुपम राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है। एक नागरिक के रूप में हमारे प्रदेश और देश के प्रति बहुत दायित्व हैं। राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है, तरक्की की दिशा में ले जा रही है, इनमें नागरिक कर्तव्यों का पालन निश्चित रूप से गति प्रदान करेगा। एक नागरिक के रूप में हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ाता हो। प्रदेश में अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है, इनमें गंदगी ना हो इन पर अवैध कब्जा ना हो यह सरोवर गांव की गरिमा को पोषित करें, यह नागरिकों की जिम्मेदारी है। प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान महाअभियान बना है। प्रकृति के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का वृक्षारोपण एक श्रेष्ठ माध्यम है। हमारा कर्तव्य है कि जो पौधरोपण किए गए हैं, वे सुरक्षित रहें और वृद्धि करते हुए पर्यावरण संतुलन में योगदान दें। राज्य सरकार मिशन रोजगार के माध्यम से प्रदेश के नौजवानों को नौकरी तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। जिन्हें नौकरी अथवा रोजगार मिल रहा है, उनका कर्तव्य है कि वे ईमानदारी तथा पूर्ण निष्ठा से कार्य करते हुए जनता को न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करने में अपना योगदान दें।

मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यह पांचवा प्रण सभी प्रण की आधारशिला है। वास्तव में एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार प्रदेशवासी होने की दृष्टि से सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यदि देश के सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया के विकसित देश अपने नागरिकों के राष्ट्रप्रेम के कारण ही विकसित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में किए जा रहे सभी विकासपरक कार्यों में प्रदेशवासियों की सहभागिता ही उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है और पहुंचा भी रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर प्रदेश वासियों ने अनुपम राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है। एक नागरिक के रूप में हमारे प्रदेश और देश के प्रति बहुत दायित्व हैं। राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है,

उत्तर प्रदेश गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती के पावन संगम का प्रदेश है। अत्यन्त प्राचीन इस धरा पर यमुना नदी के किनारे भगवान श्रीकृष्ण और सरयू नदी के किनारे भगवान श्रीराम ने अपनी लीला रची। ये आज भी हमें मंत्रमुग्ध और भाव–विभोर कर देती है। बुन्देलखण्ड की धरती वीरता के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अवध क्षेत्र अपनी लखनवी तहज़ीब, सभ्यता और अदब से प्रदेश का नाम भारत और विश्व में रौशन करता रहा है। ऐसे प्रदेश में विगत 6 वर्षों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास कार्यों से राज्य की नई पहचान बन रही है। उत्तर प्रदेश विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सतत् प्रगति तथा उन्नति कर आगे बढ़ रहा है। राज्य में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। यह प्रगति अनवरत जारी है, और नये कीर्तिमान स्थापित कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी तथा अन्य क्षेत्रों में प्रदेश में द्रुतगति से विकास कार्य हो रहे हैं, जिसने राज्य को देश की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने में योगदान दिया है।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां लगभग 25 करोड़ की आबादी निवास करती

है। साथ ही, उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से पूर्वी, पश्चिमी, मध्य तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में भी अपनी विभिन्नताएं प्रदर्शित करता है। ऐसे में बड़ी आबादी की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति तथा प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 06 वर्षों से अनवरत किया जा रहे कार्यों के परिणाम सुखद हैं एवं गौरवान्वित करने वाले हैं प्रदेश में कानून–व्यवस्था की बेहतर स्थिति से निवेश का व्यापक व अनुकूल माहौल बना है। इसी का परिणाम है कि विगत फरवरी 2023 में यू.पी. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन के माध्यम से प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को ज़मीनी धरातल पर उतारने के लिए शीघ्र ही ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विभिन्न विभागों ने कमर कस ली है और तीव्र गति से प्रयास प्रारम्भ कर दिए हैं।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए परिवर्तनों में मुख्य रूप से ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 19 पैरामीटरों पर आधारभूत संरचना व मूलभूत सुविधाओं की स्थापना के लिए ठोस कार्य किये गए हैं। इनसे परिषदीय विद्यालयों में पठन का माहौल बना है और छात्र–छात्राओं के नामांकन में वृद्धि हुई है। बेसिक शिक्षा की तर्ज़ पर ही अब माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों के कायाकल्प के लिए प्रोजेक्ट अलंकार की शुरुआत की गई है। हाल ही में बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का वाहक बनेगा। शिक्षा की पहुंच सर्व सुलभ बनाने, विद्यार्थियों के कैरियर गाइडेंस, विद्यालय अनुश्रवण, ई–लाइब्रेरी, विद्यालयों के वेब पेज/वेबसाइट हेतु विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए हैं। यह तकनीकी के बेहतर प्रयोग का उदाहरण बने हैं जिनसे सरकारी विद्यालयों में आमूल–चूल बदलाव हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में 'एक जनपद–एक मेडिकल कॉलेज' की दिशा में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 65 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें सरकारी के साथ ही पी.पी.पी. मोड पर भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। नर्सिंग व पैरामेडिकल चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश की बड़ी आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अच्छे चिकित्सकों के साथ ही नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए प्रदेश में मिशन निरामयाः के माध्यम से गुणवत्तायुक्त नर्सिंग व पैरामेडिकल शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। प्रदेश के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों की गुणवत्ता सुधार की दिशा में सराहनीय पहल करते हुए

क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया द्वारा इन संस्थानों की रेटिंग कराई जा रही है। इससे इन संस्थानों में आपस में अच्छी प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ा है तथा वे सुधार हेतु प्रेरित हुए हैं। प्रदेश सरकार का यह कार्य इन संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धि में भी सहायक हो रहा है। नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थानों की रेटिंग को प्रदर्शित करने वाली वेबसाइट का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। इसके साथ ही, इन संस्थानों की गुणवत्ता सुधार हेतु मेण्टर–मेण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 संस्थानों का मेण्टर संस्थाओं के रूप में चयन किया गया है। प्रदेश में हेल्थ ए.टी.एम. लगाए जा रहे हैं, जहां से विभिन्न प्रकार की जांच की सुविधा दी जा रही है। साथ ही, टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं मिल रही हैं। किसी भी राज्य के विकास के लिए अच्छी आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके दृष्टिगत प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पहचान आज एक्सप्रेस–वे स्टेट के रूप में हो रही है। पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे पर संचालन शुरू हो चुका है तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे तथा पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से बलिया को जोड़ने हेतु बलिया लिंक एक्सप्रेस–वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। एक्सप्रेस–वे के क्षेत्र में प्रदेश को प्रगति की नई उड़ान देने के लिए मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर लम्बे लगभग 36,230 करोड़ रुपए की लागत से गंगा एक्सप्रेस–वे का निर्माण भी प्रगति पर है। गंगा एक्सप्रेस–वे पश्चिम से पूर्व को कनेक्टिविटी तो देगा ही, साथ ही, लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। यह प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में सम्पर्क बढ़ाकर क्षेत्रीय विषमता को दूर करने में सहायक होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित समीपवर्ती राज्यों को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से भी जोड़ेगा। प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेस–वे की खास बात यह भी है कि इनके किनारे औद्योगिक क्लस्टरों का विकास भी किया जा रहा है जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी प्रदेश की देश व दुनिया में

उत्तर प्रदेश ने सदैव ही देश व दुनिया को दिशा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की छवि में सकारात्मक रूप से बदलाव आया है और प्रदेश अपनी भूमिका को प्रदेशवासियों तथा देश के हित में अच्छे रूप से निभा रहा है। प्रदेश सरकार लोक कल्याण के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रही है। शासन–प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री कमाण्ड सेण्टर तथा सी.एम. डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है। यह प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त तथा सदैव तत्पर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास तथा समृद्ध विरासत मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सतत् अक्षुण्ण रहते हुए उन्नति की ओर बढ़ रही है।

नई पहचान बना रहे हैं। औद्योगिक गलियारों से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

अयोध्या तथा गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डों का निर्माण हो रहा है। इनके बन जाने से प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां पांच–पांच अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। जेवर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। प्रदेश में घरेलू उड़ानों की संख्या तथा गन्तव्य में वृद्धि हुई है। वर्तमान में 09 क्रियाशील एयरपोर्ट से 75 से 80 डोमेस्टिक तथा इण्टरनेशनल फ्लाइट उपलब्ध है। देश का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या–01 वाराणसी से हल्दिया के बीच शुरू हो चुका है। इसने उत्तर प्रदेश को पूर्वी बंदरगाह से कनेक्टिविटी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश में इनलैंड वॉटर कनेक्टिविटी को विस्तार दिया जा रहा है। किसानों की समृद्धि के बगैर किसी भी राज्य का विकास अधूरा है। किसानों के कल्याणार्थ प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील विजन के अनुरूप ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। रसायनमुक्त तथा विषमुक्त खेती के लिए प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम संचालित है। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। गन्ना किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में अब तक 02 लाख 15 हजार करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान कर रिकॉर्ड बनाया गया है। निजी नलकूप संचालित करने वाले किसानों के विद्युत बिल में छूट दी जा रही है। इसके लिए फीडर सेपरेशन के कार्य प्रदेश में गतिमान है।

सामाजिक, आर्थिक अवसंरचनाओं के विकास के साथ ही आस्था के माध्यम से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने में विशेष जोर दिया जा रहा है। इससे प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों में पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। अकेले श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन सहित वाराणसी में 01 वर्ष में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु व पर्यटक दर्शनार्थ आ रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, वृन्दावन नैमिषारण्य, प्रयागराज कुम्भ–महाकुम्भ के आयोजन आदि अनेक कार्यों से उत्तर प्रदेश, देश व दुनिया के नक्शे में पर्यटन तथा आस्था के केंद्र के रूप में उभरा है। इन स्थलों के विकास के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी व्यापक रूप से बढ़ावा मिला है। अयोध्या को विश्व की सुंदरतम नगरी बनाने का मुख्यमंत्री जी का विजन तेजी से आकार ले रहा है। वर्ष 2024 में श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो जाने पर वहां भी पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। उनकी सुविधा के लिए मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में तीव्र गति से कार्य हो रहे हैं।इसके साथ ही प्रदेश में अन्य अनेक कार्यों ने भारत सहित दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। प्रदेश की 'एक जनपद एक उत्पाद योजना', 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना', 'माटी कला बोर्ड' जैसी अनेक योजनाओं ने प्रदेश को प्रगति पथ पर अग्रसर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इन योजनाओं ने प्रदेश का निर्यात बढ़ाने, व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने तथा सम्बन्धित जनपदों के हस्तशिल्पियों, कारीगरों तथा श्रमिकों की समृद्धि और उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय बजट सहित देश के अन्य प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की इन योजनाओं से प्रेरित अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं इन सभी योजनाओं के प्रेरणा स्त्रोत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं।

उत्तर प्रदेश ने सदैव ही देश व दुनिया को दिशा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की छवि में सकारात्मक रूप से बदलाव आया है और प्रदेश अपनी भूमिका को प्रदेशवासियों तथा देश के हित में अच्छे रूप से निभा रहा है। प्रदेश सरकार लोक कल्याण के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रही है। शासन–प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री कमाण्ड सेण्टर तथा सी.एम. डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है। यह प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त तथा सदैव तत्पर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास तथा समृद्ध विरासत मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सतत् अक्षुण्ण रहते हुए उन्नति की ओर बढ़ रही है। ◆

मो. : 7705800992

समाज को जोड़ने का अनूठा मूलमंत्र

—यशोदा श्रीवास्तव

यूं तो योगी बनना ही आसान नहीं है लेकिन योगी आदित्यनाथ बनना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। गोरक्षनाथ मंदिर का उत्तराधिकारी बनने के वक्त उनकी उम्र मात्र 22 साल की थी और वे जब पहला लोकसभा का चुनाव लड़े तो 26 साल के थे, लोकसभा के सर्वाधिक युवा सदस्य! हिंदुत्व वादी छवि ही उनकी शिनाख्त है जो उन्हें गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुरूप विरासत में मिली है। उनके नेतृत्व में हिंदू युवा वाहिनी के गठन के पीछे का मकसद हिंदुओं को संगठित कर उन्हें अपने धर्म के प्रति जागरूक करना था। वे कभी भी किसी जाति व धर्म के खिलाफ नहीं थे,न हैं लेकिन सनातन धर्म की आलोचना कत्तई न बर्दाश्त कर सकने वाले संन्यासी हैं। गोरखपुर में गोरक्षपीठ के इर्द–गिर्द मुस्लिम समाज की बस्तियां हैं,वे योगी जी को वोट दें न दें लेकिन इन्हें अपना सबसे मजबूत और भरोसेमंद संरक्षक जरूर मानते हैं। बतौर जनप्रतिनिधि उन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरक्षनाथ मंदिर में लगने वाले जनता दर्शन में ज्यादातर संख्या उन्हीं की होती और एक गवाह नहीं मिलेगा जो यह कह दे कि उनकी नहीं सुनी गई।

योगी आदित्यनाथ सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं। और जब सामाजिक समरसता की बात होती है तो इसमें जातियों का बंधन नहीं रहता। वे गरीबों के बीच भोजन करते हैं, दीवाली उन्हीं के बीच मनाते हैं। सहभोज से समरसता उनका मूलमंत्र है। वे चाहते हैं कि हिंदू धर्म में जो जातियों की बेड़ी है वह टूट जाय! हालांकि यह आसान नहीं है लेकिन हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने इस मुहिम में शिद्दत से जुटे हुए हैं। सांसद थे तब भी और मुख्यमंत्री हैं तब भी, साल में दो तीन सहभोज के आयोजनों में तो उनकी मौजूदगी रहती ही है। योगी जी जब ऐसे आयोजनों में होते हैं तो इसका संदेश भी स्पष्ट होता है। गोरक्षनाथ की यह सदियों की परंपरा है जिसे योगी आदित्यनाथ निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल राम मंदिर के लिए दशकों तक चले आंदोलन में गोरक्षपीठ के सहभोज से समरता का बड़ा योगदान रहा है। यही वह मूलमंत्र था जिसकी वजह से हजारों लाखों हिंदू इस

आंदोलन से जुड़े, लाठी डंडे खाए और 1992 में मुलायम सिंह यादव की सरकार की बर्बरता में तमाम राम भक्त शहीद भी हुए।

भव्य राम मंदिर का सपना गोरक्षपीठ के ब्रम्हलीन महंत अवेद्यनाथ जी का था। गोरक्ष मंदिर राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख केन्द्र था। आगामी जनवरी माह में भव्य राम मंदिर का हिंदू जनमानस के लिए समर्पण संभावित है। यह भारत और भारत के बाहर रह रहे करोड़ों हिंदुओं का सपना था जो अब साकार होने जा रहा है। राम मंदिर का विश्व के समस्त हिंदू धर्मावलंबियों को समर्पण गोरक्षपीठ के ब्रम्हलीन महंत अवेद्यनाथ जी और शहीद हुए कारसेवकों को हृदय से श्रद्धांजलि भी होगी।

पहले की सरकारों में उपेक्षित अयोध्या को रामनगरी का स्वरूप गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ के यूपी का सीएम बनने के बाद ही हासिल हुआ है। बताने की जरूरत नहीं कि योगी आदित्यनाथ केवल सीएम भर नहीं हैं, वे नेपाल सहित भारत के करोड़ों श्रद्धालुओं के श्रद्धा के केंद्र गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं। इन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए योगी पूज्यनीय हैं। वे उस पीठ के महंत हैं जिसकी पीढ़ियां रामनगरी अयोध्या से जुड़ी हुई है। श्रीराम जन्मभूमि मुक्त आंदोलन में अयोध्या से 135 किलोमीटर दूर गोरखपुर के गोरक्षपीठ की बड़ी भूमिका रही है। पूर्व में इस पीठ के अनेक महन्थों ने समय–समय पर सहभोज से समरसता के जरिए समाज के बड़े वर्ग को जन्मभूमि आंदोलन के लिए तैयार किया है।

योगी आदित्यनाथ सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं। और जब सामाजिक समरसता की बात होती है तो इसमें जातियों का बंधन नहीं रहता। वे गरीबों के बीच भोजन करते हैं, दीवाली उन्हीं के बीच मनाते हैं। सहभोज से समरसता उनका मूलमंत्र है। वे चाहते हैं कि हिंदू धर्म में जो जातियों की बेड़ी है वह टूट जाय! हालांकि यह आसान नहीं है लेकिन हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने इस मुहिम में शिद्दत से जुटे हुए हैं। सांसद थे तब भी और मुख्यमंत्री हैं तब भी।

हिंदू और मुसलमानों के बीच राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद नया नही था, लेकिन इस विवाद को हल करने के लिए दशकों पूर्व 1885 में गोरक्षपीठ के तत्कालीन महंत गोपालनाथ, योगिराज बाबा गंभीरनाथ और महंत ब्रह्मनाथ ने हिंदू और मुसलमानों में आपसी सामंजस्य स्थापित कर इस विवाद का हल निकालने की कोशिश की थी। इसमें अमीर अली नामक एक नामचीन मुस्लिम शख्सियत की भूमिका महत्वपूर्ण थी और विवाद लगभग सुलझा लिया गया था। दोनों पक्षों के बीच वर्ष 1885 में बनी सहमति में अयोध्या राममंदिर के विवादित ढांचे को हिंदुओं को सौंपने पर सहमति हो गई थी लेकिन इस पर अमल हो पाता कि इसी बीच भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और मुलमानों की अगुवाई कर रहे अमीर अली और हिन्दुओं का पक्ष रखने वाले रामचरणदास को बागी घोषित कर उन्हें फांसी दे दी गयी। गोरक्षपीठ ने ब्रिटिश काल में ही मुसलमानों को साथ लेकर श्रीराम मंदिर आंदोलन का शंखनाद कर दिया था।

गोरखपुर के शिक्षाविद डॉ. प्रदीप राव के सम्पादन में तीन खंडों में प्रकाशित 'राष्ट्रीयता के अनन्य साधक महंत अवेद्यनाथ' नामक पुस्तक में गोरक्षपीठ और रामजन्म भूमि आंदोलन की कई ऐतिहासिक जानकारियां साझा की गईं हैं। डॉ. प्रदीप राव के मुताबिक वर्ष 1855 से वर्ष 1885 तक महंत गोपालनाथ गोरक्षपीठाधीश्वर थे। वर्ष 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अवध क्षेत्र (वर्तमान में उत्तर प्रदेश) पर ब्रिटिश शासन का अधिपत्य हो गया था। अंग्रेजी राज के खिलाफ हिन्दू–मुसलमान तेजी से संगठित हो रहे थे। ऐसे समय में एक मुस्लिम क्रांतिकारी नेता अमीर अली ने अयोध्या–फैजाबाद के मुसलमानों को समझाया कि सम्राट बहादुरशाह जफर की राह पर चलते हुए उन्हें भी मिसाल पेश करनी चाहिए। अमीर अली ने एकता बनाने के लिए रामजन्मभूमि हिन्दुओं को सौंपने का प्रस्ताव रखा। जन्मभूमि

हस्तांतरण की पृष्ठभूमि तैयार करने में बाबा रामचरणदास की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन दोनों लोगों को तैयार करने के पीछे तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत गोपालनाथ के प्रयास को सदैव याद रखा जाएगा।

नाथ पंथ के जानकार डा. प्रदीप राव कहते हैं कि अमीर अली और बाबा रामचरण दास को फांसी दिए जाने की घटना ने आम लोगों को झकझोर कर रख दिया। गोरक्ष पीठ के आगे के श्रद्धेय महंतों ने लोगों को एकजुट रखते हुए यह प्रयास जारी रखा। मामला गंभीर होता जा रहा था और आस्था का यह विषय भारतीयों में तेजी से फैल रहा था। इस वजह से अंग्रेज भी किसी बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट से सशंकित थे। फिर यह बात, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया तक पहुंची। हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की नियति से ही महारानी विक्टोरिया ने बाबरी मस्जिद का नक्शा मंगवाया और परिसर के बीच में दीवार बना दी गई। मुसलमानों को भीतर नमाज पढ़ने और बाहर के चबूतरे पर हिंदुओं को पूजा पाठ करने का फरमान जारी कर दिया। अपनी पुस्तक में डॉ. राव कहते हैं कि महंत गोपालनाथ के बाद उनके शिष्य योगीराज बाबा गम्भीरनाथ और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत ब्रह्मनाथ ने भी राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए प्रयास जारी रखा। लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस इसे किसी न किसी बहाने लटकाती रही। लेकिन राम मंदिर की चाह हिंदू धर्मावलंबियों के बच्चे बच्चे में घर कर गया था इसलिए यह आंदोलन दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया।

आगे चलकर गोरक्षपीठ के ब्रम्ह लीन महंत अवेद्यनाथ ने इस आंदोलन की अगुवाई की जो न केवल ऐतिहासिक था,उसी वक्त राम मंदिर विरोधियों के मुंह की खाने की इबारत लिख उठी थीं। इस तरह जब हम राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में झांकेंगे तो बातें साफ तौर दिखेगी। एक, इस आंदोलन में गोरक्षपीठ के सहभोज से समरसता का योगदान और दूसरा अयोध्या से गोरक्षपीठ के पुश्त दर पुश्त का लगाव।

आज महंत अवेद्यनाथ के उत्तराधिकारी महंत योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में अयोध्या में श्रीराम मंदिर विश्व भर के हिंदू जनमानस के लिए समर्पण को तैयार है। आने वाले दिनों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी की ख्याति सनातन धर्म की राजधानी के रूप में होगी। ◆

मो. : 9918955583

जी–20 शिखर सम्मेलन और उत्तर प्रदेश

–सियाराम पांडेय 'शांत'

भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। अतिथि यहां देवतुल्य माना जाता है। उनके स्वागत–सत्कार में कोई कमी न हो, इसका ध्यान रखना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। कार्यक्रमों के आयोजन और तत्सम्बन्धी नवाचार में तो वैसे भी भारत का कोई जोड़ नहीं है। यूं तो भारत के हर राज्य अपनी खास विशिष्टताओं के साथ कार्यक्रम आयोजित करते और मेहमानों की आवभगत करते हैं लेकिन इन सबमें उत्तर प्रदेश का अंदाज़ और मिजाज़ दोनों ही अलग होता है। विश्व की प्रमुख आर्थिक व्यवस्था वाले 20 देशों की 200 से अधिक बैठकें भारत के सभी राज्यों के 55 प्रमुख शहरों में होनी हैं, जिसमें 11 बैठकें अकेले उत्तर प्रदेश के वाराणसी, आगरा, लखनऊ और नोएडा में आयोजित हैं। अधिकांश हो भी चुकीं। अब इक्का–दुक्का बैठकें ही होनी हैं। चूंकि यह सिलसिला नवंबर, 2023 तक चलना है, ऐसे में दुनिया के देशों पर अपनी सांस्कृतिक और वैचारिक छाप छोड़ना कौन नहीं चाहेगा? कहना न होगा कि ऐसा करने में उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों के मुकाबले बाजी मार ली है।

कुछ लोगों को यह आपत्ति हो सकती है कि मेहमानों से देश की गरीबी क्यों छिपाई जा रही है? ऐसे लोगों को रहीम का वह दोहा जरूर पढ़ना चाहिए जिसमें कहा गया है कि 'रहिमन निज मन की व्यथा मन ही राख्यो गोय। सुनि इठलैहैं लोग सब बांट न लैहैं कोय।' मित्रता और संबंध हमेशा समानता के बीच ही टिकते हैं। गरीब और अमीर के बीच मित्रता नहीं हो सकती। कृष्ण और सुदामा की मित्रता अपवाद हो सकती है लेकिन हमें द्रुपद और द्रोणाचार्य के संबंधों पर भी ध्यान देना होगा। गरीबी और अमीरी के बीच की रेखा दूरी बढ़ा तो सकती है, लेकिन उसे घटा नहीं सकती। सहानुभूति और आत्मीयता जीवन नदी के दो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जब तक देश–प्रदेश में इस सूत्र वाक्य पर अमल होता रहा, यह देश सोने की चिड़िया बना रहा। इसलिए भी, यह तो सोचना ही होगा कि बजाय मीन–मेख निकालने के हम सार्थक क्या कर सकते हैं?

यह सच है कि रोटी, कपड़ा और मकान सबकी जरूरत है लेकिन नैतिक उत्थान उससे भी बड़ी जरूरत है फिर वाराणसी तो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और अब तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, ऐसे में उस पर पूरी दुनिया की नजर है। काशी में किया गया नवाचार पूरी दुनिया पर असर डालता है। इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर समझते हैं। अतिथि सत्कार तो सभी करते हैं। सम्मेलन भी सभी करते हैं लेकिन उससे अतिथियों को ही नहीं, पूरे देश–पूरी दुनिया में सार्थक संदेश जाए, इसका विचार ही जी–20 शिखर सम्मेलन की विशेष उपादेयता रही है।

वाराणसी का पं. दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल सभागार जी–20 शिखर सम्मेलन के अनेक विमर्शों का गवाह रहा है। यहां अब तक पांच शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और छठवां जो होना है, उसमें देश भर के, यही नहीं, विदेशी धर्माचार्यों को सम्मिलित होना है, जो यह तय करेंगे कि राजसत्ता की रीति–नीति जन सापेक्ष कैसे हो सकती है?

पहली बैठक जी–20 देशों के कृषि मंत्रियों की हुई जिसमें 17 से 19 अप्रैल तक आधुनिक खेती पर चिंतन–मनन किया गया। 9 से 11 जून तक जी–20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें तेज विकास, उसकी चुनौतियों और विकासशील देशों की चिंताओं पर विचार–विमर्श हुआ। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जी–20 के देशों के विदेश मंत्रियों, उनके प्रतिनिधियों, नौ अतिथि देशों और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नुमाइंदों सहित 200 लोगों ने भाग लिया। विदेश नीति कैसी हो? देशों के बीच मधुर संबंधों का विकास कैसे हो, एक दूसरे देश की सीमाएं सुरक्षित कैसे रहें, इस पर मंथन अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बस इसे ही देखने का हर भारतवासी को इंतजार है। विदेश मंत्रियों की इस बैठक का अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली आगाज़ किया और उन्हें भारत की एक धरती, एक परिवार, एक लक्ष्य–सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा से अवगत कराया तो भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने उसे परवान तक पहुंचाने में महती भूमिका अदा की। उन्होंने वैश्विक आर्थिक सुधार की धीमी गति पर न केवल चिंता जताई बल्कि अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता और विश्वस्तरीय प्रयास की जरूरत पर जोर भी दिया। लंबे कर्ज संकट और ऊर्जा, खाद्य एवं उर्वरक सुरक्षा पर दबाव, श्रृंखला में बाधा को वैश्विक सुधार की मंद गति की वजह बताया तो जी–20 देशों के विदेशमंत्रियों को यह भी बताना नहीं भूले कि ऐसे में टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्रगति को रफ्तार देने के लिए भारत की महत्वाकांक्षी सात वर्षीय कार्य योजना क्या है? उन्होंने जी–20 गतिविधियों के लिए समन्वित एवं समावेशी खाका भी पेश किया।

भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। अतिथि यहां देवतुल्य माना जाता है। उनके स्वागत–सत्कार में कोई कमी न हो, इसका ध्यान रखना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। कार्यक्रमों के आयोजन और तत्सम्बन्धी नवाचार में तो वैसे भी भारत का कोई जोड़ नहीं है। यूं तो भारत के हर राज्य अपनी खास विशिष्टताओं के साथ कार्यक्रम आयोजित करते और मेहमानों की आवभगत करते हैं लेकिन इन सबमें उत्तर प्रदेश का अंदाज़ और मिजाज़ दोनों ही अलग होता है।

विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि इस खाका में डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत ढांचा, विकास के लिए डाटा को मजबूत करने, महिला नीत विकास के लिए निवेश और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए ऊर्जा संसाधनों के परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने दुनिया में बढ़ते अभूतपूर्व संकटों पर भी चिंता जाहिर की। साथ ही यह भी कहा कि मौजूदा युग दिन–ब–दिन अधिक परिवर्तनशील और अनिश्चित होता जा रहा है। इससे कई देशों पर बढ़ती महंगाई, बढ़ती ब्याज दर और सिकुड़ते राजकोष का प्रभाव पड़ा है। हमेशा की तरह, ऐसे समय में गरीब और कमजोर लोगों को खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। आवश्यकता है विकास के लिए डेटा एवं डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए साहसिक, निर्णायक कार्रवाई की, जो दुनिया भर में ज़मीनी स्तर पर नवाचारों के त्वरित आगाज के लिए आवश्यक है। इन नवाचारों के साथ भारत के अपने अनुभव ने आधे दशक से भी कम समय में हमारे समाज और शासन को बदल दिया है।

एक धरती के रूप में, हमें जरूरतमंदों के लिए एकजुटता प्रदर्शित करनी चाहिए। वास्तव में किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। संसाधन जुटाना चाहिए और हमारे प्रयासों को वहां निर्देशित करना चाहिए जहां उनकी सबसे

ज्यादा जरूरत है। हमें अपने दृष्टिकोणों को एकीकृत करने की जरूरत है, ऐसे सिस्टम का निर्माण करना चाहिए जो व्यापार–नापसंद पर भरोसा करने के बजाय तालमेल का लाभ उठाएं। एक भविष्य के लिए हमें अपने कार्यों के केंद्र में अपने नौजवानों की आकांक्षाओं को रखना होगा। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सब समानता, आपसी सम्मान एवं एकजुटता की बुनियाद पर आधारित हो।

17 से 20 अगस्त के बीच हुए युवा–20 शिखर सम्मेलन में जी–20 देशों, अतिथि देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े युवाओं ने प्रतिभाग किया। सम्मेलन के आगाज से पूर्व युवाओं को संबल देने वाले वीडियो का प्रसारण भी किया गया। इस दौरान न केवल माईगव की जानकारी दी गई,अपितु इसे सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच के रूप में भी स्थापित किया गया। इसमें कार्य का भविष्य, उद्योग, नवाचार, 21वीं सदी के कौशल, शांति, निर्माण और सुलह : युद्ध रहित युग की शुरुआत, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण, स्थिरता को जीने का ढंग बनाने, साझा भविष्य : लोकतंत्र और शासन, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भलाई और खेल, युवाओं के लिए एजेंडा तय किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि देश–दुनिया को आगे ले जाने का काम युवा ही कर सकते हैं। यह काम वे पहले भी करते रहे हैं। आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाषचंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई आदि जितने भी मनीषी हैं, वे सब युवा थे और आज भी देश–दुनिया के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व युवाओं के कंधे पर है। इस देश को पता है कि कोरे विकास से बात नहीं बननी है। विकास के साथ व्यक्ति का नैतिक और चरित्रवान होना भी जरूरी है। शिक्षा के साथ कार्य कौशल भी जरूरी है। स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता भी जरूरी है। पर्यावरण का संतुलन भी जरूरी है। मौजूदा समय युद्ध का नहीं, शांतिकामी बुद्ध का है। इस लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश में जितने भी शिखर सम्मेलन हुए, उनके अपने राजनीतिक, सामाजिक, तात्विक और दार्शनिक महत्व है। कुल मिलाकर इस सम्मेलन में जितने भी प्रस्ताव पास हुए हैं, जितने मुद्दों पर सहमतियां बनी हैं, अगर उन पर गौर किया जाए और अमल किया जाए तो दुनिया में अमन–चैन और विकास का वातावरण बनेगा। देश और प्रदेश की यह पहल इस धरती को और अधिक खूबसूरत बनाने में सहायक होगी। ◆

मो. : 7459998968

पर्यटकों को आकर्षित करता है उत्तर प्रदेश

–डॉ. सौरभ मालवीय

उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध राज्य है। इसके उत्तरी एवं पूर्वी भाग की ओर पर्वत हैं तथा पश्चिमी एवं मध्य भाग में मैदान हैं। दक्षिण का विन्ध्याचल क्षेत्र पठारी भू–भाग है। यह क्षेत्र पर्वतों, मैदानों एवं घाटियों से घिरा हुआ है। प्रदेश की जलवायु मुख्यतः उष्णदेशीय मानसून की है। चूंकि यह एक विशाल प्रदेश है, इसलिए समुद्र तल से ऊंचाई परिवर्तित होने के साथ–साथ इसमें भी परिवर्तन होता है। उत्तर प्रदेश में बहुत सी नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनमें गंगा, यमुना, रामगंगा, सरयू, शारदा, घाघरा, राप्ती, चम्बल, बेतवा, सिन्धु, केन, सोन, गोमती, तमसा, चन्द्रप्रभा, कर्मनासा, रिहन्द बेलन एवं घसांन आदि प्रमुख हैं।

पर्यटन प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाता है। इससे सरकार को राजस्व तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसके कारण विकास कार्यों को भी बढ़ावा मिलता है। उत्तर प्रदेश में कई ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल हैं। प्रदेश धर्म, संस्कृति एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। प्रयागराज हिन्दुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, क्योंकि यहां गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत संगम होता है जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहां कुम्भ मेले का आयोजन होता है। कुम्भ मेले के अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति बारहवें वर्ष तथा प्रयाग में दो कुम्भ पर्वों के बीच छह वर्ष के अंतराल में अर्धकुम्भ मेला भी लगता है। कुम्भ का शाब्दिक अर्थ घड़ा एवं मेले का अर्थ एक स्थान पर एकत्रित होना है। इसे अमृत उत्सव भी कहा जाता है।

खगोल गणनाओं के अनुसार कुम्भ मेला मकर संक्रान्ति के दिन प्रारम्भ होता है। उस समय सूर्य और चन्द्रमा, वृश्चिक राशि में और वृहस्पति, मेष राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिवस को अति शुभ एवं मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुलते हैं। इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु अमृत से भरा कुम्भ लेकर जा रहे थे कि असुरों ने आक्रमण कर दिया। अमृत प्राप्ति के लिए देव एवं दानवों में परस्पर बारह दिन तक निरंतर युद्ध

भारत में महाकुम्भ धार्मिक स्तर पर अत्यंत पवित्र एवं महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। महीने भर चलने वाले इस आयोजन में तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए टेंट लगा कर एक छोटी सी नगरी अलग से बसाई जाती है। यहां सुख–सुविधा की सारी वस्तुएं जुटाई जाती हैं। यह आयोजन प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरणों एवं पुलिस की सहायता से आयोजित किया जाता है। इस मेले में दूर–दूर के जंगलों, पहाड़ों और कंदराओं से साधु–संत आते हैं। कुम्भ योग की गणना कर स्नान का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। स्नान से पूर्व मुहूर्त में नागा साधु स्नान करते हैं। इन साधुओं के शरीर पर भभूत लिपटी रहती है, बाल लंबे होते हैं और वे मृगचर्म पहनते हैं। स्नान के लिए विभिन्न नागा साधुओं के अखाड़े भव्य रूप से शोभा यात्रा की भांति संगम तट पर पहुंचते हैं।

हुआ। देवताओं के बारह दिन मनुष्यों के बारह वर्ष के समान होते हैं। इसलिए कुम्भ भी बारह होते हैं। इनमें से चार कुम्भ पृथ्वी पर होते हैं तथा शेष आठ कुम्भ देवलोक में होते हैं। देव एवं दानवों के इस संघर्ष के दौरान अमृत की चार बूंदें गिर गईं। ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक तथा उज्जैन में गिरीं, जहां पर तीर्थस्थान बना दिए गए। तीर्थ उस स्थान को कहा जाता है जहां मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जहां अमृत की बूंदें गिरीं, उन स्थानों पर तीन–तीन वर्ष के अंतराल पर बारी–बारी से कुम्भ मेले का आयोजन किया जाता है। इन तीर्थों में प्रयाग को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां तीन पवित्र नदियों का संगम होता है।

भारत में महाकुम्भ धार्मिक स्तर पर अत्यंत पवित्र एवं महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। महीने भर चलने वाले इस आयोजन में तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए टेंट लगा कर एक छोटी सी नगरी अलग से बसाई जाती है। यहां सुख–सुविधा की सारी वस्तुएं जुटाई जाती हैं। यह आयोजन प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरणों एवं पुलिस की सहायता से आयोजित किया जाता है। इस मेले में दूर–दूर के जंगलों, पहाड़ों और कंदराओं से साधु–संत आते हैं। कुम्भ योग की गणना कर स्नान का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। स्नान से पूर्व मुहूर्त में नागा साधु स्नान करते हैं। इन साधुओं के शरीर पर भभूत लिपटी रहती है, बाल लंबे होते हैं और वे मृगचर्म पहनते हैं। स्नान के लिए विभिन्न नागा साधुओं के अखाड़े भव्य रूप से शोभा यात्रा की भांति संगम तट पर पहुंचते हैं।

वाराणसी में गंगा नदी के तट पर बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यह हिन्दुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यह मंदिर शिव और पार्वती का आदि स्थान है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। शिवालिक की पहाड़ियों में शाकम्भरी शक्तिपीठ तीर्थ है। सरयू नदी के तट पर भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या की पावन नगरी है। मथुरा श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है तथा वृन्दावन श्रीकृष्ण की मनमोहक लीलाओं का पवित्र स्थल है। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में मां पाटन देवी का मंदिर है। राप्ती नदी के तट पर श्रावस्ती बौद्धों का तीर्थ स्थल है। यहां बौद्धों का प्राचीन तीर्थ स्थल सारनाथ भी

है। मान्यता है कि ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इसी स्थान पर दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन भी इसी स्थान से प्रारम्भ किया था। कुशीनगर भी बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिए थे। ललितपुर जिले का देवगढ़ जैन समुदाय का तीर्थ स्थल है।

आगरा में यमुना नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है। यूनेस्को ने वर्ष 1983 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया था। यूनेस्को के अनुसार ताजमहल भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की

विरासत की सार्वभौमिक प्रशंसनीय कृतियों में से एक है। यह मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक माना जाता है। भारत में सबसे अधिक पर्यटक यहीं पर आते हैं। इससे सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अनेक मस्जिदे, इमामबाड़े, दरगाहें एवं गुरुद्वारें भी हैं।

प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत सरकार धार्मिक स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार के बजट 2023–24 में पर्यटन विकास एवं संस्कृति धर्मार्थ कार्य पर विशेष बल दिया गया है। बजट में 237 करोड़ रुपये पर्यटन के विकास के लिए आवंटित किए गये हैं। वर्ष 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2022 में 24 करोड़ 87 लाख से अधिक पर्यटक आए। इनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 24 करोड़ 83 लाख है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या चार लाख 10 हजार से अधिक रही। प्रदेश सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए आधारभूत संरचाओं में वृद्धि की है। इससे पर्यटन वृद्धि के राजस्व में बढ़ोतरी होने के साथ–साथ अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021–2022 के बजट में अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों की विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त विन्ध्यांचल एवं नैमिषारण्य में स्थल विकास के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया गया। चौरी चौरा महोत्सव के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। श्रीराम जन्म भूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग बनाने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण के लिए आठ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं के लिए चार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पर्यटन हम सबके जीवन को एक नया वातावरण देता है। जीवन जीने की नई विधा हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उत्साह और उमंग भरने के लिए पर्यटन की अपार संभावनाओं को हम सबके सम्मुख लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के दो प्रकार हैं– एक परम्परागत एवं दूसरा मनोरंजन। परम्परागत पर्यटन में वे लोग सम्मिलित हैं, जो प्रत्येक वर्ष यहां मंदिरों एवं तीर्थों के दर्शन करने आते हैं, जबकि मनोरंजन पर्यटन में वे लोग सम्मिलित हैं जो परिवार के साथ मनोरंजन के लिए पर्यटन करते हैं। उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक पर्यटन के मामले में सबसे धनी एवं सघन है। यहां एक साल में तीस करोड़ श्रद्धालुओं ने पर्यटन किया।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना प्रारम्भ किया। उन्होंने अपने प्रथम कार्यकाल में अयोध्या, काशी एवं मथुरा सहित लगभग सभी धर्मनगरियों में नए कार्यक्रम आरम्भ किए। इसके अंतर्गत धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों का कायाकल्प किया गया। अनेक स्थानों में यह कार्य पूर्ण हो चुका है और बहुत से स्थानों पर यह कार्य चल रहा है और पूर्ण होने वाला है। उन्होंने अपने द्वितीय कार्यकाल में भी अपने इस कार्यक्रम को जारी रखा।

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विधानसभा स्तर पर एक पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा। यह कार्य मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत किया जाएगा।

निःसंदेह यदि प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाए, तो यह रोजगार सृजित करेगा।

इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकेगा तथा गरीबी उन्मूलन में भी यह सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो सार्थक सिद्ध होगा। ◆

मो. : 8750820740

एक जिला एक उत्पाद से अन्त्योदय तक

—अशोक सिन्हा

समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से पिछड़े, गरीब, कमजोर वर्ग का उत्थान हो सके, इस निमित्त सबसे आख़िरी व्यक्ति के उत्थान का प्रयास ही अन्त्योदय है। स्व. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के मूल में अन्त्योदय है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के द्वारा कौशल सामाजिक एवं आर्थिक विकास के द्वारा कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करते हुए व्यक्ति का सामाजिक स्तर से ऊपर उठाना इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। सबसे गरीब व्यक्ति को सहायता कैसे पहुंचे इसके लिये अनेक सामाजिक एवं राजनैतिक संगठन सक्रिय प्रयास करते रहते हैं। सरकार एवं शासन व्यवस्था भी अपनी ओर से अनेक योजनाएं चलाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस दिशा में गम्भीरता से प्रयास हुए हैं। यह कहना नितान्त उचित होगा। भारत की समृद्धि में लघु एवं कुटीर उद्योगों का सर्वाधिक योगदान रहा है। जब प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर था और प्रत्येक गांववासी हुनरमंद होता था तब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत का वैभव विश्व में विख्यात था। सम्पूर्ण विश्व से भारत में व्यापारी आकर व्यापार करते थे। ढाका मलमल, केरल के मसाले, कन्नौज का इत्र और एक से

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक जिला एक उत्पाद योजना को जनवरी 2018 से लागू किया है, जिसकी भारत ही नहीं विश्व में चर्चा हो चुकी है। राज्य में इससे लाखों युवकों को काम मिला है। तथा राज्य सरकार की ओर से 5 वर्षों में हुनरमंद व्यक्तियों को 26000 रुपये की सहायता भी दी जा रही है। हुनर हाट लगाकर बाजार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक जनपद के हस्तकला, हस्तशिल्प एवं विशिष्ठ हुनर को सुरक्षित एवं विकसित करना है। इससे सम्बंधित जनपद में रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य पूरा हो रहा है। जनपद में विशिष्ठ उत्पाद के लिए कच्चामाल, डिजाइन, प्रशिक्षण, तकनीकी और बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

बढ़कर कृषि उत्पाद भारत की पहचान होते थे। पूरा विश्व इन वस्तुओं से सम्मोहित था। उस समय अन्त्योदय की आवश्यकता नहीं थी। कालान्तर में जब भारत में आक्रान्ता आये, देश गुलाम हुआ तब लूट और बेकारी बढ़ी। औद्योगिकीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप ही बदल दिया। गांव में हस्तशिल्प का ह्रास हुआ और परम्परागत उद्योग–धन्धे चौपट हो गये। यह स्थिति गरीबी बढ़ाने वाली हुई। कालांतर में समाज में विभाजन हुआ। श्रम का महत्त्व कम होने लगा और बाबूगिरी, अफसरशाही सम्मानसूचक माने जाने लगे। कामगार, कृषक, मजदूर वर्ग द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाने लगा। बेरोजगारी बढ़ी और देश में गरीबी बढ़ी। यदि विश्व का सिरमौर बनना है तो उसे समाज के अन्तिम पायदान पर बैठे हर नौजवान को काम देने का अवसर प्रदान करना होगा तथा हर हुनर को हाट प्रदान करना होगा। इस प्रयास से केवल और केवल सरकारी

नौकरी या नौकरी करने की तीव्र दबावयुक्त भावना पर रोक लगेगी और अनावश्यक बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा। हाथ को जब काम मिलेगा तब हुनर विकसित होगा और देश की वास्तविक प्रगति होगी। उत्पादन और बाजार के मध्य समन्वय भी बनेगा तथा निर्यात भी बढ़ेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक जिला एक उत्पाद योजना को जनवरी 2018 से लागू किया है, जिसकी भारत ही नहीं विश्व में चर्चा हो चुकी है। राज्य में इससे लाखों युवकों को काम मिला है। तथा राज्य सरकार की ओर से 5 वर्षों में हुनरमंद व्यक्तियों को 26000 रुपये की सहायता भी दी जा रही है। हुनर हाट लगाकर बाजार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य

उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक जनपद के हस्तकला, हस्तशिल्प एवं विशिष्ठ हुनर को सुरक्षित एवं विकसित करना है। इससे सम्बंधित जनपद में रोजगार सृजन और आर्थिक संमृद्धि का लक्ष्य पूरा हो रहा है। जनपद में विशिष्ठ उत्पाद के लिए कच्चामाल, डिजाइन, प्रशिक्षण, तकनीकी और बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे अत्यन्त छोटे स्तर पर अच्छा लाभ मिलने के साथ परिवार व घर छोड़कर अन्यत्र भटकना नहीं पड़ता है। छोटे–छोटे गाँव भी भारत में अपनी पहचान बना रहे हैं। नई तकनीक से श्रेष्ठ उत्पादन होने लगे हैं और सहज अनुदान, विपणन की सुविधा तथा प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सफलता को देखरकर देश के 17 राज्यों में 54 इनक्यूबेशन केन्द्र खोले गये हैं। 35 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के 707 जिलों को

केन्द्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा एक जिला एक उत्पाद के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। 17 राज्यों में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू–कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं उत्तराखण्ड शामिल हैं। इन सभी राज्यों में 470 जिला स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र बने हैं।

उपरोक्त उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। यह उत्पाद एक ब्राण्ड बने हैं और यह ब्राण्ड यू.पी. की पहचान होगी। इस योजना के अन्तर्गत लघु, मध्यम और नियमित उद्योगों को मदद प्रदान की जा रही है। अनुदान व्यवस्था सामान्य सुविधा केन्द्र, विपणन सुविधा, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। लक्ष्य 25 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार व नौकरी देने का लक्ष्य है और राज्य का सकल घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि मिल रही है। पारम्परिक उद्योगों की तेजी से स्थापना हो रही है और छोटे–छोटे गांवों का नाम विदेशों में भी पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का भी प्रसार हो रहा है। जी–20 के राष्ट्राध्यक्षों को ओ.डी.ओ.पी. देकर प्रधानमंत्री ने भी उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया।

विदेशी मेहमानों को वाराणसी की गुलाकी मीनाकारी कपलिंग्स, गणेश प्रतिमा, बांदा का शजर स्टोन कपलिंग्स, कन्नौज का इत्र, लखनऊ का चिकनकारी वस्त्र, मुरादाबादी पीतल बाउल सेट, खुर्ज़ा के कप प्लेट्स, सीतापुर के आसन, बरेली के जरी जरदोज़ी से बने उपहार, दिये गये जो बहुत पसंद किए गए। अब उ.प्र. के उपहार देश–दुनिया के बड़े निवेशकों के ऑफिस व घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। सरकार के रोड शो इवेंट में अपनी मिट्टी–संस्कृति की सुगंध तभी महका रही है। योगी सरकार लखनऊ के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में इस प्रयास की विश्वव्यापी चर्चा की गई तथा प्रत्यक्ष स्टाल लगे जहाँ दर्शकों की भारी भीड़ जमा थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में यह उल्लेख हुआ है कि भारत में 13.5 करोड़ जनसंख्या को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर विश्व से गरीबी दूर करने का विशेष कार्य किया गया है जो पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी अधिक है। यही है अन्त्योदय अब धरातल पर काम दिखने लगा है। यदि देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, संस्कृति प्रथम, व्यक्ति की गरिमा और श्रम का सम्मान प्रथम इस भावना से देश के राजनेता, श्रमिक, नागरिकगण कार्य करेंगे तो अन्त्योदय का सूरज अवश्य चमकेगा। भारत की गरिमा बढ़ेगी और राष्ट्र की विश्व को दिशा देने की क्षमता बढ़ेगी। भारती अति प्राचीनकाल से अपनी श्रमशक्ति, मानव कल्याण और विश्व को एक कुटुम्ब मान कर सर्वहितकारी भावना से कार्य करने के लिए प्रसिद्ध रहा है। पुनः सांस्कृतिक आजादी और पुनर्जागरण का काल आया है। पं. दीनदयाल उपाध्याय के स्वप्न को साकार और सार्थक बनाने का यह अवसर अवश्य देश का मान–सम्मान बढ़ाने वाल सिद्ध होगा। ◆

मो. : 9453140038

निवेश से बदलता परिवेश

राइट वे पर यूपी

—सुयष मिश्रा

उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य के रूप में विख्यात था। बढ़ता माफियाराज और कानून व्यवस्था सरकार की बड़ी चुनौती थी। व्यवसायी यूपी में इन्वेस्ट करने से कतराते थे। लोगों का कहना था कि यूपी का विकास होना मुश्किल है। कानून–व्यवस्था में सुधार नामुमकिन–सा हो गया था। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था। ऐसे में साल 2017 में जब यूपी में योगी सरकार बनी तो उम्मीदों के अनुरूप सार्थक परिणाम भी आए। पिछले 5–6 सालों के भीतर यूपी ने अपनी नई पहचान स्थापित की है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता से है। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल के परिणाम नज़र आ रहे हैं। अब कहा जा सकता है कि यूपी राइट वे पर है। आज सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च कर रही है और हर वर्ष इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी में निवेश के नए मौके बन रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि में भी निवेश के अनेक अवसर हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तक़रीबन 9 हजार स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। यह आंकड़ा अभी और आगे बढ़ेगा। युवाओं का रुझान स्टार्टअप की ओर बढ़ा है। प्रमुख

सचिव औद्योगिक विकास नरेंद्र भूषण के मुताबिक स्टार्टअप नीति 2020 में वर्ष 2025 तक 10 हजार स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य है। जो कि कुछ महीनों में ही पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र स्टार्टअप स्थापित करने के मामले में नंबर एक पर है। हमारी कोशिश है कि स्टार्टअप में उत्तर प्रदेश को नंबर वन की पोजीशन पर लाया जाए।

कोविड–19 के चलते जब देशभर में लॉकडाउन लगा तो अन्य राज्यों से तकरीबन 3.5 मिलियन से अधिक प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश लौटे। ऐसे में इन श्रमिकों को प्रदेश में रोज़गार दिलाना बड़ी चुनौती थी। साल 2017 में यूपी में पूर्ण बहुमत से आई योगी सरकार के लिए यह कठिन समय था। प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के हिसाब से रोज़गार का सृजन करना आसान नहीं था। ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने 8 जुलाई को उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी ताकि नए व्यापारिक विचारों का पोषण किया जा सके। इसका उद्देश्य उद्यम के क्षेत्र में नए विचारों और सोच वाले युवाओं को बढ़ावा देना था ताकि छोटे उद्यमों से इन प्रवासी श्रमिकों को ऐसी नौकरियां प्रदान की जा सकें जो उनके वर्क–प्रोफाइल के अनुरूप हों और विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा भी मिल सके। इससे पहले 20 मई को, सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड भी लॉन्च किया था जिसे लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (एसडीबीआई) द्वारा प्रबंधित किया गया। राज्य सरकार द्वारा इस फंड की स्थापना उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्ट–अप नीति 2017 के तहत की गई है।

उत्तर प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (यूपीजीआईएस) के जरिए देश–दुनिया से यूपी में 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव हासिल कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में बड़ी लकीर खींच दी है। किसी भी दूसरे प्रदेश में निवेश के आए प्रस्तावों का रिकार्ड तोड़ योगी ने दिखा दिया कि असीम संभावनाओं का उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बनने में पूरी तरह सक्षम है। यही नहीं उच्च अधिकारियों का कहना है कि अभी निवेश के और बढ़ने की उम्मीद है। वह दिन दूर नहीं जब यूपी भारत की ग्रोथ को ड्राइव करेगा। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर जाना जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। स्टार्टअप में यूपी भारत में नंबर वन की पोजिशन पर होगा। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश को अगले पांच सालों में एक मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य है।

उत्तर प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (यूपीजीआईएस) के जरिए देश–दुनिया से यूपी में 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव हासिल कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में बड़ी लकीर खींच दी है। किसी भी दूसरे प्रदेश में निवेश के आए प्रस्तावों का रिकार्ड तोड़ योगी ने दिखा दिया कि असीम संभावनाओं का उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बनने में पूरी तरह सक्षम है। यही नहीं उच्च अधिकारियों का कहना है कि अभी निवेश के और बढ़ने की उम्मीद है। वह दिन दूर नहीं जब यूपी भारत की ग्रोथ को ड्राइव करेगा। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर जाना जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। स्टार्टअप में यूपी भारत में नंबर वन की पोजीशन पर होगा। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश को अगले पांच सालों में एक मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में साल 2020 से पहले तक स्टार्टअप को उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत संचालित किया जा रहा था, जोकि मुख्य रूप से आईटी सेक्टर पर केंद्रित थी। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ यहां के 1800 से अधिक स्टार्टअप उद्यम पंजीकृत थे। चूंकि इस मौजूदा स्टार्टअप ढांचे ने अन्य क्षेत्रों की विभिन्न जरूरतों को पूरा नहीं किया, इसलिए राज्य सरकार पहले से ही इस मुद्दे को हल करने के लिए एक व्यापक नीति बना रही थी। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लाई गई स्टार्टअप नीति के चलते राज्य में स्टार्टअप की संख्या में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है। राज्य में अब तक 9000 स्टार्टअप पंजीकृत हो गए हैं, जल्दी ही इनकी संख्या बढ़कर दस हजार के पार हो जाएगी। स्टार्टअप नीति से प्रभावित निवेशक यूपी में लगातार निवेश कर रहे हैं। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेटर और एक्सीलेंस सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। सबसे अधिक 1200 से अधिक स्टार्टअप नोएडा में स्थापित किए गए हैं, जबकि गाज़ियाबाद में 533, लखनऊ में 500 और बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र के जिलों में कुल 1,219 से अधिक स्टार्टअप स्थापित किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कई निवेशक यूपी में अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। राज्य में स्टार्टअप की संख्या और अधिक करने के लिए प्रदेश के हर जिले में इनक्यूबेटर की स्थापना करने का फैसला किया गया है। इसके तहत उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग में इन्क्यूबेटर की स्थापना किए जाएंगे। राज्य सरकार का मत है कि इन्क्यूबेटर और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना से जहां प्रदेश में एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप देश को स्टार्टअप हब बनाने में अहम भूमिका निभा सकेंगे। औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों की मानें तो राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रेजेंटेशन में लगातार नए स्टार्टअप की स्थापना को बढ़ावा देने पर जोर

स्टार्टअप नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं :

1. **नई स्टार्टअप नीति अधिसूचना की तारीख से पांच साल तक के लिए लागू है यह 10,000 से अधिक स्टार्टअप के निगमीकरण में भी मदद करेगी।**
2. **यह नीति एक सक्षम कारोबारी परिवेश को बढ़ावा देगी और उत्कृष्टता का एक अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करेगी।**
3. **यह नीति लखनऊ में देश का सबसे बड़ा इन्क्यूबेशन हब भी स्थापित करेगी।**
4. **यह नई स्टार्टअप नीति चिकित्सा और स्वास्थ्य, कृषि, खादी, ऊर्जा, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन आदि के विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को एक समान महत्व देगी।**
5. **यह नीति अतिरिक्त ऊष्मायन (इन्क्यूबेशन) और वित्तीय सहायता के साथ बुंदेलखंड और पूर्वांचल के पिछड़े क्षेत्रों में भी स्टार्टअप उपक्रमों को विशेष बल प्रदान करेगी।**

दिया जा रहा है ताकि दस लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने और स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को नंबर वन बनाए जाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जल्दी ही राज्य में हर मंडल स्तर और हर जिले में एक इन्क्यूबेटर सेंटर बनाए जाएंगे, कुल एक सौ नए इन्क्यूबेटर सेंटर की स्थापना की जाएगी। इन इन्क्यूबेटर सेंटर के जरिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग या अन्य जरूरी सेवाएं देकर नई स्टार्टअप कंपनियों को विकसित करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों का दावा है कि यूपी सरकार की स्टार्टअप नीति 2020 नए स्टार्टअप स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को भा रही है। इस नीति में नया स्टार्टअप स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को जो प्रोत्साहन सरकार दे रही है, उसके चलते ही 9 हजार से अधिक स्टार्टअप स्थापित किए जा चुके हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ हैं। ये स्टार्टअप सूचना प्रौद्योगिकी, सर्विस सेक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, टेक्सटाइल क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब इसमें और इजाफा होगा क्योंकि जल्द ही राज्य में हर मंडल और हर जिले में इन्क्यूबेटर की स्थापना की जाएगी। अभी राज्य के 15 जिलों में ही 47 इन्क्यूबेटर स्थापित हैं। राज्य के हर जिले में स्थापित किए जाने वाले इन्क्यूबेटर के जरिए प्रबंधन प्रशिक्षण या अन्य जरूरी सेवाएं प्रदान करके नई स्टार्टअप कंपनियों को विकसित करने में मदद मिलेगी। इनके जरिये लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने सौ दिनों में दो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है, इनमें से एक ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी कानपुर में स्थापित किया जाएगा। नई स्टार्टअप नीति यूपी में एक कुशल कारोबारी माहौल को बढ़ावा दे रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य, कृषि, खादी, ऊर्जा, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन आदि के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित स्टार्टअप यूपी को नई दिशा दे रहे हैं। इसका नतीजा है कि प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप देश को स्टार्टअप हब बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और जल्दी ही नए स्टार्टअप इस तस्वीर को बेहतर कर सकते हैं। ◆

मो. : 8924856004

पंचायती राज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका

—डॉ. नन्द किशोर साह

भारत के आधुनिक इतिहास में 24 अप्रैल, 1993 को पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्राम स्तर पर मौन क्रांति का सूत्रपात हुआ है। पंचायती राज प्रणाली को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए सरकार के प्रयासों के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। गांव की तस्वीर बदल रही है। पंचायतों के माध्यम से उनको उनका वांछित हक मिल रहा है। राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में वंचित परिवार के लोग सीधे जुड़ रहे हैं। यह हमारे समाज और राजनीतिक तंत्र के लिए एक सुखद संदेश है। दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को वाजिब हक मिलना सही मायने में पूज्य बापू के सपनों का साकार रूप है। गांव गरीब किसान और पंचायतों को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देशभर में 753 लाख गरीब परिवार की महिलाओं को समूह से जोड़ा गया है, जो मौन आंदोलन के रूप में उभर रहा है।

महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण के चलते आज वे विभिन्न क्षेत्र में आगे बढ़ रहीं हैं और खुद के साथ दूसरों को भी आगे बढ़ा रही है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 72.69 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 693663 सहायता समूहों, 42060 ग्राम संगठनों एवं 2356 संकुल स्तरीय संघ से जोड़ा गया है। सभी समूह की महिलाओं को लाखपति बनाने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। महिलाएं इसके माध्यम से पंचायती राज में अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज़ कराई है। इनकी सक्रियता के कारण ही कोविड–19 के बावजूद

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि ''गांव की आज़ादी के बगैर भारत की आज़ादी अधूरी है।'' समाज को अपने बारे में स्वयं सोचने स्वयं निर्णय लेने और स्वयं क्रियान्वित करने की आज़ादी है। उन्होंने अपने हरिजन पत्र में लिखा है कि ''सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे हुए 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता अपितु इसका क्रियान्वयन प्रत्येक गांव के ग्रामीण जनों द्वारा होना चाहिए।'' गांधी जी की इस कथन का आज व्यावहारिक रूप नजर आने लगी है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं यानि पंचायती राज लोकतंत्र को गांव की ज़मीन तक ले जाने का सबसे सशक्त माध्यम है जिससे आधी आबादी को सत्ता में भागीदारी का अवसर प्राप्त हो। इसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है।

पंचायत चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। निःसंदेह आने वाले दिनों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के 403 सदस्यों वाली विधानसभा में महिलाओं की संख्या 47 है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि ''गांव की आज़ादी के बगैर भारत की आज़ादी अधूरी है।'' समाज को अपने बारे में स्वयं सोचने स्वयं निर्णय लेने और स्वयं क्रियान्वित करने की आज़ादी है। उन्होंने अपने हरिजन पत्र में लिखा है कि ''सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे हुए 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता अपितु इसका क्रियान्वयन प्रत्येक गांव के ग्रामीण जनों द्वारा होना चाहिए।'' गांधी जी के इस कथन का आज व्यावहारिक रूप नजर आने लगा है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं यानि पंचायती राज लोकतंत्र को गांव की जमीन तक ले जाने का सबसे सशक्त माध्यम है जिससे आधी आबादी को सत्ता में भागीदारी का अवसर प्राप्त हो। इसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है।

सदियों से चली आ रही पंचायती राज की अवधारणा को राष्ट्रपिता से प्रेरणा लेकर ही इसे दिशा प्रदान किया गया है। यह सही नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था अचानक अस्तित्व में आ गई। इसके पीछे इसकी की मेहनत, प्रयास और राजनीतिक इच्छाशक्ति दूसरे रूप में कहा जाए तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1958 से आरंभ हुआ। ग्राम पंचायतों के वर्तमान स्वरूप का श्रेय बलवंत राय मेहता समिति को जाता है जिसने त्रिस्तरीय पंचायती संरचना बनाई और इसके आधार पर 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का श्रीगणेश किया। देश में पंचायती राज सुदृढ़ व विकसित करने के उपाय सुलझाने के लिए समय–समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया।

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को संवैधानिक दर्ज़ा प्रदान करते हुए बुनियादी विकास के जिस 29 विषयों का अनुरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। इन दायित्वों के निर्वहन में पंचायतों में कमजोर तबके एवं महिलाओं की छुपी ऊर्जा द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की गई है। समाज को जागरूक, जुझारू एवं मेहनतशीलल बनाने का प्रयास किया गया है। पंचायतों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं को सत्ता में भागीदार बनाया गया है। महिला सशक्तीकरण का प्रयास किया गया है। आज ग्रामीण महिलाओं का दखल चूल्हे चौके तक सीमित न रहकर राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों के नीति निर्माण में अहम बनता जा रहा है। इसको एक बेहतरीन शुरुआत कहा जा सकता है। सही मायने में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भारत के विकास का नया स्वरूप प्रदान किया जा रहा है।

भारत में पंचायती राज की अवधारणा नई नहीं है किंतु वर्तमान परिस्थितियों में उसके उद्देश्य ज्यादा नवीन एवं महत्वपूर्ण हो गए हैं। सामाजिक–आर्थिक न्याय की अवधारणा को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था जिन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ी, उनमें एकता और विकास दो अहम बिंदु थे। ग्रामीण समाज की जिस एकता, सांप्रदायिक सौहार्द, सहभागिता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सत्ता में भागीदारी, आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की भावना को लाने का प्रयास किया गया है, उसमें पंचायती राज व्यवस्था अभी एक सीमा तक सफल हुई है।

संविधान में किया गया महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण ने समाज को एक नई दिशा दिया क्योंकि 33% से 50% आरक्षण ने महिलाओं को चूल्हे से निकाल कर चौपाल में पहुंचाने का काम किया। यह एक क्रांतिकारी कदम है। भारत के दूरदराज गांवों की महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का शुभ अवसर प्रदान किया। ग्रामीण स्तर में महिलाओं को स्थानीय शासन में भागीदारी का एक बड़ा लाभ यह हुआ कि उसने देश भर में विधानसभा और संसद में भी महिलाओं के आरक्षण के बहस भी छेड़ दी। किसी भी समाज का सामाजिक और राजनीतिक विकास महिलाओं के विकास के बिना संभव नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि महिलाएं राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में बने तो उनका शिक्षित एवं जागरूक होना आवश्यक है। महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक–आर्थिक व राजनीतिक जीवन में समान अवसर उपलब्ध कराना होगा।

गांधीजी मानते थे कि सच्चा लोकतंत्र वही है जो निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी पर आधारित हो। पंचायती राज व्यवस्था में नए खून का संचार 73वां संविधान

संशोधन के बाद हुआ, जिससे पंचायती संस्थाओं के स्वरूप और कार्यप्रणाली ही नहीं बल्कि उनकी संरचना और कुशलता में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। पंचायती राज संस्थाओं में हर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देकर निश्चित रूप से इनको ग्राम विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है।

उपभोक्तावाद ही सबसे बड़ी समस्या है जिससे पूरी दुनिया तबाह है। नदियां, वृक्ष समेत पूरे पर्यावरण को यह लील गया है। गांधी ने ताउम्र इसी उपभोक्तावाद का विरोध किया। गांधी उद्योगों या इनके यंत्रीकरण के विरुद्ध नहीं थे। उनका मानना था कि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। वह बड़े उद्योगों के बजाय कुटीर उद्योग के हिमायती थे। वह चाहते थे कि बड़े–बड़े कारखाने के बजाय देश के विशाल जन समुदाय द्वारा अपने घरों में चीजें उत्पादित की जाए। आज किसानों को बचाना जरूरी है। वे मजबूत होंगे, तो गांव मजबूत होंगे। जिससे शहरों में भीड़ कम होगी और कई समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर वहां की महिलाओं की स्थिति है। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए, जहां वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सके। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था ''नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्भर करती है।'' नारी प्रकृति की बेटी है एवं सृष्टि के सौंदर्य की सर्वश्रेष्ठ कृति है।

पंचायती राज के संचालन में आ रही समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराना भी प्रासंगिक होगा। वर्ष 1959 के पश्चात पंचायती राज अपने क्रमिक विकास को प्राप्त करता आ रहा है जबकि सामाजिक एकता के स्वरूप की संकल्पना जो गांधी जी ने देखी थी वह आज पंचायतों में दलीय राजनीति के कारण कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है। राजनीति जिसको विकास का एक सशक्त हथियार माना जाता है, वही गांव में दलगत राजनीति को बढ़ावा देकर वैमनस्य की भावना उत्पन्न कर रहा है। दूसरी ओर, महिला अधिकारों का उपयोग उनके पति, पिता, भाई या किसी रिश्तेदार पुरुष द्वारा ही किया जा रहा है। इस पर संस्थागत प्रयास करके ही बापू की ग्रामोदय से भारत उदय और ग्राम स्वराज की परिकल्पना को ज़मीनी हक़ीकत में बदल सकते है। ◆

मो. : 9934797610

आकांक्षी नगर योजना से शहरों का बदलता रूपरंग

–सुरेन्द्र अग्निहोत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृष्टिकोण से रूप–रंग ऐसा हो जाएगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रारम्भ की जा रही आकांक्षी नगर योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किए गए दिशा–निर्देशों को स्वीकृति प्रदान करने के साथ विकेन्द्रीकरण के तहत योजना के दिशा–निर्देशों में भविष्य में आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन एवं संशोधन हेतु मंत्रिपरिषद ने नगर विकास विभाग के मंत्री को अधिकृत कर राह आसान कर दी है।

आजादी के अमृतकाल यानि 75 साल बाद एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रंग और रूप बदल रहा है। इसके बढ़ते दायरे और इसमें हो रहे नए–नए प्रयोग शहर को कैसे और कहा तक रिस्पांसिबिल टूरिज्म के लिए आवश्यक योग्यता हासिल कर सके। आकांक्षी नगर योजना से शहर का माहौल सुरक्षित और स्वस्थ हो साथ ही सफाई के लिए वहां रहने वाला हर व्यक्ति इस जिम्मेदारी का निर्वाह करें। त्वरित विकास को गति मिल सके, तंगी से जूझ रहे नगरीय निकाय को बूस्टर डोज की तरह आकांक्षी नगर योजना शहरी इलाकों यानि नगरीय निकायों में सुविधाओं का विस्तार का वायस बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात रूपी आकांक्षी नगर योजना को मंत्री परिषद से स्वीकृत कराकर शहर के विकास के लिए अनुपम भेट दी है। शहरों का वर्तमान स्वरूप ही बदल जायेगा। विकास की नई संरचनाएं शहर की फिज़ा में नया रंग भरेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृष्टिकोण से रूप–रंग ऐसा हो जाएगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रारम्भ की जा रही आकांक्षी नगर योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किए गए दिशा–निर्देशों को स्वीकृति प्रदान करने के साथ विकेन्द्रीकरण के तहत योजना के दिशा–निर्देशों में भविष्य में आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन एवं संशोधन हेतु मंत्रिपरिषद ने नगर

विकास विभाग के मंत्री को अधिकृत कर राह आसान कर दी है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जनप्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं, एवं आमजन मानस और अपने विजन के साथ जो खाका तैयार किया है उसे धरातल पर उतारने, समस्त वार्डों के समुचित मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास कर रहे है।

20 हजार से 01 लाख जनसंख्या के नगर निकायों के संसाधनों के आदर्श रूप में प्रयोग, आर्थिक विकास के अवसरों में वृद्धि कर पलायन को रोकने तथा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने में बड़ा योगदान देने हेतु तैयार किये जाने के उद्देश्य से सबसे पिछड़े 100 नगरीय निकायों हेतु आकांक्षी नगर योजना की संकल्पना की गयी है।

आकांक्षी नगर योजना का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में चल रही सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति व सतत विकास प्राप्त करना है। योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था उपलब्ध है। इस योजना में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार मा. सांसद/विधायक निधि, अन्य संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर कन्वर्जेन्स के माध्यम से परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।

03 सी (कनवर्जेन्स, कोलेबरेशन, कम्प्टीशन) का अनुप्रयोग कर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

योजनान्तर्गत स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन के माध्यम से आकड़ों का संकलन एवं उनका अनुप्रयोग करते हुए अनुश्रवण, वित्तीय भौतिक प्रगति, गैप एनालिसेस एवं गुणवत्ता सुधार किया जाएगा। आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत के तहत कुल 762 नगरीय निकायों में से 100 आकांक्षी नगरीय निकायों का चयन नीति आयोग द्वारा निर्धारित 16 पैरामीटर्स के आधार पर किया जाएगा। चयनित 100 नगर निकायों में यह योजना 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी, परन्तु इनकी मॉनीटरिंग डॅशबोर्ड के माध्यम से 31 मार्च, 2028 तक चलती रहेगी।

31 मार्च, 2026 के पूर्व वर्तमान चयनित 100 नगर निकायों के स्थान पर अन्य 100 नगर निकायों का चयन किया जाएगा तथा वहां यह योजना 01 अप्रैल, 2026 से आगे के 02 वित्तीय वर्षों तक लागू रहेगी। इसके उपरांत यह नगर निकाय आत्मनिर्भर रूप से कार्य करेंगे।

योजना के अन्तर्गत चयनित 100 आकांक्षी नगर निकायों में मुख्यमंत्री शहरी फेलोज के माध्यम से रणनीति तैयार करने, आकड़ों का संकलन एवं राज्य सरकार के साथ समन्वय, अनुश्रवण एवं अभिलेखों के रख–रखाव सम्बन्धी कार्य किए जाएंगे।

इस योजना के सुचारु रूप से कियान्वयन हेतु योजना का सतत अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा तथा योजना के तहत आकांक्षी शहरी निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन के आधार पर निकायों को प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जायेगी।

आकांक्षी नगर योजना से मूलभूत शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना के क्षेत्रों में परियोजना

डस्टबिन रखने के लिए प्रेरित करें। कूड़े के सोर्स सेग्रीगेशन के लिए भी जागरूक करें, हरियाली बढ़ाने के लिए पौधारोपण भी कराए। सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट देने तथा उन्हें सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करने के लिए सभी निकायों में ''सुरक्षा एवं कल्याण शिविर'' संचालित

के क्रियान्वयन, आर्थिक अवसरों के सृजन से जनसामान्य को सीधा लाभ प्राप्त होगा। नगर विकास मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने जल निगम के फील्ड हॉस्टल 'संगम' में निकाय अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभियान चलाकर सभी निकायों से 04 हजार कूड़ा स्थलों को साफ किया गया था। इस बार के अभियान में भी पुराने कूड़ा स्थलों के साथ नए बने कूड़ा स्थलों को साफ कर वहां पर सुंदरीकरण का कार्य कराए। लोग कूड़ा इधर–उधर न फेंके इसके लिए डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन को प्रभावी ढंग से चलाएं। लोगों को

करने, जल जमाव न होने नगरीय निकायों के सभी क्षेत्रों से जल निकासी के समुचित प्रबंधन, नाले व नालियों की साफ–सफाई, पानी निकलने में अवरोध बने नाले–नालियों के खराब निर्माण कार्यों को सुधार, संचारी रोग एवं जल जनित रोगों, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव एवं फॉगिंग ब्लीचिंग पाउडर, चूने का प्रयोग पर विशेष रूप से ध्यान देकर आकांक्षी नगर योजना से शहरों का रूपरंग बदलने के मिशन को पूर्ण करना है। ◆

मो. : 9415508695, 8787093085

निडर हुईं महिलाएँ

महिला अपराधों से संबंधित मामलों के निस्तारण में भी आई तेजी

–अखिलेश कुमार सिंह

केस–1–नेहा तिवारी विगत दस वर्षों से बीचोंबीच शहर में स्थित एक मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी कर रही हैं। वह रात 11 बजे तक स्कूटी से घर पहुंचती हैं। वह इंदिरानगर के सेक्टर 11 में मम्मी–पापा और छोटे भाई के साथ रहती हैं।

केस–2–श्वेता तिवारी, नेहा की चचेरी बहन हैं। वे दोनों एक ही मॉल में साथ ही काम करती थीं लेकिन एक वर्ष पहले श्वेता ने एक नये खुले मॉल में नौकरी कर ली। वह उनकी ससुराल मानस विहार से काफी दूर है। श्वेता पहले नेहा के साथ ही आती–जाती थीं लेकिन दो साल पहले शादी के बाद से वह मानस विहार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आती–जाती हैं। वह रात साढ़े 11 बजे तक घर वापस पहुंचती हैं।

केस–3– कीर्ति वर्मा कपूरथला पर पिछले सात वर्षों से दो कोचिंग सेंटरों में फिजिक्स पढ़ाती हैं। वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आती–जाती हैं। उन्हें कठौता चौराहे के पास स्थित घर पहुंचने में रात के 11 बज जाते हैं। कभी जाम का सामना करना पड़ा तो ज्यादा समय भी लग जाता है।

इन तीनों में एक चीज कॉमन है। नेहा, श्वेता और कीर्ति तीनों ही प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की फैन हैं। तीनों का कहना है कि जबसे योगी सरकार आई है, सड़क पर रात में घूमने वाले लोफर नहीं दिखाई देते। पहले हम लोगों को रोज इनके दर्शन होते थे। इनसे बड़ा डर लगता था। कभी–कभार इनकी फब्तियां और सीटियां भी सुननी पड़ती थीं पर अब यह सब बीते ज़माने की बात हो गई।

यह बात सही है कि योगी सरकार आने के बाद सड़क पर घूमने वाले मवाली लड़के अब न के बराबर दिखते हैं। बड़े–बड़े बदमाशों पर की गई कार्रवाई के बाद से ये छुटभैये बदमाश डरे–सहमे हैं। इनमें तमाम जेल में हैं और कुछ ने टपोरीगिरी करना छोड़कर अपना छोटा–मोटा काम–धंधा शुरू कर दिया है। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये छेड़खानी करते पकड़े गए तो अब इन्हें कोई स्थानीय नेता संरक्षण देने वाला नहीं है। पहले ये वारदात करके अपने स्थानीय

आकाओं के रसूख के चलते थानों से छूट जाया करते थे और फिर से लोफरगीरी शुरू कर देते थे।

2017 में अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत में ही योगी सरकार ने इन मंजनुओं के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ी और प्रभावी कार्रवाई की थी। सरकार के इस अभियान का नाम एंटी–रोमियो रखा गया था। आज भी तबके पकड़े गए तमाम रोमियो जेल में हैं और अपनी करनी की सजा भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन पर चल रहे मुकदमे ढीले–ढाले तरीके से चल रहे हैं। इन्हें मुकदमा चलाकर भी सजा दिलाई गई है। इस समय उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों के मामलों में मुकदमों के निस्तारण में अभूतपूर्व तेजी देखने को मिल रही है।

इस संबंध में जुलाई, 2023 में आई एक अखिल भारतीय रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराधों के निस्तारण के मामले में यूपी पूरे देश में नंबर दो पर है। उसके आगे–पीछे, अर्थात पहले स्थान पर दादरा नागर हवेली और दमन और दीव (पहले ये दोनों अलग–अलग केंद्रशासित प्रदेश थे, 2020 में इन्हें एक कर दिया गया है) है, जबकि तीसरे स्थान पर पुंडुच्चेरी है। यहां पर यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि ये दोनों ही प्रदेश जनसंख्या और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश के सामने कहीं भी नहीं ठहरते। बहुत ही छोटे हैं। जहां हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है, वहीं दादरा नागर हवेली और दमन और दीव का क्षेत्रफल मात्र 491 किलोमीटर है। जबकि पुंडुच्चेरी का क्षेत्रफल मात्र 19.54 वर्ग किलोमीटर ही है। ऐसे में ये दोनों प्रदेश हमारे लखनऊ जिले से भी छोटे हैं (जिसका क्षेत्रफल 631 वर्ग किलोमीटर है)। उत्तर प्रदेश दादरा नागर हवेली एवं दमण और दीव से 495 गुना और पुडुच्चेरी से 12450 गुना बड़ा है। दुबारा कह सकते हैं कि ये दोनों ही राज्य उत्तर प्रदेश के आकार के सामने कहीं नहीं ठहरते। ऐसे में उत्तर प्रदेश का अपराध नियंत्रण में इनकी तुलना में दूसरे स्थान पर रहने के बाद भी उसकी महत्ता पहले स्थान जैसी ही कही जाएगी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे और अच्छा काम करके इस मामले में भी प्रदेश को पहला स्थान दिलवाएं।

इस मामले में प्रदेश में जिन–जिन जिलों ने अच्छा काम किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन जिलों के जिलाधिकारियों को पुरस्कृत भी किया है। ध्यातव्य है कि महिला अपराधों के निस्तारण में जिलावार रिजल्ट भदोही, मऊ और बलरामपुर जिले का सबसे अच्छा रहा है। ये तीनों जिले क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आए हैं। मुख्यमंत्री जानते हैं कि अगर महिला अपराधों के निस्तारण में प्रदेश अव्वल रहेगा तो इससे विदेशी निवेश पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

प्रदेश सरकार द्वारा महिला अपराधों में कमी लाने और उन्हें त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए प्रदेश स्तर पर वीमेन पावर लाइन नंबर 1090 चलाई जा रही है। जहां जरूरत पड़ने पर प्रदेश के किसी भी कोने में रहने वाली महिला फोन करके तुरंत छेड़खानी या अपने साथ हुए किसी प्रकार के अपराध की शिकायत कर सकती हैं और इसके साथ ही पुलिस की सहायता प्राप्त कर

सकती है। इसके अलावा प्रदेश के थानों में महिला हेल्प डेस्क का सृजन किया है। साथ ही साथ थानों में महिला बीट अलग से बनाई गई है, जिसका काम महिला पुलिस देखती हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि महिलाएं, महिला पुलिसकर्मियों से खुलकर अपनी बात कह सकेंगी। पुरुष पुलिसकर्मियों से बातें बताने में जो लाज–शर्म की दिक्कत आती थी, महिला पुलिसकर्मियों के साथ यह दिक्कत नहीं आएगी।

प्रदेश सरकार द्वारा महिला अपराधों में कमी लाने और उन्हें त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए प्रदेश स्तर पर वीमेन पावर लाइन नंबर 1090 चलाई जा रही है। जहां जरूरत पड़ने पर प्रदेश के किसी भी कोने में रहने वाली महिला फोन करके तुरंत छेड़खानी या अपने साथ हुए किसी प्रकार के अपराध की शिकायत कर सकती हैं और इसके साथ ही पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश के थानों में महिला हेल्प डेस्क का सृजन किया है। साथ ही साथ थानों में महिला बीट अलग से बनाई गई है, जिसका काम महिला पुलिस देखती है। ऐसा इसलिए किया गया है कि महिलाएं, महिला पुलिसकर्मियों से खुलकर अपनी बात कह सकेंगी। पुरुष पुलिसकर्मियों से बातें बताने में जो लाज–शर्म की दिक्कत आती थी, महिला पुलिसकर्मियों के साथ यह दिक्कत नहीं आएगी।

लड़कियों, महिलाओं को महिला अपराध के प्रति उठ खड़े होने के लिए उनके बीच सरकार द्वारा प्रभावकारी ढंग से जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों–कालेजों में ऐसे अभियान खास तौर पर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पर नुक्कड़ नाटकों और गोष्ठियों के जरिये भी महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा भी कालेजों–स्कूलों में महिला सशक्तीकरण से संबंधित तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

वैसे तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 के तहत महिला–पुरुष को समान दर्जा दिया गया है। इस अनुच्छेद में किसी के भी साथ लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है लेकिन आज भी बहुत से लोग महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। महिलाओं के प्रति उनके नज़रिये में अंतर अभी तक नहीं आया है। इसके लिए महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है। प्रदेश की योगी सरकार जानती है कि महिलाओं में जागरूकता तभी

आएगी, जब वे पढ़ी–लिखी होंगी। वे अच्छे तरीके से पढ़–लिख तब पाएंगी, जब स्वस्थ रहेंगी। ऐसे में राज्य सरकार कन्या शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके अलावा उनके सशक्तीकरण के लिए तमाम स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिनके बारे में यहां पर अलग से चर्चा करना विषयांतर होगा लेकिन अगर हम नमूने के तौर पर एक योजना 'मिशन शक्ति' को लें तो शायद ही प्रदेश का कोई नागरिक होगा जो 'मिशन शक्ति' योजना से परिचित न हो। इस योजना को योगी सरकार ने 17 अक्टूबर, 2020 को

शारदीय नवरात्र के पहले दिन शुरू किया था। जिसका उद्देश्य था–महिलाओ की सुरक्षा और सम्मान के साथ उन्हें स्वावलंबी बनाना। यह योजना अभी भी चल रही है और महिलाएं न केवल अपनी सुरक्षा आप करने के मामले में निर्भीक हुई हैं, बल्कि उन्होंने स्वावलंबन को भी अपनाया है। ऐसी स्वावलंबी महिलाएं आपको हर जिले के हर ब्लॉक और न्याय पंचायत में मिल जाएंगी। महिला सशक्तिकरण की यह योजना अपने आप में अलग है। पुलिस भी इस योजना को लेकर स्कूलों, कालेजों, गांवों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता अभियान चला रही है। अब तक प्रदेश में ऐसे लाखों जागरूकता अभियान चल चुके हैं और अभी भी निरंतर चलाए जा रहे हैं। क्योंकि पुलिस को पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यदि इसके क्रियान्वयन में कोई हीलाहवाली हुई तो मुख्यमंत्री इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन में महिलाएं अपने प्रति होने वाली घरेलू हिंसा के साथ–साथ हर तरह के अन्याय के खिलाफ तेजी से मुखर हुई हैं।

इन सब को मिला कर समग्रता में जो चीज सामने आती है, वह यह कि योगी सरकार महिला अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में बहुत सख्त है। जिसके चलते इस सरकार में महिला अपराध न केवल घटे हैं बल्कि रात में सड़कों पर घूमने वाले टपोरिए अपराधी न के बराबर रह गए हैं। यही कारण है कि लड़कियों और महिलाओं के भीतर का डर अब निकल गया है। क्योंकि वे जानती हैं अगर उन्हें किसी तरह से परेशान किया गया तो उनके पास तुरंत शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध है। वे टपोरियों के साथ–साथ अपने प्रति होने वाले हर अपराध के खिलाफ जागरूक हुई हैं और आवाज उठा रही हैं। क्योंकि उन्हें यह पता है कि चूंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में बेहद संवेदनशील हैं, इसलिए उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी ही होगी। महिलाओं के मन से यह डर निकलने का सकारात्मक प्रभाव आने वाले दिनों में समाज में उभरीं सशक्त महिलाओं के सामने आएगा। जिससे हमारा समाज और बेहतर बनेगा। ◆

मो. : 8400645735

श्रीअन्न से समृद्धि की ओर

—मीनाक्षी लोहानी

मिलेट्स अर्थात् पोषक अनाज एक सामूहिक शब्द है। परंपरागत पुस्तकीय भाषा में इसे कदन्न नाम से जाना जाता है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था तथा जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति इसके फायदों को देखते हुए इसे श्री अन्न नाम से संबोधित किया। मिलेट्स, कदन्न, श्रीअन्न तथा मोटा अनाज नाम से जाने जाने वाले फसलों के इस समूह का अर्थ है छोटे–बीज वाली फसलें। इस प्रकार की फसलों की खेती खाद्य फसल के रूप में मुख्य रूप से समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों व शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर की जाती है। भारत में उपलब्ध कुछ सामान्य फसलों में बाजरा, रागी, ज्वार, सावां, बाजरा और वरिगा (प्रोसो मिलेट) शामिल हैं। यह भोज्य पदार्थ भारतीय संस्कृति की व्यवस्था की भांति भोजन की थाली की विविधता को बढ़ाते रहे हैं।

मानव सभ्यता जैसे–जैसे विकास के नित नए पड़ाव पार करते जा रही है वैसे–वैसे हमारी भूमि और हमारे भोजन की थाली पर विविधता की आवश्यकता को लगातार महसूस किया जा रहा है। विगत 3 वर्षों से विश्व भर में उभरी महामारी और चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं के दौर में भोजन की थाली में विविधता के साथ–साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले पोषक तत्वों से भरपूर गुणवत्तापूर्ण भोजन की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। विशेषज्ञों द्वारा भारत के परंपरागत भोजन मोटे अनाजों को भोजन की थाली में विविधता के संपूर्ण समाधान रूप में देखा जा रहा है।

मिलेट्स अर्थात् पोषक अनाज एक सामूहिक शब्द है। परंपरागत पुस्तकीय भाषा में इसे कदन्न नाम से जाना जाता है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था तथा जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति इसके फायदों को देखते हुए इसे श्री अन्न नाम से संबोधित किया। मिलेट्स, कदन्न, श्रीअन्न तथा मोटा अनाज नाम से जाने जाने वाले फसलों के इस समूह का अर्थ है छोटे–बीज वाली फसलें। इस प्रकार की फसलों की खेती खाद्य फसल के रूप में मुख्य रूप से समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों व शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर की

जाती है। भारत में उपलब्ध कुछ सामान्य फसलों में बाजरा, रागी, ज्वार, सावां, बाजरा और वरिगा (प्रोसो मिलेट) शामिल हैं। यह भोज्य पदार्थ भारतीय संस्कृति की व्यवस्था की भांति भोजन की थाली की विविधता को बढ़ाते रहे हैं।

अब सवाल यह उठता है कि आख़िर मोटे अनाजों में ऐसे कौन से गुण होते हैं जिनके कारण अचानक इनकी चर्चा इतने बड़े पैमाने पर होने लगी है। असल में मिलिट्स ग्लूटेन मुक्त और उच्च प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट सामग्री युक्त होते हैं। इसके साथ ही मिलेट्स को सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी खेती कम वर्षा तथा सिंचाई रहित अर्ध–शुष्क क्षेत्रों में भी की जा सकती हैं। मिलेट्स कठोर वातावरण और कम उपजाऊ मिट्टी में भी जीवित रहने में सक्षम हैं। भारत सरकार मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2018 से विशेष प्रयास कर रही है। इसके लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा 2018–19 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के तहत न्यूट्री–अनाज (मिलेट) पर उप–मिशन के रूप में मिलेट विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। इसके स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए, भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में मिलेट को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया।

मिलेट की घरेलू और वैश्विक मांग बनाने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष (IYM) के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया था, जो कि दिसंबर 2018 में FAO द्वारा स्वीकार गया। भारत के इस संकल्प को 72 देशों का समर्थन प्राप्त था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष (IYM 2023) घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष–2023 की मुख्य कार्य योजना उत्पादन, खपत, निर्यात, ब्रांडिंग आदि को बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है।

मिलेट्स अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी हैं। जैसे की मधुमेह के खतरे को कम करना, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करना, मोटापे का प्रबंधन आदि। अभी सबसे महत्वपूर्ण हमारा स्वास्थ्य है, अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। इसके लिए मिलेट का सेवन बेहद फायदेमंद है। इसके बहुत सारे ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जो कि किसी और प्रकार के भोजन

से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे की ताँबा, फास्फोरस, लोहा, मैगनीशियम आदि। इसलिए मिलेट को कैल्शियम सैंडोज की टैबलेट भी कहते हैं। मिलेट ग्लूटेन मुक्त अनाज हैं जो एंटीऑक्सिडेंट, घुलनशील फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। विशेष रूप से, मिलेट कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक होता है।

मिलेट ग्रामीण, शहरी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सीमांत उत्पादन क्षेत्रों के लिए आय का एक स्रोत है तथा नवीन प्रसंस्करण और विपणन अवसरों के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए अच्छे रोजगार सृजित करने का एक तरीका है।

रागी को भारतीय मूल का अनाज माना जाता है। यह उच्च पोषण मान वाला मोटा अनाज होता है, जिसमें 344 मिग्रा/100ग्राम कैल्शियम होता है। दूसरे किसी भी अनाज में कैल्शियम की इतनी अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है। हड्डियों के स्वास्थ्य, रक्त वाहिका और मांसपेशियों के संकुचन और उचित तंत्रिका कार्य को सुनिश्चित करने के लिए कैल्शियम आवश्यक है। रागी में लौह तत्त्व की मात्रा 3.9मिग्रा/100ग्राम होती है, जो बाजरे को छोड़कर सभी अनाजों से अधिक है। रागी खाने की सलाह मधुमेह के रोगियों को दी जाती है। पारंपरिक रूप से रागी का इस्तेमाल खिचड़ी जैसे आहार के रूप में किया जाता है।

इसी प्रकार बाजरा भी एक बहुत लोकप्रिय मोटा अनाज है। बाजरे का इस्तेमाल कई औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। बाजरे के 100 ग्रा. खाद्य हिस्से में लगभग 11.6 ग्रा. प्रोटीन, 67.5 ग्रा. कार्बोहाइडेट, 8 मि.ग्रा लौह तत्व और 132 माइक्रोग्राम कैरोटीन मौजूद होता है, जो हमारी आँखों की सुरक्षा करता है। भले ही इसमें पाइटिक अम्ल, पॉलीफेनॉल और एमाइलेज जैसे कुछ पोषण–निरोधी अवरोधक होते हैं, पर पानी में भिगोने के बाद अंकुरण और अन्य पकाने की विधियों से इसके पोषण–निरोधी तत्त्वों में कमी हो जाती है।

एक अन्य मोटा अनाज ज्वार दक्षिण अफ्रीकी देश नाइजीरिया का प्रमुख भोजन है। ज्वार का औद्योगिक उपयोग अन्य मोटे अनाजों की तुलना में अधिक होता है। इसका उपयोग शराब उद्योग, डबलरोटी उत्पादन उद्योग, गेहूं–ज्वार संयोजन में किया जाता है। व्यापारिक रूप से शिशु आहार बनाने वाले उद्योगों में ज्वार चवली तथा ज्वार सोयाबीन संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रत्येक 100 ग्राम में 10.4 ग्रा. प्रोटीन, 66.2 ग्रा. कार्बोहाइड्रेट, 2.7 ग्रा. रेशा और अन्य सूक्ष्य तथा वृहत पोषण तत्त्व मौजूद होते हैं।

मोटे अनाज फाइबर (रेशों) से भी भरपूर होते हैं। आहार रेशे को वनस्पति कोशिका के ऐसे घटक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो हमारे भोजन में मौजूद रहते हैं। आहार रेशों में पानी सोखने की प्रवृत्ति होती है और ये फूलने (बल्किंग) वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह आमाशयांत्र प्रणाली में भोजन की तेज गति को प्रेरित करता है तथा बड़ी आंत में मल के जमा होने की अवधि को कम करता है। यह पित्त लवण से जुड़कर कॉलेस्ट्रॉल में कमी

मिलेट्स अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी हैं। जैसे की मधुमेह के खतरे को कम करना, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करना, मोटापे का प्रबंधन आदि। अभी सबसे महत्वपूर्ण हमारा स्वास्थ्य है, अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। इसके लिए मिलेट का सेवन बेहद फायदेमंद है। इसके बहुत सारे ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जो कि किसी और प्रकार के भोजन से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे की ताँबा, फास्फोरस, लोहा, मैगनीशियम आदि। इसलिए मिलेट को कैल्शियम सैंडोज की टैबलेट भी कहते हैं। मिलेट ग्लूटेन मुक्त अनाज हैं जो एंटीऑक्सिडेंट, घुलनशील फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। विशेष रूप से, मिलेट कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक होता है।

करता है। यह हाइपो कॉलेस्ट्रेमिक एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हृदय–रक्तवाहिका तंत्र रोगों में लाभदायक होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि चावल में अन्य अनाजों की तुलना में सबसे कम आहार रेशे होते हैं। ज्वार, बाजरे तथा रागी में आहारीय रेशे की मात्रा अत्यधिक होती है।

वर्तमान में एक अन्य स्वास्थ्य समस्या के रूप में कैल्शियम की कमी का मुद्दा चर्चा में रहता है। विशेषकर गर्भवती तथा धात्री महिलाओं में। विशेषज्ञों द्वारा बताया जाता है कि गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं में कैल्शियम की कमी होने से बच्चों की हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान अपर्याप्त कैल्शियम लेने से माँ का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, इस दौरान माँ की हड्डियों के कैल्शियम का इस्तेमाल भ्रूण के विकास और स्तन दुग्ध के निर्माण में होने लगता है। कैल्शियम की कमी के कारण माँ की संचरण प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है और उच्च रक्तचाप की समस्या पैदा होती है। गर्भावस्था के दूसरे अर्धावधि में कैल्शियम का पूरक आहार देने से गर्भावस्था से उत्पन्न उच्च रक्तचाप और प्री–एक्लेम्प्सिया की घटनाओं में कमी आती है। यदि हम मोटे अनाज, रागी और ज्वार के पोषण मानों का विश्लेषण करें, तो पाएंगे कि इनमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

मक्का, ज्वार और अन्य मोटे अनाज का उत्पादन भारत के कुल खाद्य उत्पादन का एक चौथाई है तथा यह देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है। इसके अलावा पारंपरिक पाकविधियों में मोटे अनाजों का इस्तेमाल शिशु आहार बनाने वाले उद्योग तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है। ज्वार का इस्तेमाल ग्लुकोज और अन्य पेय निर्माण उद्योग में किया जाता है। अब रागी और गेहूं के मिश्रण से निर्मित वर्मिसेली बाजार में उपलब्ध है, जिसे खाने के लिये तैयार भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

अब एक समस्या यह आती है कि मोटे अनाजों में मौजूद पोषण–निरोधी तत्त्वों को कैसे घटाया जाए? हवा लगाना, सेंकना, अंकुरण, भिंगोने और माल्टिंग जैसी कुछ पारंपरिक विधियों के जरिए मोटे अनाजों के गाढ़ेपन में काफी कमी आ जाती है। गाढ़ेपन में सबसे अधिक कमी मॉल्टिंग के दौरान आती है। अनाज के अंकुरण के बाद और धूप में सुखाने के बाद अधिकतर अवांछित एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। मिश्रण का गाढ़ापन और अमाइलेज की मात्रा, गैर–माल्टेड अनाज मिश्रण से काफी कम होती है। माल्टेड मोटे अनाज, शिशु आहार फार्मूलों और साथ ही बूढ़े व्यक्तियों के पोषण में काफी लाभदायक होते हैं।

चूँकि उत्तर प्रदेश मोटे अनाजों का अग्रणी उत्पादक तथा भारत के निर्यात भागीदारी में प्रमुख सहभागी भी है। इसलिए विगत वर्षों से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका परिणाम धरातल में भी दिखाई दे रहा है। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में कुल 10.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मोटे अनाज बोये गए थे जिससे कुल 22.25 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ था। वर्ष 2022 में मोटे अनाजों का क्षेत्रफल बढ़कर 12.10 लाख हेक्टेयर हो गया तथा उत्पादन बढ़कर 27.61 लाख मैट्रिक टन। इस दर को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2023 के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाकर 12.58 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन का लक्ष्य 28.71 एक लाख मैट्रिक टन रखा गया है।

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में मिलेट्स (ज्वार, बाजरा,

कोदो, सावा रागी/मडुआ आदि) की खेती प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।इसके तहत उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम यू.पी.एम.आर.पी.) नामक यह नवीन योजना वर्ष 2022–23 (01 जनवरी, 2023) से वर्ष 2026–27 तक संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम क्रियान्वयन की 05 वर्षों की इस अवधि में 18626.50 लाख रुपये का अनुमानित व्यय आंकलित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नयी योजना स्वीकृत करते हुए वहन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के संचालन हेतु नीति निर्धारण, पात्रता हेतु मापदण्ड निर्धारण, अनुदान भुगतान हेतु मानक के निर्धारण एवं योजना की सामयिक प्रगति की समीक्षा हेतु कृषि निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय परियोजना स्क्रीनिंग समिति अधिकृत होगी। राज्य स्तरीय परियोजना स्क्रीनिंग समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों की स्वीकृति अनुश्रवण एवं स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त करने हेतु अपर मुख्य सचिव कृषि की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति अधिकृत होगी। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, क्षेत्र एवं क्रियान्वयन के दिशा–निर्देशों में भविष्य की आवश्यकता के अनुसार वांछित संशोधन राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा किया जाएगा।

इस कार्यक्रम को क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में किया जाएगा। इसके तहत मिलेट्स की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु मिलेट्स बीज के मिनीकिट कृषकों को निःशुल्क वितरित किये जाएंगे। गुणवत्तायुक्त बीजों का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राज्य की प्रमाणित बीज वितरण योजना के अन्तर्गत अनुदान पर किया जाएगा। बीज मिनीकिट वितरण में सीमान्त एवं लघु कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी, यदि सामान्य कृषक भी मिलेट्स का बीज लेना चाहें तो उन्हें भी उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2023–24 से 04 वर्षों तक मिलेट्स के बीज मिनीकिट 2.5 लाख कृषकों को निःशुल्क वितरित किये जाएंगे। इसके लिए कृषकों का चयन कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत अथवा भारत सरकार की किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत आच्छादित कृषकों में से किया जाएगा। चयनित कृषकों में 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति ध् अनुसूचित जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। महिला कृषकों को विशेष वरीयता प्रदान की जाएगी।

आम जनमानस में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की गई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत मोटे अनाजों से तैयार पोषक तत्व वाला भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसानों को मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोटे अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए प्रदेश के मोटे अनाज उत्पादक प्रमुख 18 जनपदों के 106 राजकीय बाजरा क्रय केंद्रों से 2350 रुपया प्रति कुंटल की दर से 43,438 मेट्रिक टन बाजरा की खरीद की गई। इसके लिए 8532 किसानों को 102.08 करोड़ रुपयों का भुगतान उनके आधार से लिंक बैंक खातों में किया गया। ◆

मो. : 8077278361

पिछड़ों और दिव्यांगजनों के साथ खड़ी सरकार

—प्रिया श्रीवास्तव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की सफलताओं से प्रभावित होकर विश्व–विख्यात जगतगुरू रामभद्राचार्य के द्वारा स्थापित जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट को उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन देने का निर्णय लिया, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान मण्डल द्वारा विधेयक पेश करके राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। अब उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के उच्च शिक्षा के लिये डा. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय सहित दो विश्वविद्यालय हो गये हैं जिनके माध्यम से दिव्यांगजनों को शिक्षित बनाकर सशक्त किया जायेगा।

शादी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दिव्यांग दम्पत्ति को शादी प्रोत्साहन योजना के तहत 35000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है परन्तु दिव्यांग दम्पत्ति को शादी पंजीकरण करना आवश्यक था जिससे दिव्यांगजनों पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ रहा था तथा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था इसलिये दिव्यांग दम्पत्ति को शादी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के लिये रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा राज्य दिव्यांग आयुक्त के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं का निस्तारण लखनऊ स्थित कार्यालय से किया जा रहा है, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मोबाइल कोर्ट के माध्यम से विभिन्न जनपदों में राज्य दिव्यांग आयुक्त द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी आदि जनपदों में मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना जा रहा है। मोबाइल कोर्ट व्यवस्था दिव्यांगजनों के लिये बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है।

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए 48 करोड़ रूपये की लागत से नवीन महिला छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। महिला छात्रावास बन जाने से प्रदेश भर की दिव्यांग छात्रों को और अधिक शिक्षा प्राप्त करने

का अवसर मिलेगा। डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के विभिन्न पाठ्यक्रमों बी.टेक., बी.बी.ए., एम.सी.ए. आदि में अध्ययनरत कुल 112 विद्यार्थियों को प्लेसमेंट सेल के माध्यम से विभिन्न कॉरपोरेट कम्पनियों में प्लेसमेंट कराकर एक बड़ी शुरूआत की गई है। भविष्य में भी इस तरह के प्रयास करके छात्र–छात्राओं को नौकरियों से जोड़ा जायेगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित समस्त 16 विशेष विद्यालयों को अपनी उच्च स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था सहित कैम्पस की उच्च स्तर प्रबन्ध प्रणाली के लिये वित्तीय वर्ष 2022–23 आई.एस.ओ. 90012015 प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। इन विद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा के लिये स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था की गई है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु बजट में अतिरिक्त इस वर्ष 435 करोड़ की व्यवस्था की गई है व अन्य कार्यों के लिये 167 करोड़ की बजट में वृद्धि की गई है। शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब छात्र व छात्राओं के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2023–24 में ऐसे छात्रावासों के अनुरक्षण हेतु विशेष प्रयास कर 1.25 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था पहली बार करायी गई है। छात्रों को छात्रवृत्ति मार्च में मिलने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था इसके दृष्टिगत अब छात्रवृत्ति की उपलब्धता दिसम्बर माह में ही कर दी जायेगी। शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को 20,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु बजट में अतिरिक्त इस वर्ष 435 करोड़ की व्यवस्था की गई है व अन्य कार्यो के लिये 167 करोड़ की बजट में वृद्धि की गई है। शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब छात्र व छात्राओं के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2023–24 में ऐसे छात्रावासों के अनुरक्षण हेतु विशेष प्रयास कर 1.25 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था पहली बार करायी गई है। छात्रों को छात्रवृत्ति मार्च में मिलने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था इसके दृष्टिगत अब छात्रवृत्ति की उपलब्धता दिसम्बर माह में ही कर दी जायेगी। शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को 20,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 150 करोड़ रूपये का प्राविधान है जिससे इस वर्ष 75000 लाभार्थी लाभन्वित होंगे। ◆

मो. : 7007912739

बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का ऐतिहासिक फैसला

—विदर्भ कुमार

बुन्देलखण्ड क्षेत्र को भारत में दलहन उपज का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ यमुना, बेतवा, केन, चम्बल, टौंस व सोन आदि हैं। सागौन, शीशम, चन्दन, आम और महुआ आदि प्रमुख वन सम्पदा है। उल्लेखनीय है कि बुन्देलखण्ड का प्राचीन नाम ''जैजाक मुक्ति'' है। ''बुन्देली'' इस क्षेत्र की मुख्य भाषा है। महान शासक विद्याधर चन्देल, आल्हा—उदल, महाराजा छत्रसाल, राजा भोज, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैथिलीशरण गुप्त, मेजर ध्यान चन्द तथा गोस्वामी तुलसीदास आदि अनेक महान विभूतियाँ इस क्षेत्र से सम्बन्ध रखती हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में झाँसी व चित्रकूट धाम मण्डल हैं। इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले दोनों मण्डल में सात जनपद यथा—झाँसी, ललितपुर, जालौन, बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर तथा महोबा आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इसकी आबादी लगभग 97 लाख है। इस क्षेत्र में प्रायः पठारी भूमि है। यहाँ औसत वर्षा 60—100 से.मी. के लगभग होती है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र को भारत में दलहन उपज का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ यमुना, बेतवा, केन, चम्बल, टौंस व सोन आदि हैं। सागौन, शीशम, चन्दन, आम और महुआ आदि प्रमुख वन सम्पदा है। उल्लेखनीय है कि बुन्देलखण्ड का प्राचीन नाम ''जैजाक मुक्ति'' है। ''बुन्देली'' इस क्षेत्र की मुख्य भाषा है। महान शासक विद्याधर चन्देल, आल्हा—उदल, महाराजा छत्रसाल, राजा भोज, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैथिलीशरण गुप्त, मेजर ध्यान चन्द तथा गोस्वामी तुलसीदास आदि अनेक महान विभूतियाँ इस क्षेत्र से सम्बन्ध रखती हैं। बुन्देलखण्ड में पानी की कमी और भूमि अनुपजाऊ दो तरफा प्रहार के कारण औद्योगिक विकास शून्य था नौकरी प्राप्ति एक सपना, देहातों से निगर्मन दर अत्यधिक 39 प्रतिशत है जबकि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में यह मात्र 11 प्रतिशत है। निवासियों के पास 5—10 एकड़ जमीन है किन्तु दो वक्त का भोजन पाने में असमर्थ लोगों के जीवन में खुशहाली की सौगात देने के लिए आजादी के अमृतकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का ऐतिहासिक फैसला लेकर बुन्देलखण्ड के निवासियों के सर्वांगीण विकास की पहल की है। पूर्व की सरकारों में बदहाल

बुंदेलखंड अब 'डबल इंजन की सरकार' में विकास के बुलंदी की गाथा लिख रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उ.प्र. सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कृत संकल्पित है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र की प्रगति के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की लाइफ लाइन बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे परियोजना तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र की पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने जनपद झांसी के 33 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के गठन हेतु प्रस्तुत अधिसूचना के आलेख को अनुमोदित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इसके पूर्व वर्ष 1976 में एक नए शहर नोएडा के गठन का निर्णय लिया गया था। 47 वर्षों के बाद एक नए शहर की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से बुन्देलखण्ड के बहुआयामी विकास को तेज गति मिलेगी। बुंदेलखंड के विकास के लिए एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ष 2022–23 के अनुपूरक बजट में नई मांग के रूप में प्रदेश में 'मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण/नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना' का शुभारम्भ किया था। इसके अन्तर्गत बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के लिए 5,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत झांसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा की तर्ज़ पर एक नई इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किए जाने का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्य मंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण/नये औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना मद के अन्तर्गत ऋण के रूप में 5000 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

प्रस्तावित नए इण्डस्ट्रियल टाउनशिप उद्योगों के साथ–साथ शैक्षणिक संस्थाओं, अन्य सेक्टर से सम्बन्धित संस्थाओं के विकास, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय परिसर के निर्माण को बढ़ावा देगा। प्रस्तावित नए शहर में विश्व स्तरीय नियोजन व उसके अनुसार अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झांसी के अलावा बुन्देलखण्ड के अन्य जनपदों में भी सेटेलाइट औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सहायक होगा।

बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पहले चरण में झांसी–ग्वालियर रोड एवं झांसी–बबीना–ललितपुर रोड के मध्य पड़ने वाले 33 राजस्व ग्रामों की भूमि अधिग्रहीत कर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इन 33 ग्रामों में कुल लगभग 35,000 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें लगभग 8,000 एकड़ भूमि ग्राम समाज की है। ग्राम समाज की भूमि रिज्यूम कर निःशुल्क बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाएगी एवं कृषकों की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

जिलाधिकारी, झांसी द्वारा अपने 28 जुलाई, 2023 के पत्र द्वारा 33 ग्रामों की सूची भूमि के रकबा वार उपलब्ध करायी गई है। जिलाधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के अनुसार समस्त ग्रामों की प्राइवेट भूमि का सर्किल रेट का 4गुना एवं परिसम्पत्तियों का अनुमानित मूल्यांकन लगभग 6,312 करोड़ रुपये है।

बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय झांसी में होगा। झांसी वह स्थान है, जहाँ ईस्ट–वेस्ट, नॉर्थ–साउथ स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर का जंक्शन है और यह प्रदेश को देश के दक्षिणी हिस्से से कनेक्ट करने का भी एक रास्ता है। बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की प्लानिंग एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के इंडस्ट्रियल टाउनशिप के विकास को लक्षित कर बनायी जाएगी। एक एयरपोर्ट का निर्माण भी इसी क्षेत्र में प्रस्तावित है।

बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठित होने पर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा तथा रोजगार का सृजन होगा तथा जन सामान्य को क्षेत्रीय विकास के साथ–साथ रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे जन सामान्य को प्रत्यक्ष लाभ होगा।

आजादी के अमृतकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का ऐतिहासिक फैसला लेकर बुन्देलखण्ड के निवासियों के सर्वांगीण विकास की पहल की है। पूर्व की सरकारों में बदहाल बुंदेलखंड अब 'डबल इंजन की सरकार' में विकास के बुलंदी की गाथा लिख रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उ.प्र. सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कृत संकल्पित है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के परंपरागत उद्योगों का होगा अब विकास

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की माँग को देखते हुये पर्यटन, हेल्थकेयर, स्टोन क्रशर, टूरिज्म एण्ड हास्पिटैलिटी, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रानिक्स, कन्स्ट्रक्सन, आटोमोटिव रिन्यूएबल एनर्जी, आयरन एण्ड स्टील, टैक्सटाईल एवं माइनिंग सेक्टर में विकास को वल मिलेगा। क्षेत्र के परम्परागत उद्योग यथा चन्देरी साड़ी, रानीपुर टेरीकॉट, हाथ कागज निर्माण कपड़े के खिलौने तथा गुड़िया निर्माण की परम्परागत विधा का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने जखौरा, ललितपुर तथा महोबा के ढलवाँ पीतल, गौरा पत्थर व चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने बनाने वाले परम्परागत कारीगरों को मूर्ति शिल्प तकनीक व लकड़ी के खिलौनों की लाख कोटिंग का ज्ञान देने के साथ बाँदा के शजर पत्थर के नग तथा आभूषण उत्पादन,हमीरपुर की जूती निर्माण, पाली के देसी चर्म के उत्पाद, तालबेहट के लौह कढ़ाई के उत्पाद के कारीगरों का प्रशिक्षण के साथ आयुर्वेद दवा उद्योग हेतु वनों पर आधारित कच्चे माल के वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग ,परम्परागत कुम्हारी कला के कारीगरों को आधुनिक तकनीक के चाक चलाने का प्रशिक्षण देकर विकास से जोडने की योजना से रोजगार सृजन के साथ औद्योगिक विकास होगा। मऊ रानीपुर में खुशबूदार इलायची, बरूआसागर में उत्पन्न होने वाले अदरक और हल्दी, खोया, पनीर तथा दूध के भण्डारण के निर्माण के आधुनिक तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण मिलेगा। ग्रेनाइट कटिंग व पॉलिशिंग, आर्गेनिक कृषि, फ्लोरीकल्चर, पोली हाउस में सब्जी की खेती, देशावरी पान उत्पाद अतर्रा, बाँदा के देशी धान, अचार उत्पादन, फल संरक्षण के वनों पर आधारित उद्योगों तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली सब्जियों तथा फलों आदि के लिये पैकेजिंग एवं प्रोसेसिंग हो सकेगी। होजरी निर्माण का कभी हब रहे जनपद ललितपुर के कारीगरों में काटन होजरी निर्माण के पुर्नविकास, पावरलूम आधारित रानीपुर टेरीकाट के बुनकरों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की मांग के अनुसार डिजाइन तैयार करने हेतु प्रशिक्षित करने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक डिजाइन इन्स्टीट्यूट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ◆

मो. : 76073 54095

चंदन से महक रहा प्रदेश

—केवल राम

प्रदेश के बुंदेलखण्ड में चंदन वन आज भी अपनी पहचान बनाये हुए है, चंदन की उपयोगिता के दृष्टिगत चंदन की खेती के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के किसान परंपरागत किसानी के साथ–साथ चंदन की खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दो दर्जन से जिलों में चंदन की खेती हो रही है। इन सबके प्रेरणा हैं प्रतापगढ़ निवासी उत्कृष्ट पांडेय। एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट पद से इस्तीफा देने के बाद अपने गांव में चंदन की न केवल खेती कर रहे हैं बल्कि नर्सरी तैयार कर किसानों को पौधे उपलब्ध करा रहे हैं। यहां भ्रमण के लिए दूसरे जिलों और प्रदेशों से लोग आते हैं। बकौल पांडेय यूपी में उनसे जुड़े करीब दो दर्जन जिले में लोग चंदन की खेती कर रहे हैं। यह अलग बात है कि कोई एक वर्ष पहले पौधारोपण किया है तो कोई दो–तीन वर्ष पहले। किसानों की यह पहल पर्यटन विभाग की उस मुहिम को सफल बना रही है जिसमें टूरिज्म और रूरल टूरिज्म आदि के जरिये ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रतापगढ़ के ग्राम भदौना निवासी किसान उत्कृष्ट पांडेय के मुताबिक चंदन की खेती के लिए प्रदेश का वातावरण अनुकूल है। प्रदेश में कहीं–कहीं छिटपुट रूप से चंदन होता रहा है जिसका वर्णन साहित्य में मिलता है, किंतु एक मुहिम के रूप में चंदन की खेती की शुरुआत उत्कृष्ट पांडे द्वारा की जा चुकी है। इसके लिए 6–8 पीएच वाली मिट्टी की जरूरत होती है और तापमान 5–45 डिग्री के बीच होना चाहिए, जल जमाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, जबकि बारिश 400 से 1500 एमएम के बीच होनी चाहिए, ये सभी अनुकूल कारक प्रदेश में मौजूद है। चंदन का पौधा किसी भी मौसम में लगा सकते और इसको बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। इसे आप पूरे खेत के साथ कम जमीन में फेंसिंग/मेड़ के रूप में भी लगा सकते हैं। चंदन के पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, साथ ही कृषि वानिकी के लिए अनुकूल पौधा है। एक चंदन का पेड़ तैयार होने में 15/16 साल तक का समय लेता है लगभग 6 वर्ष बाद से हर्टवुड बनाने लगती है जो चंदन के सुगंध का कारण होती है। चंदन के पेड़ों के साथ–साथ अन्य औषधीय और फलदार पेड़ लगाकर अच्छी कमाई की जा सकती है। चंदन का पौधा किसानों को 100 रुपये से 150 रुपये तक में मिल जाता है। एक एकड़ में 250 से 300 पौधे लगाए जा सकते हैं। चंदन के एक पेड़ से किसान 2 से 3 लाख रुपये तक की कमाई कर सकते हैं।

चन्दन का उत्पादन आपूर्ति के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में इसकी मार्केटिंग/बिक्री में कोई परेशानी नहीं होती

है। यूपी में कन्नौज, जहां इत्र का काम होता हैं यह बड़ा बाजार है। यहां चंदन की मांग बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा दक्षिण में कर्नाटक फारेस्ट, कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्डेंट लिमिटेड (KSDL), एससेंशियल ऑइल निर्माताओं जैसे बड़े खरीददार हैं। चंदन की लकड़ी को सबसे महंगी लकड़ी माना जाता है इसका बाजार मूल्य करीब 10 हजार से 15 हजार रुपये प्रति किलो तक है। एक पेड़ से किसान को 15 से 20 किलो लकड़ी आराम से मिल जाती है। ऐसे में उसे एक पेड़ से 2 से 3 लाख रुपये तक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जबकि चंदन का तेल गुणवत्ता के आधार पर 4–5 लाख रुपयेध्लीटर के हिसाब से बिकता है। वर्तमान समय में चंदन की भारी मांग को देखते हुए इसकी खेती की जाने लगी है।

- **चंदन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा परफ्यूम में किया जाता है।**
- **आयुर्वेद में चंदन का खूब इस्तेमाल किया जाता है।**
- **इसे तरल पदार्थ (चंदन का तेल) के रूप में भी तैयार किया जाता है।**
- **इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।**

प्रतापगढ़ के चंदन किसान उत्कृष्ट पांडेय ने कहा कि "वह चाहते है कि हमारे युवा भी देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करें। उनका कहना है कि 'ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों को आय को दुगुना करने की मुहिम में चंदन एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसी सपने के साथ वर्ष 2016 में मैंने असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी छोड़ दी और कई सेक्टर्स को एक्सप्लोर करने लगे। इस बीच चंदन और काली हल्दी की खेती का विचार आया है। पांडे ने बताया कि हर कोई समझता है कि चंदन को सिर्फ दक्षिण भारत में ही उगाया जा सकता है, लेकिन जब इससे जुड़ी जानकारियां इकट्ठी कीं तो पता चला कि उत्तर प्रदेश भी सफेद चंदन की खेती के लिए अनुकूल है। उसके बाद बैंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एवं टेक्नोलॉजी से कोर्स भी किया, जो आज चंदन पर रिसर्च करने वाला सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। ◆

मो. : 6389300599

सजग युवा, सशक्त प्रदेश

–उपेन्द्र कुमार

किसी भी देश या प्रदेश का भविष्य वहां के युवाओं पर टिका होता है। देश की युवा पीढ़ी यदि गलत रास्ते पर चली जाए तो निश्चित तौर पर जीवन अंधकारमय हो जाता है। युवा वर्ग में जिंदगी के प्रत्येक क्षण को रोमांच के साथ जीने की ललक होती है। यह युवा रोमांच में और अधिक वृद्धि करने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। युवा पीढ़ी नशा करना अपनी शान समझती है। युवा शराब, गुटका, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि के नशे में उलझ जाते हैं। इन भटके हुए युवाओं को सही मार्ग पर लाने के लिए अच्छी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसी प्रेरणा का सूत्रपात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विगत 12 अगस्त 2023 को अन्तरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश में 'नशा मुक्त प्रदेश, सशक्त प्रदेश' अभियान का शुभारंभ किया। उन्होनें प्रदेश के युवाओं को नशा मुक्ति हेतु शपथ दिलायी तथा 'नशा मुक्त प्रदेश, सशक्त प्रदेश' के लिए हस्ताक्षर अभियान का शुभारम्भ किया। प्रदेश ने मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी है। प्रदेश सरकार नशा मुक्त भारत बनाने की भारत सरकार की कटिबद्धता में पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व नशे के खिलाफ लड़ाई के लिए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में ड्रग तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया था।इस क्षेत्रीय सम्मेलन के मौके पर सभी की वर्चुअल उपस्थिति में प्रदेश में कुल 984 अभियोगों के तहत कुल 4146.75 किलोग्राम मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया। प्रदेश में एनकॉर्ड की राज्य स्तरीय समिति तथा सभी 75 जनपदों में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है। प्रदेश में एनकॉर्ड की राज्य स्तरीय समितियों की कुल 04 बैठकें हुई हैं। प्रथम राज्य स्तरीय बैठक में एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया। द्वितीय बैठक में आबकारी नीति में बदलाव करते हुए सभी रेस्टोरेंट/पब/बार आदि पर स्टील प्लेटेड चेतावनी बोर्ड लगवाना अनिवार्य किया गया। तृतीय बैठक में एडवांस्ड डाटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और अफीम पोस्त फसल की सेटेलाइट मैपिंग और विनष्टीकरण का निर्णय लिया गया। नशे के समूल नाश के लिए नशा मुक्ति जागरूकता अभियान और प्रवर्तन की कार्यवाही साथ–साथ चलाया जाना प्रभावी सिद्ध हो रहा है। एन.डी.पी.एस. अधिनियम के सर्वाधिक लम्बित मुकदमों वाले शीर्ष 10 जनपदों में विशेष न्यायालय का गठन की कार्यवाही चल रही

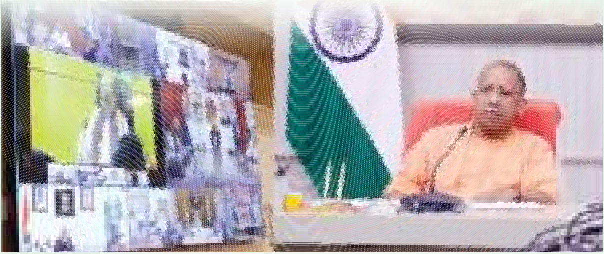

है। विगत वर्ष 04 अगस्त, 2022 को एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ए.एन.टी.एफ.) का गठन किया गया। ए.एन.टी.एफ. को सर्च, विवेचना, कुर्की, अभिरक्षा, गिरफ्तारी, ज़ब्तीकरण की शक्तियां प्राप्त हैं। पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को ए.एन.टी.एफ. का प्रमुख बनाया गया है। ए.एन.टी.एफ. की 02 विंग ऑपरेशन्स और मुख्यालय/प्रशासन हैं। इनमें पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपाधीक्षक के अधिकारी तैनात किए जाने की व्यवस्था है। प्रदेश में मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्यवाही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ लगातार की जा रही है। प्रदेश में मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए वर्ष 2020 से जून, 2023 तक कुल 35,775 अभियोगों में कुल 39,344 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा कुल 02 लाख 13 हजार 726 किलोग्राम से अधिक मात्रा के मादक पदार्थों की बरामदगी की गयी। एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने प्रदेश में अगस्त, 2022 में अपने गठन के पश्चात कुल 40 अभियोगों में कुल 108 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा लगभग 6,569 किलोग्राम मादक पदार्थों की बरामदगी की। ए.एन.टी.एफ. ने वर्ष 2023 में जनपद आगरा में 02 तथा जनपद बरेली में 01, कुल 03 मादक पदार्थों के कारखानों का ध्वस्तीकरण किया।

एस.टी.एफ. द्वारा वर्ष 2021 से माह जून, 2023 तक कुल 460 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करते हुए कुल 44,455 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों की बरामदगी की गयी। उत्तर प्रदेश में सतत प्रक्रिया के तहत वर्ष 2022 व वर्ष 2023 में अब तक कुल 01 लाख 08 हजार 289 अभियोगों में कुल 4,631 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया है। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान को गति देते हुए प्रदेश में कुल 22 नशा निर्व्यसन केन्द्र क्रियाशील हैं। अन्तरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस 26 जून, 2023 को एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं प्रदेश के समस्त जनपदों के पुलिस कार्यालयों पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध जागरूकता अभियान के अन्तर्गत नुक्कड़ सभाओं, रैलियों, शपथ, खेलकूद, मोटर साइकिल रैली आदि कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। सिनेमा घरों/एफ.एम. रेडियो/ट्रैफिक कण्ट्रोल रूम द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु संदेश का प्रसारण भी किया जा रहा है। युवा नशे की लत में न फंसे इसके लिए उन्हें के अपने आसपास के लोगों और दोस्तों से सतर्क रहना चाहिए। एक बार नशे की आदत लगने के बाद नशे की लत में बच्चे और युवा निरंतर इस जाल में फंसते चले जाते हैं। कोई कितना भी खास दोस्त या रिश्तेदार हो यदि नशे के लिए दबाव डालता है तो समझ जाइए कि वह नशे के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिस आयु में युवा को समाज और देश के भविष्य के बारे में चिंतन करते हुए नए सपनों को बुनना और उसके अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए यदि उस आयु में वह नशे का आदी हो जाएगा, तो वह समाज में क्या योगदान दे पाएगा। नशा अन्दर ही अन्दर व्यक्ति को खोखला कर देता है। व्यक्ति किसी लायक नहीं रहता।

नशा नाश और जवानी को समाप्त करने का कारण है। इससे दूर रहकर स्वस्थ चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए युवाओं के मन में नशे के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न कर इस लड़ाई में विजय पायी जा सकती है। नशे की आदत न केवल आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह देश की सुरक्षा के लिए भी घातक है। मादक पदार्थों से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान तथा आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। मादक पदार्थों से न केवल देश की युवा पीढ़ी को का नुकसान हो रहा है, बल्कि यह समाज व राष्ट्र की भी क्षति कर रहा है। इसलिए इन पर प्रभावी रोक लगाया जाना आवश्यक है। ◆

मो. : 6306959511

वन्यजीवों के संरक्षण से मिली नई दिशा

—के.एल. चौधरी

वन और वन्यजीव इस धरती की प्राकृतिक धरोहर है। वनो और वन्यजीवों से पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहता है, जो मानव जीवन को समृद्ध और सुखमय बनाते हैं। भारत में विभिन्न प्रजातियों के कई वन्यजीवों का वास है। वन्यजीव भी प्राणी हैं। आज वन्य प्राणियों के प्रभावी संरक्षण व संवर्द्धन हेतु व्यापक जन जागरूकता करते हुए उनके प्रति करूणा व स्नेह का भाव जागृत करना जरूरी है। वन्यजीवों को सुरक्षित रखने की हमारी समृद्ध परम्परा का ही परिणाम है कि इस धरती पर शहरीकरण एवं औद्योगिक विकास होने तथा अत्यधिक जैविक दबाव होने पर भी विभिन्न प्रकार के वन वनस्पतियों एवं वन्यजीव की प्रजातियां जीवित पाई जाती है। धरती की प्राकृतिक सुन्दरता का संतुलन बनाये रखने के लिए विभिन्न प्रजाति के जीवों में समन्वय जरूरी होता है। वन्य जीव उस हर वृक्ष, पौधे, जानवर, पक्षी और अन्य जीव को कहा जाता है, जो मानव द्वारा पालतू न बनाया गया हो। जंगली जीव दुनिया के सभी क्षेत्रों रेगिस्तान, वन, घास भूमि, मैदान, पर्वत, जलीय क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में भी पाये जाते हैं और मानव बसेरों से दूर वनों–पर्वतों आदि प्राकृतिक स्थानों में रहते हैं।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में वन्यजीवों के प्राकृतिवासों संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु विशेष कार्य किये जा रहे हैं। वन्य प्राणियों को प्राकृतिकवास देने और अनुकूल वातावरण बनाये रखने के लिए प्रदेश सरकार ने वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाकर पौधरोपण कराया है। प्रदेश सरकार के गत 06 वर्षों के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में लगभग 140 करोड़ पौधे रोपित करते हुए वनावरण/वृक्षावरण बढ़ाया है। प्रदेश में इस वर्ष ही 36.16 करोड़ पौधे रोपित हुए हैं।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु विशेष कार्य किये जा रहे हैं। वन्य प्राणियों को प्राकृतिकवास देने और अनुकूल वातावरण बनाये रखने के लिए प्रदेश सरकार ने वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाकर पौधरोपण कराया है। प्रदेश सरकार के गत 06 वर्षों के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में लगभग 140 करोड़ पौधे रोपित करते हुए वन क्षेत्र बढ़ाया है। प्रदेश में इस वर्ष ही 36.16 करोड़ पौधे रोपित हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कराये गये वृक्षारोपण से प्रदेश में 91 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है।

प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्था का ही परिणाम है कि प्रदेश में राष्ट्रीय पशु बाघों की संख्या जो 173 थी वह बढ़कर 205 हो गई है। प्रदेश में बाघों की संख्या में 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। प्रदेश सरकार ने झीलों, तालाबों की संख्या में बढ़ोत्तरी की है। जो झीलें, नदियां, तालाब आदि जल के क्षेत्रों में भराव घास उगे थे उनकी सफाई, मरम्मत आदि कराकर मूल स्वरूप में लाया गया है। प्राकृतिक वातावरण और पूर्ण संरक्षण देने का ही परिणाम है कि ''राज्यपक्षी सारस'' की संख्या विगत 06 वर्षों में 17586 से बढ़कर 19616 हो गई है। राज्यपक्षी सारस को प्रदेशवासी बहुत प्यार करते है और उनके वास से छेड़छाड़ नहीं की जाती है।

प्रदेश सरकार ने वन्यजीवों को प्राकृतिक वास देकर उनकी आबादी में बढ़ोत्तरी की है। वन्यजीवों को जब प्राकृतिक और उनकी प्रकृति, स्वभाव के अनुकूल भरपेट भोजन मिलता रहेगा और नर–मादा प्राकृतिक रूप से मिलेंगे तो उनका कुनबा निश्चय ही बढ़ेगा। प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्था का ही परिणाम है कि प्रदेश में राष्ट्रीय पशु बाघों की संख्या जो 173 थी वह बढ़कर 205 हो गई है। प्रदेश में बाघों की संख्या में 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। प्रदेश सरकार ने झीलों, तालाबों की संख्या में बढ़ोत्तरी की है। जो झीलें, नदियां, तालाब आदि जल के क्षेत्रों में भराव घास उगे थे उनकी सफाई, मरम्मत आदि कराकर मूल स्वरूप में लाया गया हैं। प्राकृतिक वातावरण और पूर्ण संरक्षण देने का ही परिणाम है कि ''राज्यपक्षी सारस'' की संख्या विगत 06 वर्षों में 17586 से बढ़कर 19616 हो गई है। राज्यपक्षी सारस को प्रदेशवासी बहुत प्यार करते हैं और उनके वास से छेड़छाड़ नहीं की जाती है। इसी प्रकार प्रदेश में हाथी की संख्या 265 से बढ़कर 352 हो गई है। प्रदेश के वन क्षेत्रों में हाथियों को पूर्ण संरक्षण दिया जा रहा है।

प्रदेश सरकार प्रदेश के 27 वन्यजीव विहार व पक्षी विहार को संरक्षित कर रही है। इन विहारों में वन्यजीवों को प्राकृतवास मिल रहा है और उनका कुनबा बढ़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत विन्ध्य पर्वतमाला में स्थित लगभग 53000 हेक्टेयर का विशालकाय तथा रमणीय वन क्षेत्र, जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण 19 अक्टूबर 2022 को ''रानीपुर टाइगर रिजर्व'' के नाम से प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है। प्रदेश के जनपद गोरखपुर में कैम्पियरगंज रेंज के अन्तर्गत ''रेडहेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र'' बनाकर गिद्धों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ''वेटलैण्डस'' की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इन ''वेटलैण्ड रामसर साइट'' में पक्षी सहित विभिन्न जलीय जीव–जन्तु निवास करते हैं। प्रदेश में 10 वेटलैण्ड रामसर साइट घोषित हुए है, जो देश में सर्वाधिक हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा वन्यजीव सुरक्षा तथा संरक्षित क्षेत्रों के समुचित संरक्षण तथा तकनीकी नवाचार के प्रयोग से वन्यजीवों के संरक्षण को नई दिशा मिली है। ◆

मो. : 9453067441

ऊर्जा के बढ़ते कदम

—के.एल. चौधरी

वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में ''पावर फॉर आल'' के अन्तर्गत 1.58 करोड़ घरों को नये विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं और वर्ष 2022 से अगस्त 2023 तक 11.32 लाख नये विद्युत संयोजन अवमुक्त किये गये है। प्रदेश के 1,21,324 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 62.18 लाख घरों को विद्युत कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा। प्रदेश सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों के 1000 से अधिक आबादी वाले 19,031 गांवों और मजरों में लगे खुले तारों के स्थान पर केबिल तार लगाकर विद्युत सुरक्षा दी गई है। प्रदेश में बहुत से घरों में विद्युत मीटर नहीं लगे थे। ऐसे 8.60 लाख अनमीटर्स विद्युत उपभोक्ताओं के परिसरों में नये मीटर लगाकर विद्युत चोरी, अवैध विद्युत उपभोग पर लगाम लगायी गई है।

विद्युत आधुनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और अर्थव्यवस्था व प्रगति के लिए अति आवश्यक है। आज बिजली का उपयोग प्रकाश, हीटिंग, शीतलन, कम्प्यूटर संचालन, विभिन्न उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स, विभिन्न मशीनरी, औद्योगिक उपकरणों, वाणिज्यिक, सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों आदि के संचालन के लिए आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए ऊर्जा जरूरी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन सहित ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता 30,462 मेगावॉट हो गई है। इस विद्युत उत्पादन से प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। प्रदेश में 8609 करोड़ रुपये के निजी पूंजी निवेश से 1913 मेगावॉट क्षमता की परियोजनायें स्थापित की गई है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 33/11 के.वी. के 738 नये विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना की है। साथ ही 1482 विद्युत उपकेन्द्रो की क्षमता में वृद्धि की गई है। प्रदेश में 15,80,527 नग नये ट्रांसफार्मर्स की स्थापना की गई है।

वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में ''पावर फॉर आल'' के अन्तर्गत 1.58 करोड़ घरों को नये विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं और वर्ष 2022 से अगस्त 2023 तक 11.32 लाख नये विद्युत संयोजन अवमुक्त किये गये है। प्रदेश के 1,21,324 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 62.18 लाख घरों को विद्युत कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा। प्रदेश सरकार

ने दूरस्थ क्षेत्रों के 1000 से अधिक आबादी वाले 19,031 गांवों और मजरों में लगे खुले तारों के स्थान पर केबिल तार लगाकर विद्युत सुरक्षा दी गई है। प्रदेश में बहुत से घरों में विद्युत मीटर नहीं लगे थे। ऐसे 8.60 लाख अनमीटर्स विद्युत उपभोक्ताओं के परिसरों में नये मीटर लगाकर विद्युत चोरी, अवैध विद्युत उपभोग पर लगाम लगायी गई है।

उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में काफी विकास किया है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 332.92 लाख विद्युत उपभोक्ता है जिन्हें निर्वाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 21.30 घंटे और जनपद मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में कहीं भी ट्रांसफार्मर खराब हुए तो उन्हें 24 घंटे के अन्दर बदलने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता के हित को दृष्टिगत रखते हुए गत चार वर्षों से विद्युत दर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। प्रदेश सरकार ने निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर योजना लागू की है।

प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए निजी नलकूपों हेतु भरपूर विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सरकार ने किसानों के नलकूपों के लिए अलग फीडर की व्यवस्था की है। प्रदेश के 2710 ग्रामीण विद्युत फीडर किसानों के लिए अलग से लगाये गये है। सरकार ने निजी नलकूपों के कनेक्शन देने के लिए डार्क जोन में लगा प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया है, इससे एक लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिलों का शत–प्रतिशत छूट का निर्णय लिया है। इससे किसानों को काफी सहायता मिली है और किसान सरकार के इस निर्णय से बेहद खुश हैं। विद्युत संबंधी नये कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल झटपट/निवेश मित्र/निजी नलकूप की सुविधा देते हुए उपभोक्ताओं को अन्य झंझटों से मुक्ति दी गई है। ऑनलाइन सुविधा से सभी उपभोक्ताओं को समय से नये कनेक्शन मिल रहे हैं।

प्रदेश सरकार ने विद्युत आपूर्ति के विभिन्न कार्यों का गहन परीक्षण, निरीक्षण एवं समीक्षा में तेजी लाई है। विद्युत विभाग द्वारा लगातार सुधारात्मक कार्यवाही करने का ही परिणाम है कि वर्ष 2016–14 में जहाँ लाइन हानियाँ 21.47

प्रतिशत थी, वहीं वर्ष 2023 में अब तक लाइन हानियाँ 16.60 प्रतिशत रह गई है। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में ए.टी. एण्ड सी. हानियाँ 28.81 प्रतिशत थी जो वर्ष 2023 में अब तक घटकर 23.29 प्रतिशत हो गई है। विद्युत क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा किये गये कार्यों की जनता द्वारा सराहना की जा रही है।

सौर ऊर्जा कार्यक्रम से प्रदेश में बढ़ रहा है सौर विद्युत उत्पादन

आज विश्व के हर क्षेत्र में विकास करने के लिये विद्युत जरूरी है। बिना विद्युत के कोई भी यन्त्र, उपकरण, मशीनरी, इलेक्ट्रानिक उपकरण यातायात वाहन, घरेलू प्रकाश आदि नही चल पाते है। विद्युत उत्पादन, विद्युत शक्ति, जल से कोयले आदि की उष्मा से नाभिकीय अभिक्रियाओं से, पवन शक्ति से पेट्रोलियम/प्राकृतिक गैस आदि से होती है। किन्तु यह संसाधन धीरे–धीरे खत्म हो रहे है। इसलिये मानव को विद्युत आवश्यकताओं के लिये सौर ऊर्जा व अन्य विद्युत उत्पादन संसाधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। विश्व भौगोलिक क्षेत्र में सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्त्रोत है। सूर्य की ऊर्जा के कारण ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन होता है। धरती पर सभी प्रकार के जीवन, जीव–जन्तु, पेड़–पौधे आदि को सूर्य की ऊर्जा का ही सहारा है। इसी सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा वास्तव में अक्षय ऊर्जा स्त्रोत है जिसका उपयोग छोटे स्तर से लेकर बडे स्तर तक किया जा सकता है। सूर्य की उष्मा से प्राप्त सौर ऊर्जा उत्पादन में कोई प्रदूषण नही होता है। इससे संचालित उपकरणों का जीवन लम्बा होता है और रख–रखाब की कम आवश्यकता होती है। सौर ऊर्जा आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुये है। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति–2022 प्रख्यापित की गयी है। इस नीति में आगामी 05 वर्षों में 22000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। नीति के अन्तर्गत लक्षित क्षमता 6000 मेगावाट के सापेक्ष राज्य में निजी/सरकारी भवनो पर सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना करायी जा रही है। नीति में 14000 मेगावाट यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजनाओ/सोलर पावर पार्क की स्थापना की जायेगी तथा 2000 मेगावाट क्षमता पीएम कुसुम योजान्तर्गत निजी ऑनग्रिड पम्प का सोलराइजेशन एवं पृथक कृषि विद्युत फीडरों को सोलराइजेशन कराया जायेगा। इस क्षेत्र में कार्य तेजी से हो रहे है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022" घोषित की गई है, जिसमें कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमड अपशिष्ट इत्यादि जैसे विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग कम्प्रेस्ड बायो–गैस प्लांट, बायो–कोल (पैलेट्स और ब्रिकेट्स), बायो–डीजल/बायो–एथेनॉल की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। इसके के क्रम में कई निवेश प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे है।

प्रदेश में सोलर रूफटॉप पॉवर प्लाण्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत 290 मेगावॅाट क्षमता के संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सोलर स्ट्रीट लाईट कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 130574 संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण किया गया। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत दूरस्थ ग्रामों में 53354 सोलर पॉवर पैक संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण कराया गया। पीएम कुसुम कम्पोनेंट–ए योजनान्तर्गत 0.5 से 02 मेगावाट क्षमता हेतु आमंत्रित ईओआई के सापेक्ष आवंटित सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु 4.5 मेगावाट क्षमता के पीपीए हस्ताक्षरित हुये है। यूपीनेडा उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण की गतिविधियों को संचालित करने हेतु नामित संस्था भी है।

यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2023 में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कुल 496 एमओयू के सापेक्ष रु. 813731.81 करोड़ का निवेश संभावित है। परियोजनाओं की स्थापना कार्य प्रगति पर है। यूटिलिटी स्केल पावर प्रोजेक्ट्स कार्यक्रम के अंतर्गत 1913 मेगावॅाट क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ◆

मो. : 9453067441

किसानों की मददगार
डबल इंजन की सरकार
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 750 करोड़ रुपये का प्रावधान

बच्चों की मददगार
डबल इंजन की सरकार
स्पॉन्सरशिप योजना
₹4,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता
पात्रता
अभिभावक की आय सीमा
ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम ₹72,000 वार्षिक
शहरी क्षेत्रों में अधिकतम ₹96,000 वार्षिक
https://mahilakalyan.up.nic.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. स्वत्वाधिकारी के लिए शिशिर, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रकाशित तथा प्रकाश एन. भार्गव, प्रकाश पैकेजर्स, लखनऊ द्वारा मुद्रित